खबरें जो सोच बदल दे

शुभ लाभ

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

Postal Regd.No. HQ/SD/523/2023-25 | शनिवार, 26 जुलाई, 2025 | हैदराबाद और नई दिल्ली से प्रकाशित | website : https://www.shubhlabhdaily.com | संपादक : गोपाल अग्रवाल | पृष्ठ : 14 | मूल्य-8 रु. | वर्ष-7 | अंक-205

बांग्लादेश में सरकारी आदेश के जरिए शरिया कानून का ट्रायल

सरकारी दफ्तर में इस्लामी ड्रेस-कोड लागू

सूफी यायावर

बांग्लादेश में लोकतंत्र अब आखिरी सांसें ले रहा है। देश में आम चुनाव कराने की बात तो दूर है, अब वहां शरिया शासन लागू करने की शुरुआत हो चुकी है। सरकारी संस्थाओं में शरिया कानून के तहत ड्रेस-कोड लागू किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा सरकारी आदेश जारी किए जा रहे हैं। अब सरकार ने अध्यादेश जारी कर यह ताकीद की है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की किसी ने भी आलोचना की तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, साथ ही उसे सख्त कानूनी कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ेगा।

यूनुस की आलोचना करने वाले कर्मचारी बर्खास्त किए जाएंगे

चोरमोनाई के प्रभावशाली पीर और अति-इस्लामी समूह इस्लामी शाशनतोंत्रो आंदोलन (इस्लामी शासन की स्थापना का आंदोलन) के प्रमुख मुफ्ती सैयद मोहम्मद रजाउल करीम उर्फ मुफ्ती फौजुल करीम की बांग्लादेश में शरिया-आधारित तालिबान शैली के शासन की मांग के बहाने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शरिया शासन के तौर-तरीके अख्तियार करने शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी एजेंडे के संस्थागत कार्यान्वयन के कई उदाहरण सामने आ रहे रहे हैं। मुफ्ती की चौंकाने वाली मांग और उस पर बांग्लादेश सरकार के अंधानुकरण की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा होनी चाहिए थी, लेकिन निंदा के बजाय चुप्पी साध कर मोहम्मद यूनुस को बढ़ावा दिया जा रहा है। तथाकथित प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और बुद्धिजीवी जमातें भी शातिराना चुप्पी साधे बैठी हैं।

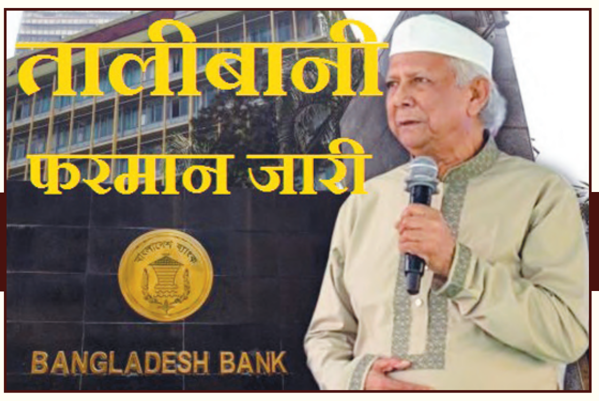

दो विवादास्पद आदेशों पर प्रगतिशील साधे हैं शातिराना चुप्पी

21 जुलाई को बांग्लादेश की शीर्ष संस्था केंद्रीय वित्तीय प्राधिकरण, बांग्लादेश बैंक के मानव संसाधन विभाग ने अपने कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं के लिए विशिष्ट इस्लामी ड्रेस कोड अनिवार्य करते हुए औपचारिक निर्देश जारी किया है। नए नियमों के अनुसार महिला कर्मचारियों को साड़ी या सलवार-कमीज पहनना होगा, अपने सिर को स्कार्फ या हिजाब से ढंकना होगा और छोटी बाजू या कम लंबाई के कपड़े, लेगिंग या किसी भी प्रकार के पश्चिमी ▶10 पर

मालदीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत

हमारे लिए दोस्ती हमेशा पहले आती है: मोदी

माले, 25 जुलाई (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव की राजधानी माले पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू खुद मौजूद थे, उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुइज्जू को गले लगा कर उनका स्वागत स्वीकार किया। हवाई अड्डे पर मालदीव के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ ही आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी पीएम मोदी की अगवानी के लिए मौजूद थे। मालदीव के रिपब्लिक स्क्वायर पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान भारत और मालदीव के राष्ट्रगान की धुनों के बीच पीएम मोदी का स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

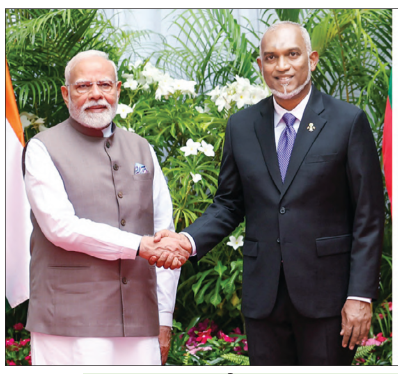

- मालदीव और भारत की मजबूत दोस्ती पर लगाई मुहर
- मालदीव को भारत देगा 4,850 करोड़ की ऋण सहायता
- हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए खुद मौजूद थे मुइज्जू
- दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए

मालदीव की राजधानी में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे लिए दोस्ती हमेशा पहले आती है। सबसे पहले मैं भारत की जनता की ओर से मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति मुइज्जू और यहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंधों की जड़ें समुद्र जितनी गहरी हैं। आज जारी किए गए स्मारक डाक टिकटों में दोनों देशों की ▶10 पर

जेबी संविधान वाले बिहार चुनाव के पहले फैलाने लगे जहर

संविधान से 'दो' शब्द हटाने की तैयारी का शिगूफा

नई दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसियां)। बिहार चुनाव के पहले राजनीति के गलियारे में फिर से उस चर्चा को हवा दी जा रही है कि क्या भारत सरकार संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने जा रही है। जेब में संविधान लेकर चलने वाले नेता राहुल गांधी और उसकी पिछलग्गू जमात की तरफ से यह चर्चा ऐन बिहार चुनाव के पहले वायरल की जा रही है ताकि इसका असर चुनाव पर पड़े और विपक्ष को उसका कुछ फायदा मिल जाए। पिछले चुनाव के समय आरक्षण वाला मुद्दा चमकाया गया था और उसका लाभ हासिल किया गया था। जबकि देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ-साफ कह दिया है कि भारत सरकार की ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई इरादा नहीं है। कानून मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि कुछ लोग संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर ऐसा कोई विचार नहीं है।

राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कानून मंत्री से इस बारे में पूछा था। रामजी लाल सुमन के इस सवाल को जिज्ञासा या जानकारी चाहने वाला सवाल नहीं समझना चाहिए।

रामजी लाल सुमन

कानून मंत्री ने कहा, यह सरकार के विचार में ही नहीं

यह सवाल जानबूझ कर सदन में रखा गया ताकि इस पर तूल मचे और फिर यह मुद्दा संसद से सड़क तक जाए और संविधान का बोनसाई एडिशन पॉकेट से निकल कर ईवीएम तक नाचना शुरू कर दे। लेकिन इस सवाल को निर्मूल साबित करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, भारत सरकार ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को ▶10 पर

प्राचीन शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध

लगातार बढ़ रहा दोनों देशों का संघर्ष, अब तक 14 की मौत

बैंकॉक, 25 जुलाई (एजेंसियां)। 11वीं सदी के प्रीह विहार शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और शुक्रवार को भी दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी हुई। इस संघर्ष में अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। संघर्ष के चलते एक लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दोनों तरफ से हमले के लिए गोलीबारी, आर्टिलरी और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

शुक्रवार को दोनों ही देशों की सेनाओं ने सीमा पर सैनिकों के अतिरिक्त रेजीमेंट्स भेजे हैं। गुरुवार को कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड के सीमा पर स्थित गांवों पर हमला किया गया। इसके जवाब में थाईलैंड की सेना ने एफ-16 फाइटर जेट से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। हमलों के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों से आम लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। साल 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस साम्राज्य के अंतर्गत आता था, तब सियाम और कंबोडिया के बीच सीमाएं तय की गई थीं। हालांकि, आगे चलकर 817 किमी लंबी इस सीमा को लेकर विवाद शुरू हो गया। खासकर कुछ ऐतिहासिक मंदिरों, खासकर 11वीं सदी के प्रीह विहार मंदिर को लेकर दोनों देशों में यह विवाद खासा गहरा गया।

▶10 पर

संसद के दोनों सदनों में होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा

शत्रु की शैतानी और सेना की जांबाजी सुनेगा देश

नई दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसियां)। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में होगी। सोमवार 28 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में भाग लेने वाले अन्य मंत्रियों में गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे भी इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा में भी 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। इसमें राजनाथ सिंह, जयशंकर और अन्य मंत्री भाग लेंगे। उच्च सदन में भी प्रधानमंत्री मोदी के चर्चा में हिस्सा लेने की उम्मीद है। दोनों सदनों में इस विषय पर 16 घंटे की चर्चा होगी।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में फंसे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जाएगा। न्यायपालिका में

संसद में आएगा भ्रष्ट जज को हटाने का प्रस्ताव

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी दलों ने एकजुट होकर आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मानसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मांग की थी कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष पहले दिन से ही संसद में हंगामा कर रहा है। संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सदन को चलने नहीं दे रहा है। संसद के मानसून सत्र के पहले हफ्ते में हम केवल एक विधेयक पारित कर पाए हैं। मैं सभी विपक्षी दलों से संसद की कार्यवाही बाधित न करने का आग्रह करता हूं।

रिजिजू ने कहा, आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक बुलाई और यह दोहराया गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आज यह निर्णय लिया गया है कि सोमवार 28 जुलाई को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मुद्दों पर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती। विपक्ष ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण ▶10 पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड

सबसे लंबा खेलने वाले दूसरे पीएम बने मोदी

नई दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसियां)। नरेंद्र मोदी आज इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बन गए। पीएम मोदी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4,078 दिन पूरे किए। इंदिरा गांधी 24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977 तक 4,077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रही थीं। प्रधानमंत्री के 26 मई 2014 से शुरू होकर 17 जून 2029 तक चलने वाले कार्यकाल को देखा जाए तो कुल

5,501 दिन होते हैं। उसमें से प्रधानमंत्री ने 4,078 दिन पूरे किए, यानि इस कार्यकाल के मुताबिक 1423 दिन बाकी हैं। नरेंद्र मोदी 25 जुलाई यानी आज लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अभी तक लगातार सबसे लंबे समय तक (16 वर्ष 286 दिन) प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड जवाहर लाल नेहरू के पास है। नरेंद्र मोदी 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए गैर-हिंदी राज्य के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन तक प्रधानमंत्री रही थीं। अगर राज्य और केंद्र में सरकार का नेतृत्व करने की बात करें तो नरेंद्र मोदी का सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक रिकॉर्ड है। वह गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं।

नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ। वह सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। वह पहले और एकमात्र गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कम से कम अपना ▶10 पर

6 साल में 16 करोड़ को मिला रोजगार

संसद में रखी गई पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट

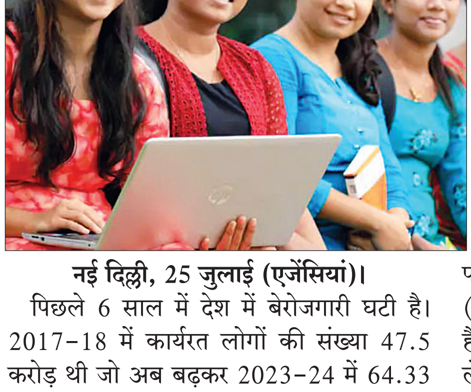

नई दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसियां)। पिछले 6 साल में देश में बेरोजगारी घटी है। 2017-18 में कार्यरत लोगों की संख्या 47.5 करोड़ थी जो अब बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में भारतीय रिजर्व बैंक के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के आधार पर यह दावा किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि का भी जिक्र किया। पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए वर्कर पापुलेशन रेशियो 2019-20 में 28.7 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 40.3 प्रतिशत हो गया। मंत्रालय ने पीएलएफएस के बारे में कहा कि यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में लेबर फोर्स भागीदारी रेट 49.8 प्रतिशत (2017-18) से बढ़कर 60.1 प्रतिशत ▶10 पर

गाजा संघर्ष के बीच राष्ट्रपति मैक्रो की बड़ी घोषणा फिलिस्तीन को फ्रांस स्वतंत्र देश की मान्यता देगा

पेरिस, 25 जुलाई (एजेंसियां)।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि उनका देश फिलिस्तीन को इसी साल सितंबर में आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा।उन्होंने कहा कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वे इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 140 से ज्यादा देशों की ओर से मान्यता प्राप्त है।

गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस समय सबसे जरूरी है कि गाजा में जारी युद्ध तत्काल खत्म हो और नागरिकों की जान बचाई जा सके।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रति ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के तहत मैंने फैसला लिया है कि फ्रांस, फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। हमें हमास को हथियार मुक्त कर गाजा को सुरक्षित बनाना और उसका पुनर्निर्माण करना होगा।

उन्होंने लिखा है कि तत्काल युद्धविराम, सभी बंधकों की रिहाई और गाजा में व्यापक स्तर पर मानवीय मदद की जरूरत है।

खास बात यह है कि मैक्रो इससे पहले इजराइल के रुख के समर्थक थे। 7 अक्तूबर 2023 को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, तब राष्ट्रपति मैक्रों ने इजराइल का समर्थन किया।

हालांकि हाल के महीनों में गाजा में इजराइल की व्यापक सैन्य कार्रवाई में आम लोगों के निशाना बनने और वहां खाद्यान्न संकट को लेकर मैक्रों चिंतित हैं।

एक दिन पहले भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में गाजा संकट पर बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि गाजा पट्टी में व्याप्त भीषण मानवीय संकट का समाधान केवल संघर्ष विराम में अस्थायी विराम से नहीं किया जा सकता। गाजा में लोग रोजाना भोजन, ईंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों की भारी कमी से जूझ रहे हैं।

न्यूज ब्रीफ

सीबीएस न्यूज पर होगा स्काईडांस का नियंत्रण, पैरामाउंट का होगा विलय

वाशिंगटन। अमेरिका के प्रमुख इलेक्ट्रानिक मीडिया सीबीएस न्यूज पर बहुत जल्द हॉलीवुड स्टूडियो स्काईडांस का नियंत्रण होगा। अमेरिकी संघीय संचार आयोग (एफसीसी) ने स्काईडांस को सीबीएस न्यूज का संचालन करने वाली कंपनी पैरामाउंट के साथ विलय को मंजूरी प्रदान कर दी। एफसीसी के अध्यक्ष ब्रेंडन कैर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि स्काईडांस से यह आश्वासन मिलने के बाद इस सौदे को मंजूरी दी गयी है कि नई कंपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध होगी। अध्यक्ष कैर ने बयान में कहा, अमेरिकी अब पारंपरिक राष्ट्रीय समाचार मीडिया पर पूरी तरह, सटीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने का भरोसा नहीं करते। अब बदलाव का समय आ गया है। इसलिए मैं कभी चर्चित रहे सीबीएस प्रसारण नेटवर्क में महत्वपूर्ण बदलाव करने की स्काईडांस की प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूं। बताया गया है कि यह 8 अरब डॉलर का सौदा है। यह पैरामाउंट के लिए नई शुरुआत का संकेत है। पैरामाउंट पर दशकों से रेडस्टोन परिवार का नियंत्रण रहा है। टेक अरबपति लैरी एलिसन के बेटे डेविड एलिसन की योजना सौदा पूरा होने पर पैरामाउंट कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की है। हाल के हफ्तों में पैरामाउंट कंपनी ट्रंप प्रशासन के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के कारण उथल-पुथल में घिरी रही है। कंपनी ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुकदमे का निपटारा करने के लिए इसी महीने 1.6 करोड़ डॉलर का भुगतान किया। सीबीएस के लेट नाइट होस्ट स्टीफन कोलबर्ट ने कहा कि यह समझौता असल में ट्रंप प्रशासन से सौदे की मंजूरी पाने के लिए एक रिश्वत थी। एफसीसी की डेमोक्रेटिक कमिश्नर एना एम. गोमेज ने इस मंजूरी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एफसीसी ने पैरामाउंट पर एक निजी कानूनी समझौता कराने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर आंच पहुंची है। चिंताजनक बात यह है कि अब एफसीसी न्यूजरूम के फैसलों और संपादकीय निर्णयों पर अभूतपूर्व नियंत्रण लागू कर रही है। फिलहाल पैरामाउंट और स्काईडांस के प्रवक्ता ने इस मंजूरी पर कोई टिप्पणी नहीं की।

वीजा-फ्री एंट्री पर करार: पाकिस्तान और बांग्लादेश में आने जाने के लिए वीजा की जरुरत नहीं होगी

ढाका। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक बिना किसी वीसा के एक दूसरे के देश में आवाजाही कर सकते हैं। दोनों देशों ने राजनयिक व आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-फ्री एंट्री पर सहमति जताई है। इसे लेकर भारत अलर्ट हो गया है। यह फैसला ढाका में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी की बैठक में लिया गया। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के अनुसार, दोनों देश राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा जरूरतों को हटाने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय के बयान में कहा गया, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश पर प्रगति हुई है। दोनों देशों ने इस मामले पर अपनी सहमति दी है। हालांकि, वीजा-फ्री व्यवस्था शुरू होने की कोई तारीख नहीं दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि बैठक में आतंकवाद विरोधी उपायों, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस ट्रेनिंग, नशीली दवाओं पर नियंत्रण और मानव तस्करी से निपटने के प्रयासों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन नई योजनाओं को लागू करने के लिए संयुक्त समिति बनाई जाएगी। इस्लामाबाद से इस टीम का नेतृत्व पाकिस्तान के गृह सचिव खुर्रम अघा करेंगे। दोनों देशों ने पुलिस अकादमियों के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू करने पर भी सहमति जताई।

दक्षिण प्रशांत महासागर में समोआ के पास 6.6 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की कोई चेतावनी नहीं

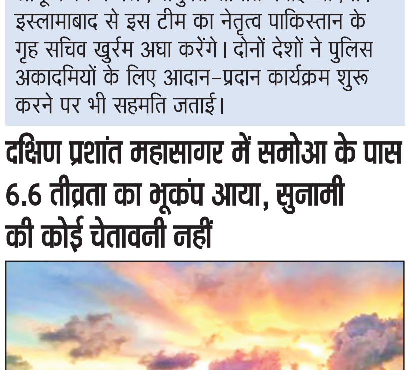

अपिया। दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित समोआ द्वीप के पास शुक्रवार को 6.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, यह भूकंप समोआ की राजधानी अपिया से करीब 440 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में दर्ज किया गया। भूकंप की गहराई 314 किलोमीटर मापी गई, जो इसे गहरे भूकंपों की श्रेणी में रखता है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। समोआ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर लोगों ने झटके महसूस नहीं किए और न ही किसी तरह की क्षति की जानकारी अभी तक मिली है। सुनामी का कोई खतरा नहीं यूएस सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भूकंप के बाद किसी भी प्रकार की सुनामी चेतावनी जारी नहीं की है।

पाकिस्तान-बांग्लादेश वीज़ा-फ्री समझौते से भारत की बढ़ी चिंता, ढाका में बढ़ती दोस्ती पर दिल्ली की पैनी नजर

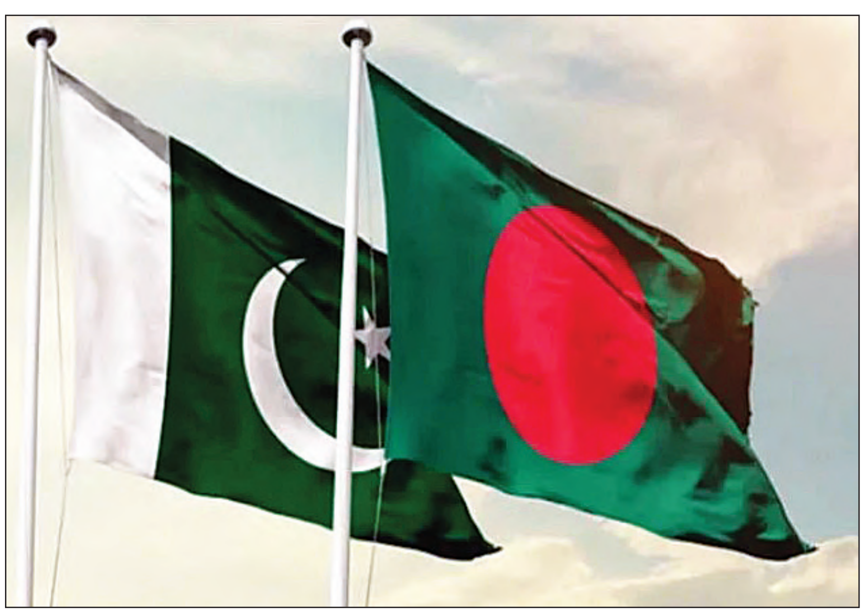

इस्लामाबाद, 25 जुलाई (एजेंसियां)।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच राजनयिक व आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश पर सहमति ने भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस फैसले के बाद नई दिल्ली अलर्ट मोड पर है और क्षेत्र में बदलते समीकरणों पर पैनी नजर बनाए हुए है। यह महत्वपूर्ण निर्णय ढाका में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी के बीच हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया।

पाकिस्तानी गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, दोनों देश राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा की अनिवार्यता को समाप्त करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। बयान में कहा गया, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों देशों ने इस मामले पर अपनी सहमति दे दी है। हालांकि, इस वीज़ा-मुक्त व्यवस्था के लागू होने की कोई निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

रिपोर्टों के अनुसार, दोनों गृहमंत्रियों की बैठक में सिर्फ वीज़ा ही नहीं, बल्कि आतंकवाद विरोधी उपायों, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशिक्षण, नशीली दवाओं पर नियंत्रण और मानव तस्करी से निपटने जैसे गंभीर मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व पाकिस्तानी पक्ष से वहां के गृह सचिव खुर्रम अघा करेंगे।

इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने पुलिस अकादमियों के बीच आदान-प्रदान कार्यक्रमों को शुरू करने पर भी रजामंदी जताई है। इसी कड़ी में, बांग्लादेश का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का दौरा करेगा। इस मौके पर बांग्लादेश के गृह मंत्री ने पाकिस्तानी गृह मंत्री का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया और उनके दौरे को भविष्य के सहयोग के लिए एक अहम मील का पत्थर बताया।

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती यह नजदीकी भारत के लिए चिंता का विषय है। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों को आशंका है कि इस वीज़ा-मुक्त सुविधा का दुरुपयोग पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों द्वारा अपनी आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किया जा सकता है।

नई दिल्ली की यह चिंता इसलिए भी अधिक गंभीर है, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बनी नई अंतरिम सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ संबंधों में अप्रत्याशित रूप से तेज़ी आई है। शेख हसीना के शासनकाल में, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एक निश्चित दूरी बनाए रखी थी और पाकिस्तानी राजनयिकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी।

अब, वीज़ा नियमों में ढील और द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि को भारत क्षेत्रीय अस्थिरता के संभावित कारक के रूप में देख रहा है। अधिकारियों को डर है कि इससे उन समूहों को बढ़ावा मिल सकता है जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और जिन्हें पहले पाकिस्तान का समर्थन मिलता रहा है। इस नए घटनाक्रम से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होती दिख रही है, जिस पर भारत की सामरिक नज़र बनी हुई है।

बांग्लादेश में भ्रष्टाचार की नींव पर तैयार पुल प्रशासन ने ढहाया

ढाका, 25 जुलाई (एजेंसियां)।
दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश के बारिसल डिवीजन के पिरोजपुर जिला में एक पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग होने पर ढहा दिया गया। मदरा बाजार रोड पर ठेकेदार के माध्यम से इस पुल को तैयार कराया गया था। ठेकेदार को इसके लिए 5.73 करोड़ टका का भुगतान किया गया। ठेकेदार ने यह काम किसी दूसरे को सौंप दिया था।

खबर के अनुसार, स्थानीय निकाय अभियांत्रिकी विभाग (एलजीईडी) से लोगों ने शिकायत की थी कि जलाबाड़ी यूनियन के मदरा बाजार रोड पर स्थित यह पुल कभी भी गिर सकता है। इसके निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। विभाग को जांच में बड़ी खामियां मिलीं। इसके बाद पुल को गिरा दिया गया।

इस घटना के बाद बांग्लादेश में सरकारी निर्माण परियोजनाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी और जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। स्थानीय नागरिकों के गुस्से को देखते हुए एलजीईडी को इस संरचना को गिराने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पुल का ठेका 29 दिसंबर, 2021 को पिरोजपुर एलजीईडी ने एक ठेकेदार फर्म को दिया था। इसका अनुबंध मूल्य 5.73 करोड़ टका था। अनुबंध के अनुसार, इसका निर्माण 28 दिसंबर, 2022 तक पूरा होना था। मुख्य ठेकेदार ने यह काम दूसरे ठेकेदार को सौंप दिया। उसने निर्माण मानकों का पालन नहीं किया और परियोजना समय-सीमा का उल्लंघन भी किया।

दूसरे ठेकेदार खोकोन मिया ने दावा किया कि कंक्रीट के काम के बाद किसी ने बिना अनुमति के सेंटरिंग हटा दी, जिसके कारण यह नौबत आई।

उप जिला इंजीनियर मोहम्मद रायसुल इस्लाम ने कहा कि पूरे स्लैब को तोड़कर नए सिरे से पुनर्निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य ठेकेदार की अनुपस्थिति के कारण परियोजना को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है।

अवैध रूप से कुवैत जा रही 47 नेपाली महिलाओं को दिल्ली हवाईअड्डे से लौटाया गया

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 47 नेपाली महिलाओं के एक समूह को उस समय रोक दिया गया, जब वो बिना उचित अनुमति के यात्रा वीजा पर कुवैत की यात्रा करने का प्रयास कर रही थीं। इन महिलाओं के पास विदेश में नौकरी के लिए नेपाली दूतावास के नाम का फर्जी अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिला, जिसके बाद उन्हें नई दिल्ली में नेपाली दूतावास के समन्वय से हिरासत में ले लिया गया। नेपाली दूतावास के उपनियोग प्रमुख डॉ. सुरेन्द्र थापा ने बताया कि सामान्य पूछताछ के बाद इन सभी महिलाओं को सड़क मार्ग से वापस नेपाल भेज दिया गया। रुपन्देही के प्रमुख जिला अधिकारी बासुदेव घिमिरे के अनुसार महिलाओं को नेपाली दूतावास से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रकाश मल्ल के नेतृत्व में गई एक टीम ने नेपाली दूतावास के अन्य कर्मचारियों के साथ सुनौली सीमा से रुपन्देही ले जाया गया। पुलिस के अनुसार आगे की जांच के लिए इन महिलाओं को काठमांडू ले जाया जा रहा है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने पुलिस को मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मानव तस्करी रोधी ब्यूरो को घटना की जांच करने और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में लाने का निर्देश दिया है।

ओली सरकार को झटका, राष्ट्रपति का संवैधानिक परिषद विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार

काठमांडू, 25 जुलाई (एजेंसियां)।
प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संवैधानिक परिषद (कर्तव्य, कार्य, अधिकार और प्रक्रिया) अधिनियम, 2006 से संबंधित संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए प्रतिनिधि सभा को वापस कर दिया है।

राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल के अनुसार, विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए गुरुवार को वापस भेज दिया गया था। पोखरेल ने कहा कि राष्ट्रपति ने विधेयक को मूल सदन को यह कहते हुए वापस कर दिया कि प्रस्तावित संशोधन संविधान की भावना और सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मानदंडों और मूल्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रथाओं के विपरीत है। राष्ट्रपति की तरफ से यह कदम संविधान के अनुच्छेद 113 (3) के तहत उठाया गया है।

प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक 15 जुलाई को प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचा था।एक सप्ताह की लंबी समीक्षा के बाद, राष्ट्रपति पौडेल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं करने का विकल्प चुना और इसे संसद के निचले सदन को वापस कर दिया।

नेपाल के संविधान की अनुच्छेद 113 राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक (धन बिलों को छोड़कर) को यदि वह इसे पुनर्विचार के लिए आवश्यक समझते है तो 15 दिनों के भीतर मूल सदन को वापस भेजने की अनुमति देता है।प्रधानमंत्री की पहल पर सदन से पारित हुए इस विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस का एक बड़ा खेमा इसके विपक्ष में दिखा। नेपाली कांग्रेस ने चिंता व्यक्त की थी कि निचले सदन द्वारा पारित संशोधन में नेशनल असेंबली का संशोधन लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और इसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। नेपाल के संविधान में छह सदस्यीय संवैधानिक परिषद की परिकल्पना की गई है जिसमें प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि सभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश और प्रमुख प्रतिपक्षी दल का नेता शामिल है। प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। लौटाए गए विधेयक में एक प्रावधान शामिल था जिसमें कहा गया था कि संवैधानिक निकायों में नियुक्तियां परिषद के भीतर सर्वसम्मति के माध्यम से की जानी चाहिए। यदि सर्वसम्मति नहीं बन पाती है, तो निर्णय बहुमत से लिए जा सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में) और वर्तमान में सेवारत सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत शामिल है। इसमें संशोधन करते हुए सभी राजनैतिक और संवैधानिक नियुक्ति करते समय सिर्फ प्रधानमंत्री और कोई भी एक सदस्य चाहे तो इस परिषद के तरफ से कोई फैसला ले सकते हैं। गठबंधन बचाने के लिए तो दोनों सदनों से इसे पारित कर दिया गया लेकिन ओली की नीयत को देखते हुए कांग्रेसी सांसदों और नेताओं ने ही राष्ट्रपति पर दबाव बनाकर उसे अस्वीकृत करवाया है। इस समय संवैधानिक परिषद में प्रधानमंत्री ओली अल्पमत में हैं। उनके अलावा सिर्फ प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही उनके पक्ष में है, बाकी डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दल के नेता सभी उनके विरोधी ही हैं।

अमेरिकी कालेज गेम्स में लागू होंगे संघीय नियम, राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

वाशिंगटन, 25 जुलाई (एजेंसियां)।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अमेरिका के सभी कालेजों के गेम्स (खेलों) में नाम, छवि और समानता से संबंधित संघीय नियम लागू करना है। राष्ट्रपति ने यह कदम इस चिंता के बाद उठाया कि अनियंत्रित खर्च और राज्यों के नाम, छवि और समानता कानूनों ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बाधित किया है।

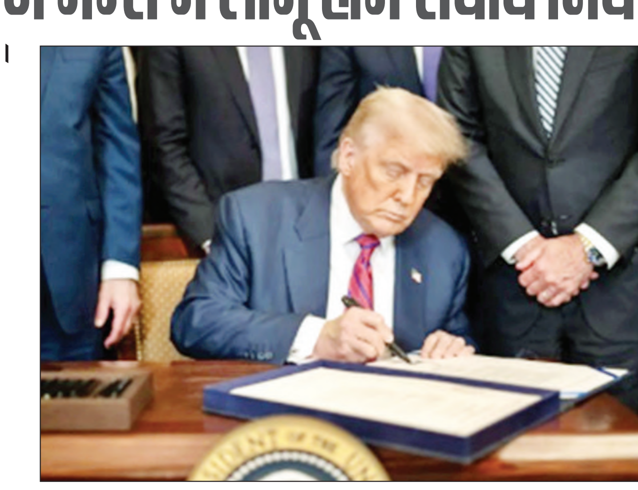

व्हाइट हाउस ने यह ब्यौरा उपलब्ध कराया है। व्हाइट हाउस के विवरण में कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह कार्यकारी आदेश छात्रवृत्ति, महिला और गैर-राजस्व खेलों की रक्षा करेगा। यह आदेश कालेज एथलीटों को तीसरे पक्ष के भुगतान पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है, जबकि ब्रांडिंग के लिए विज्ञापनों की अनुमति देता है।

राष्ट्रपति का मानना है कि एथलीटों की भर्ती के लिए प्रोत्साहन भुगतान प्रतिस्पर्धा के संतुलन के लिए खतरा पैदा करते हैं। इससे छोटे खेलों के सामने संकट खड़ा हो जाता है। इस आदेश के अनुसार, 2024-25 सीजन के दौरान 125 मिलियन डॉलर या उससे अधिक राजस्व वाले एथलेटिक विभागों को महिलाओं और गैर-राजस्व खेलों में छात्रवृत्ति और रोस्टर स्थानों का विस्तार करना होगा। 50 मिलियन डॉलर से 125 मिलियन डॉलर के बीच आय वाले विभागों को यथास्थिति बनाए रखनी होगी। 50 मिलियन डॉलर से कम आय वाले विभागों को गैर-राजस्व खेलों के अवसरों में कटौती नहीं करनी होगी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कालेज खेलों का देश में विशिष्ट स्थान है। यह खिलाड़ी स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही कई समुदायों में पारिवारिक गतिविधियों, मनोरंजन और संस्कृति का अमिट हिस्सा बनते हैं। इन खिलाड़ियों को भी फुटबॉल खिलाड़ियों जैसा मान-सम्मान और लाभ मिलना चाहिए। 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओलंपिक टीम ने कुल 126 पदक अर्जित किए। टीम लगातार आठवें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की समग्र पदक गणना में अग्रणी रही।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेजोड़ सफलता के अलावा, कॉलेज के एथलीट स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देने की अधिक संभावना रखते हैं। सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों में महिला अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा किशोरावस्था के दौरान खेलों में शामिल रहा है। इस मामले में कालेज खेलों में हिस्सा लेने वालों में कई उद्योगपतियों और पूर्व राष्ट्रपतियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि अमेरिका की कॉलेजिएट एथलेटिक्स प्रणाली हमारे राष्ट्र की सफलता के प्रेरक नेताओं को तैयार करने में एक अभिन्न भूमिका निभाती है।

ट्रंप ने कहा कि कालेज गेम्स के नियमों के खिलाफ हालिया मुकदमों की वजह से इस तरह के कार्यकारी आदेश की जरूरत महसूस की गई। यह कार्यकारी आदेश कालेज गेम्स को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। प्रशासन सभी कालेज खेलों को संरक्षण प्रदान करेगा। 2025-2026 एथलेटिक सीजन में इसका प्रभाव देखा जा सकेगा।

वोमेन इकोनॉमिक इम्पावरमेंट (वी) की रिपोर्ट

यूपी में बढ़ी महिला श्रम की भागीदारी

लखनऊ, 25 जुलाई (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश में महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। हाल ही में जारी वोमेन इकोनॉमिक इम्पावरमेंट (वी) की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में महिला श्रम भागीदारी दर 2017-18 के 14 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 36 प्रतिशत तक पहुंच गई है, यानी महिलाओं की भागीदारी दर में 22 अंकों की वृद्धि। यह परिवर्तन न केवल आंकड़ों में, बल्कि सामाजिक ढांचे और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर इशारा करता है। यह वृद्धि योगी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर किए गए कार्यों का परिणाम है।

महिला आर्थिक सशक्तीकरण सूचकांक केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस परिवर्तनशील सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य का आईना है जिसमें उत्तर प्रदेश की महिलाएं अब पीछे नहीं, बल्कि आगे खड़ी हैं। यह सिर्फ आधी आबादी की बात नहीं है, यह उस नई शक्ति की बात है जो अब राज्य की अर्थव्यवस्था, समाज और भविष्य को नया आकार देने में जुटी है। योगी सरकार की योजनाएं और नीतियां अब महिला सशक्तिकरण के एक सशक्त मॉडल के रूप में उभर रही हैं, जिसे अन्य राज्य भी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। 2017-18 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब महिला श्रमशक्ति की भागीदारी राष्ट्रीय औसत से भी काफी नीचे थी। लेकिन बीते सात वर्षों में राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्पादक कार्य वातावरण देने की दिशा में निरंतर पहल की। महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति से लेकर सरकारी नौकरियों में महिलाओं की विशेष भागीदारी, रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति से लेकर औद्योगिक इकाइयों में अवसरों की वृद्धि तक, सभी नीतिगत निर्णयों में महिलाओं को केंद्र में रखा गया।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में जहां भारत की महिला श्रम भागीदारी दर 45 प्रतिशत है, वहीं उत्तर प्रदेश की दर 36 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा भले ही देश की तुलना में थोड़ा कम हो, लेकिन 2017-18 में यूपी की भागीदारी दर मात्र 14 प्रतिशत थी, जो भारत के 25 प्रतिशत के औसत से काफी नीचे थी। इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने इन सात वर्षों में एक लंबी छलांग लगाई है और इस अंतर को पाटने में राज्य ने अनुकरणीय प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू कीं, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने महिला स्वावलंबन को जमीनी हकीकत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयासों की दिशा में योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। महिलाओं को खतरनाक श्रेणी के 29 प्रकार के कारखानों में काम करने की अनुमति देना एक बड़ा कदम है। इससे पहले देशभर में इन 29 श्रेणियों में महिलाओं को काम करने पर प्रतिबंध था। शुरुआत में केवल 12 श्रेणियों में शर्तों के साथ छूट दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 16 किया गया। लेकिन योगी सरकार ने इस बंदिश को पूरी तरह खत्म करते हुए सभी 29 श्रेणियों में महिलाओं को नियोजित किए जाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति कुछ विशेष शर्तों और सुरक्षा मानकों के अधीन दी गई है। यानी महिला श्रमिकों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा। कारखानों को निर्धारित सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके अलावा, योगी सरकार ने रात्रिकालीन पाली में महिलाओं को कार्य की अनुमति देकर एक और साहसिक पहल की है। इसके लिए नियोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा, परिवहन, भोजन और विश्राम की सुविधाएं देने की शर्तें निर्धारित की गई हैं, ताकि महिलाएं भयमुक्त होकर रात की शिफ्ट में भी काम कर सकें।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग के आकड़ों पर नजर डालें तो कारखानों में पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण में महिलाओं की 53 प्रतिशत भागीदारी, निर्माण क्षेत्र में 34.65 प्रतिशत महिला श्रमिक ये सभी संकेत देते हैं कि राज्य में महिलाओं की भागीदारी अब केवल नीति तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि वास्तविक परिवर्तन के रूप में उभर रही है। इससे महिला श्रमिकों को 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ने का कार्य भी किया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर महिलाएं स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर बढ़ रही हैं।

योगी सरकार महिलाओं को उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का सहभागी बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में महिलाओं की निर्णायक भूमिका तय की है

इंदिरम्मा हाउसिंग योजना में तेजी से प्रगति

1.74 लाख घरों का निर्माण शुरू 5,000 घर पूर्ण होने के करीब

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। तेलंगाना में इंदिरम्मा हाउसिंग योजना तेजी से प्रगति कर रही है, और निर्माण कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहा है।

हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक वी. पी. गौतम ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि अब तक लगभग 1.74 लाख घरों का निर्माण शुरू हो चुका है, जिनमें से 57,000 घरों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 5,000 घर पूर्ण होने के करीब हैं और जल्द ही रहने के लिए तैयार होंगे।

उन्होंने बताया कि मंजूर किए गए घरों को केवल दो महीने पहले स्वीकृति दी गई थी, और कार्य प्रभावशाली गति से आगे बढ़ रहा है। योजना के मौजूदा चरण में सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि सबसे कमजोर वर्ग को पहले आवास सहायता मिले।

सरकार ने निर्माण दिशानिर्देशों का पालन करने वाले लाभार्थियों के लिए 386.12 करोड़ रुपये जारी किए हैं, और हर सोमवार को धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। हाल की एक किस्त में ही लगभग 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

गौतम ने बताया कि चल रहे निर्माण कार्यों में 57,000 घर उन्नत चरण में हैं। कई मामलों में दीवारें तैयार हो चुकी हैं और स्लैब डालने के लिए तैयार हैं, जबकि लगभग 8,000 घर स्लैब चरण तक पहुंच चुके हैं। करीब 5,000 घर पूर्ण होने के करीब हैं, और बड़े पैमाने पर गृहप्रवेश समारोह की योजना बनाई जा रही है। निष्पक्षता और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, हाउसिंग कॉरपोरेशन ने तकनीक का उपयोग कर 360-डिग्री समीक्षा की। इस प्रक्रिया में लगभग 20,000 चयनित लाभार्थियों के विवरण में विसंगतियां पाई गईं। संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण के माध्यम से इनकी दोबारा जांच की गई। नतीजतन, 18,000 लाभार्थी पात्र पाए गए, जबकि लगभग 1,900 लाभार्थी अपात्र पाए गए, क्योंकि उनके पास पहले से ही आरसीसी स्लैब वाले घर थे, वे सरकारी कर्मचारी थे, या उन्हें अन्य आवास योजनाओं के तहत घर मिल चुके थे।

गौतम ने स्पष्ट किया कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रही खबरें, जिनमें दावा किया गया कि 20,000 लाभार्थियों के घर रद्द कर दिए गए, निराधार हैं। उन्होंने पुष्टि की कि केवल अपात्र मामलों को ही बाहर किया गया है, और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अन्य पात्र गरीब परिवारों की पहचान कर उनके लिए घर आवंटित करें।

उन्होंने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इंदिरम्मा हाउसिंग योजना के विभिन्न चरणों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को घर मिले।

छांगुर का मददगार इंस्पेक्टर अब्दुर रहमान सिद्दीकी सस्पेंड

हबीब बैंक से लेकर तमाम अकूत धन के दस्तावेज मिले

लखनऊ, 25 जुलाई (एजेंसियां)। धर्मांतरण गिरोह के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की मदद करने वाले गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अब्दुर रहमान सिद्दीकी को निलंबित कर दिया गया है। उस पर छांगुर से पीड़ित एयर होस्टेस का केस न दर्ज करने का भी आरोप है। एयर होस्टेस 2019 से लापता है, उसे छांगुर का गुर्गा बदर अख्तर लव जेहाद में फंसाकर भगा ले गया।

तीन साल पहले अब्दुर रहमान मेरठ स्थित सिविल लाइन थाना प्रभारी के रूप में तैनात था। तब एयर होस्टेस का परिवार अपहरण की शिकायत लेकर पहुंचा था, लेकिन रहमान ने शिकायत दर्ज नहीं की थी।

अब एडिशनल पुलिस आलोक प्रियदर्शनी ने रहमान को निलंबित कर दिया है। उधर, छांगुर पीर के धर्मांतरण मामले में फंडिंग की जांच कर रहे इडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम बलरामपुर पहुंची, जहां टीम को छांगुर के साथी नीतू उर्फ नसरीन और नवीन के धर्मांतरण के दस्तावेज, रिपब्लिक ऑफ पनामा में रजिस्टर्ड मेसर्स लोगोस मरीन नाम की कंपनी और नवीन रोहरा के बीच एमओयू के दस्तावेज मिले।

इसके अलावा मेसर्स एजी कंस्ट्रक्शन और नीतू के बीच विवाद से जुड़े कुछ कानूनी दस्तावेज, छांगुर का यूएई में एंट्री परमिट, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक के हबीब बैंक के दस्तावेज और अन्य तमाम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

मंत्री सीतक्का ने 23 नए सीडीपीओ को सौंपे नियुक्ति पत्र, सामाजिक जिम्मेदारी पर दिया जोर

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।) तेलंगाना की पंचायत राज, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉ. दनासरी अनसूया सीतक्का ने शुक्रवार को महिला एवं बाल कल्याण विभाग में नव-चयनित 23 बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को नियुक्ति पत्र सौंपे।

ये अधिकारी तेलंगाना लोक सेवा आयोग (टीजीपीएससी) के माध्यम से चुने गए हैं। सचिवालय में आयोजित समारोह में उत्सव का माहौल था, जिसमें नव-नियुक्त अधिकारियों के परिवार और शुभचिंतक उत्साह के साथ शामिल हुए। कई माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी सेवा में कदम रखते देख भावुक हो गए और उन्होंने लंबे समय से संजोए सपनों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री सीतक्का ने कहा, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। सीडीपीओ महिला एवं बाल कल्याण विभाग की रीढ़ हैं। आप एक ऐसे सम्मानित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो स्वस्थ और समतामूलक समाज के निर्माण में सीधे योगदान देता है। उन्होंने उम्मीदवारों के समर्पण की सराहना की और उन्हें इस भावना को अपने आधिकारिक कर्तव्यों में बनाए रखने का आग्रह किया।

उनके भूमिका को रेखांकित करते हुए, मंत्री ने कहा कि सीडीपीओ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सेवा करने की विशेष स्थिति में हैं। उन्होंने डेस्क जॉब के बजाय फील्डवर्क के महत्व पर जोर दिया और अधिकारियों को लोगों के बीच जाकर, गैर-राजनीतिक रहकर, और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करने की सलाह दी।

सीतक्का ने आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषण से निपटने के लिए सरकार की पहलों का विवरण दिया, जिसमें नियमित रूप से दूध और अंडे की आपूर्ति, सप्ताह में दो बार अंडा बिरयानी शुरू करना, वर्दी प्रदान करना, और आकर्षक व आनंददायक शिक्षण स्थल बनाने के लिए 57 प्रकार के खिलौनों का वितरण शामिल है।

नव-नियुक्त सीडीपीओ ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया और प्रतिबद्धता व निष्ठा के साथ सेवा देने का वादा किया।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान

ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हमारी तैयारी पुख्ता

नई दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसियां)। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और सेना की तैयारी बहुत पुख्ता है। सेना को चौबीस घंटे तैयार रहना चाहिए। उन्होंने भविष्य के युद्धों को पारंपरिक और आधुनिक तकनीकी युद्ध का समन्वय बताया और कहा कि आज के लिए हाइब्रिड वॉरियर की आवश्यकता है जो टेक, इंफो और स्कॉलर वॉरियर्स का मिश्रण हों।

जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में आयोजित एक रक्षा संगोष्ठी के दौरान कहा कि युद्ध के उभरते परिदृश्य में, भविष्य के सैनिक को सूचना और तकनीक के साथ साथ युद्ध कौशल के ऐसे मिश्रण से लैस होना चाहिए जो वॉरियर की तरह हो। उन्होंने कहा कि सेना के लिए शस्त्र (युद्ध) और शास्त्र (ज्ञान) दोनों सीखना आवश्यक है। उन्होंने आधुनिक युद्ध की बदलती रणनीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज की लड़ाइयां पारंपरिक सीमाओं में नहीं सिमटी हैं, बल्कि वे पारदर्शी, तीव्र, बहु-क्षेत्रीय और तकनीकी रूप से बेहद जटिल हो गई हैं। उन्होंने इसे तीसरी सैन्य क्रांति करार दिया और कहा कि आज का युद्ध केवल बंदूक और टैंक तक सीमित नहीं रह गया है।

सीडीएस चौहान के मुताबिक, आज के योद्धा को सामरिक, परिचालन और रणनीतिक स्तरों पर एक साथ दक्ष होना होगा। उन्हें थल, जल, वायु के साथ-साथ साइबर और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे नए युद्धक्षेत्रों में भी सक्षम होना पड़ेगा। यह एक ऐसा युग है जहां एक ड्रोन हमला, साइबर अटैक, नैरेटिव वॉर और अंतरिक्ष में बाधा एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। जनरल चौहान ने कन्वर्जेंस वॉरफेयर शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि आज काइनेटिक और नॉन-काइनेटिक (यानि पारंपरिक और डिजिटल) युद्ध एक-दूसरे में घुलमिल रहे हैं। पहली और दूसरी पीढ़ी के युद्ध आज तीसरी पीढ़ी के साइबर और एआई आधारित युद्ध के साथ सम्मिलित हो चुके हैं। भविष्य में हमें ऐसे हाइब्रिड वॉरियर की आवश्यकता होगी जो बॉर्डर पर लड़ सकें, रेगिस्तान में रणनीति बना सकें, शहरों में काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला सकें, ड्रोन को निष्क्रिय कर सकें, साइबर हमलों का जवाब दे सकें और प्रभावशाली सूचना अभियान भी चला सकें। अब हमें तीन तरह के योद्धाओं की जरूरत होगी टेक वॉरियर्स, इंफो वॉरियर्स और स्कॉलर वॉरियर्स। जहां टेक वॉरियर्स एआई और साइबर ताकत को इस्तेमाल कर पाएंगे, वहीं इंफो वॉरियर्स नैरेटिव्स को आकार देंगे और फर्जी सूचनाओं का मुकाबला करेंगे। स्कॉलर वॉरियर्स रणनीति और युद्ध विज्ञान की गहरी समझ के साथ निर्णय लेंगे। सीडीएस चौहान के अनुसार, आने वाले युद्धों में सैनिक को इन तीनों भूमिकाओं में दक्ष होना अनिवार्य होगा। यही आधुनिक युद्ध की नई परिभाषा है।

मणिपुर में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन

सरकार बनाने की कोशिशों को लगा झटका

इंफाल, 25 जुलाई (एजेंसियां)। लंबे वक्त से अशांत चल रहे मणिपुर में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन की सीमा को बढ़ा दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में इससे जुड़े प्रस्ताव को पेश कर दिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है, यह सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी 2025 को की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से छह महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करता है। मणिपुर में हालात के लगातार खराब होने के बाद केंद्र सरकार ने इस साल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इससे पहले एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब इसकी समय सीमा खत्म होने के पहले राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलती रही है कि वह मणिपुर में हालात को सामान्य नहीं कर पाए और आज तक मणिपुर नहीं गए। पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में सरकार के गठन की कोशिशें तेज हुई हैं और मैतेई और नागा समुदाय से जुड़े एनडीए के विधायक सरकार बनाने की कोशिशें में जुटे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने पर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे एनडीए के विधायक नाराज हो सकते हैं। मणिपुर में मई, 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा शुरू हुई थी और राज्य और केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य में हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। इस हिंसा में अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और सम्पत्ति का भी अच्छा-खासा नुकसान हो चुका है। सरकार ने इस साल के अंत तक हिंसा से विस्थापित हुए लोगों के एक बड़े हिस्से को उनके घरों तक पहुंचाने का इरादा जताया है लेकिन मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच संघर्ष शुरू होने के 26 महीने से ज्यादा समय बाद भी दोनों समुदायों के बीच बातचीत को लेकर ठोस काम नहीं हो पाया है।

तेलंगाना में जातिगत जनगणना का नेतृत्व

भाजपा पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण को रोकने की कोशिश कर रही है: पोन्नम प्रभाकर

नई दिल्ली/हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। तेलंगाना के परिवहन और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने शुक्रवार को कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने केंद्र में सत्ता में न होने के बावजूद जातिगत जनगणना को लागू करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश करने के लिए बीजेपी नेताओं की निंदा की।

एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए, प्रभाकर ने कहा कि राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया था और सत्ता में आने पर इसे लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने 4 फरवरी, 2024 को जातिगत जनगणना शुरू करके नेतृत्व किया।

लोकसभा चुनाव के कारण कुछ देरी के बावजूद, राज्य सरकार ने 3.5 करोड़ लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ जनगणना सफलतापूर्वक पूरी की। 80 करोड़ से अधिक दस्तावेज़ों का एकत्र किया गया डेटा डिजिटाइज़ किया गया, एक उप-समिति द्वारा इसकी समीक्षा की गई और राज्य कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दी गई।

पिछड़ा वर्ग को शिक्षा और स्थानीय निकायों में 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए बनाए गए कानून को पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया था, और बाद में 30 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया। प्रभाकर ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीजेपी नेताओं पर विधेयक का विरोध करने का आरोप लगाते हुए पिछड़ा वर्ग के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के लिए हमसे ज्यादा क्या किया है? इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करने के बजाय, वे गलत जानकारी फैलाकर और हमारे प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के मंडल आयोग और सामाजिक न्याय नीतियों के पिछले विरोध का भी हवाला दिया।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बीजेपी, जब पिछड़ा वर्ग का समर्थन करने का दावा करती है, तो उसने तेलंगाना में विपक्ष के नेता के रूप में किसी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को क्यों नहीं नियुक्त किया या अपनी पार्टी में पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व को क्यों नहीं बनाए रखा। उन्होंने कहा, हमारी कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की ब्रांड एंबेसडर है। हम किसी भी पार्टी पर दोष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन तथ्यों की जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने बीजेपी नेताओं से विभाजन पैदा करना बंद करने और इसके बजाय जातिगत जनगणना और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ तेलंगाना के बारे में नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस बातचीत के दौरान मंत्री कोंडा सुरेखा और वकिति श्रीहरि भी मौजूद थे।

खबरें जो सोच बदल दे
शुभ लाभ

फिल्म सैयारा ने दुनियाभर में रचा इतिहास

आमिर-अजय देवगन की फिल्मों को पछाड़ बनी तीसरी ब्लॉकबस्टर

मोहित सूरी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा इन दिनों दर्शकों और सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की फ्रेश जोड़ी और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। वहीं ,फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई ने भी सबको चौंका दिया है। अब इस फिल्म ने एक और बड़ा

रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसे जानकर फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे।

दरअसल, फिल्म ने अपने पहले 7 दिनों में ही आमिर खान की आइकॉनिक फिल्म 'सितारे जमीन पर' के लाइफटाइम नेट कलेक्शन 166।18 करोड़ को पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, अब इसने अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म 'रेड 2' को भी पछाड़ दिया है।

सैयारा ने तोड़ा अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म का रिकॉर्ड

डरलपळश्रज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार, सैयारा ने सोमवार को 24 करोड़, मंगलवार को 25 करोड़ और बुधवार को 21 करोड़ की कमाई करते हुए सिर्फ 7 दिनों में 177.13 करोड़ का शानदार नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 248.50 करोड़ पहुंच चुकी है।

इसके साथ ही फिल्म ने रेड 2 के इंडिया कलेक्शन 173.44 करोड़ और वर्ल्डवाइड 237.46 करोड़ को पार करते हुए साल 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। यह 'सैयारा' के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो रहा है।

तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बनी सैयारा

इसके अलावा सैयारा अब तक की बंपर ओपनिंग करने वाली तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। 2025 में 'छावा', 'सिकंदर' और 'हाउसफुल 5' जैसी बड़ी फिल्मों के बीच, 'सैयारा' ने अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्म के ओपनिंग डे पर म्यूजिक, ट्रेलर और सोशल मीडिया पर वायरल टाइटल ट्रैक ने लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से इसे जबरदस्त ओपनिंग मिली।

स्मृति ईरानी के कमबैक पर अनुपमा सोलंकी बोलीं

उनके शो देखकर बड़ी हुई आज भी भावुक हो जाती हूं

अभिनेत्री अनुपमा सोलंकी खुश हैं कि स्मृति ईरानी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के साथ छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। अनुपमा ने बताया कि वह उनके शो बचपन से देखती आई हैं, शो का थीम सॉन्ग सुन वो आज भी भावुक हो जाती हैं। अनुपमा ने बताया कि वह स्मृति के शो देखकर बड़ी हुईं।

स्मृति ईरानी की टीवी पर वापसी के बारे में पूछे जाने पर अनुपमा ने कहा, यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। इतने सालों बाद उन्हें फिर से कास्ट किया गया है, जैसे एकता कपूर ने पहले किया था। मैं 'कहानी घर घर की', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'कसौटी जिंदगी की' देखकर बड़ी हुई हूं। आज भी उन शोज के थीम सॉन्ग सुनकर भावुक हो जाती हूं।

'जागृति - एक नई सुबह' फेम अभिनेत्री ने आगे कहा, हाल ही में मैंने 'क्योंकि' के गाने पर एक रील बनाई। काश, मैं इस वापसी का हिस्सा होती, लेकिन मैं जहां हूं, वहां खुश हूं। मुझे उम्मीद है कि स्मृति जी का नया शो सुपरहिट होगा, क्योंकि यह बहुत शानदार शो है, जो दर्शकों को आज भी बहुत पसंद है। टीवी के सुनहरे युग की वापसी पर अनुपमा ने कहा, शायद यह संभव हो। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उस दौर में भावनाओं और दर्शकों से जुड़ाव की जो गहराई थी, वह बेमिसाल थी। मैं चाहती हूं कि वह दौर लौटे। एकता मैम के शो अब कम आते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह नया शो दर्शकों के दिलों को छू लेगा।

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2' का प्रीमियर 29 जुलाई को स्टार प्लस पर होगा। स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय तुलसी और मिहिर विरानी की अपनी लोकप्रिय भूमिकाओं में वापसी करेंगे।

इस नए अध्याय में हितेन तेजवानी, गौरी प्रधान, शक्ति आनंद, कमलिका गुहा ठाकुर, शगुन शर्मा, रोहित सुचंती, अमन गांधी, अंकित भाटिया और तनीषा मेहता जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

क्या धर्मा प्रोडक्शंस और पीपल मीडिया फैक्ट्री के बीच होगी हाई-प्रोफाइल साझेदारी ?

पीपल मीडिया फैक्ट्री की आगामी मेगा फिल्म मिराई, जिसमें तेजा सज्जा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म के विजुअली दमदार पोस्टर्स और दमकते टीज़र ने दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता और रोमांच पैदा कर दिया है। 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही मिराई, साल की सबसे चर्चित पैन-इंडिया फिल्मों में से एक बन चुकी है। अब इंडस्ट्री में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है - खबरें हैं कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस, पीपल मीडिया फैक्ट्री की मिराई के साथ साझेदारी करने की योजना बना रही है। बाहुबली, 2.0 और अपकमिंग देवारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ रणनीतिक भागीदारी के लिए मशहूर धर्मा प्रोडक्शंस अगर मिराई से जुड़ती है, तो फिल्म की पहुंच और लोकप्रियता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है।

एक सूत्र ने इस बारे में जानकारी दी, अगर धर्मा इस फिल्म से जुड़ती है, तो मिराई एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगी। इससे इसकी पहुंच और दृश्यता देशभर में और उससे भी आगे तक फैलेगी। करण जौहर की जनमानस की समझ और धर्मा की मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता के साथ, मिराई एक सच्चे मायनों में अखिल भारतीय इवेंट फिल्म बन सकती है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं तेजा सज्जा, जो हाल ही में 2024 की पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर हनुमान में नजर आए थे। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं कार्तिक गट्टमनेनी, जो अपनी विज़ुअल स्टोरीटेलिंग के लिए जाने जाते हैं।

निर्माता हैं टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद, जिनका नाम महत्वाकांक्षी सिनेमा के निर्माण के

लिए जाना जाता है। मिराई एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है जिसमें मिथकीय कथानक, तीव्र एक्शन और अत्याधुनिक वीएफएक्स का अद्भुत संगम होगा। फिल्म की कहानी एक निडर योद्धा की है जिसे नौ पवित्र ग्रंथों की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। फिल्म में मनोज मंचु और ऋतिका नायक भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जिनके दमदार अभिनय से कहानी को गहराई और तीव्रता मिलती है। फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं गौरा हरि, जिनका बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मकता और भव्यता को और अधिक ऊँचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। पीपल मीडिया फैक्ट्री ने 2025 की धमाकेदार शुरुआत की है सनी देओल स्टारर जाट की सफलता के साथ। मिराई के अलावा, उनके पास प्रभास की हॉरर-कॉमेडी द राजा साब समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो यह साबित करते हैं कि वे साल भर बॉक्स ऑफिस की रेस में आगे रहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

रश्मिका मंदाना ने लॉन्च किया अपना फ्रेगरेंस ब्रांड

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपने फ्रेगरेंस ब्रांड के लॉन्च की घोषणा की है। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि परफ्यूम उनके लिए एक ऐसी चीज है, जो अक्सर उन्हें उन खास पलों में वापस ले जाता हैं, जिन्हें वह भूल जाती हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का परफ्यूम ब्रांड 'डियर डायरी' मेरे निजी जीवन के अनुभवों और विचारों से प्रेरित है। अभिनेत्री ने बताया, मेरे लिए, खुशबू का मतलब यादें हैं। मुझे बहुत सी बातें याद नहीं रहतीं, या शायद कुछ चुनिंदा बातें ही याद रहती हैं, लेकिन परफ्यूम उन खास पलों को फिर से ताजा कर देता है जिन्हें मैं शायद भूल जाती हूं। इसी तरह से मैं उन लोगों, जगहों और अनुभवों को याद रखती हूं, जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी बन पाई हूं।

उन्होंने आगे कहा कि 'डियर डायरी' के जरिए वह सभी को अपनी कहानियों में साथ ले जाने का एक तरीका देना चाहती हैं।

रश्मिका ने बताया, उनके परफ्यूम को लॉन्च करने का मकसद बस खुद से जुड़ना, सुकून महसूस करना, एक अच्छा अहसास पाना और बिना किसी झिझक के अपनी पहचान बताना है।रश्मिका ने अपने नए फ्रेगरेंस ब्रांड के बारे में बात करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, यह वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, न ही परफ्यूम है, बल्कि मेरा एक हिस्सा है। खुशबू हमेशा से मेरी निजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है... और आज मैं आपके साथ इसको साझा कर रही हूं। उन्होंने कहा, मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे यह ब्रांड लॉन्च करने का मौका मिला और मैं इसको लेकर काफी उत्साहित भी हूं। मुझे उम्मीद है कि इसे आगे बढाने के लिए मुझे आप सभी का साथ मिलेगा। इस घोषणा से पहले भी अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा की थी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना गया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आखिरकार इसे रिकॉर्ड कर रही हूं। जैसा कि आप अब तक जानते ही होंगे, मैं अपने दिल के बहुत करीब किसी चीज पर काम कर रही हूं। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि मैंने आपके लिए मेरा जीवन का एक छोटा सा हिस्सा भी है। रश्मिका ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि आप इसे महसूस करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा, यह कल लॉन्च हो रहा है, और मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं।

कल रवि योग में मनाई जाएगी हरियाली तीज

नीतिका शर्मा
ज्योतिषाचार्या एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर
श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर, अजमेर

हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करती हैं। कुछ स्था नों पर कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्यी वर पाने के लिए भी तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं अपनी सखियों के साथ मिलकर पेड़ पर झूला डालती है और सावन के लोकगीत गाकर इस त्यौहार की खुशियां मनाती हैं। श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि पंचांग के अनुसार, सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 26 जुलाई को रात 10:41 मिनट पर शुरू होगी और यह तिथि 27 जुलाई को रात 10:41 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो शाम 4:23 मिनट से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 मिनट तक रहेगा। रवि योग में पूजापाठ करना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्वम होता है इसलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियां भी पहनने का प्रचलन है। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को नाग पंचमी से दो तिथि पूर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं।

सनातन धर्म में हर त्योहार का अपना एक विशेष महत्व हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है हरियाली तीज है, जो देशभर में मनाई जाती हैं। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता हैं। हरियाली तीज सावन मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व हैं।

महिलाएं इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करती हैं। हरियाली तीज सौंदर्य और प्रेम का पर्व हैं। यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता हैं। यह पर्व प्रकृति से जुड़ने का पर्व हैं। हरियाली तीज का जब पर्व आता है तो हर तरफ हरियाली छा जाती हैं। पेड़ पौधे उजले उजले नजर आने लगते हैं। हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता हैं। हरियाली तीज या श्रावणी तीज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं।

हरियाली तीज पर शुभ योग

इस साल हरियाली तीज के अवसर पर रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो शाम 4:23 मिनट से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 मिनट तक रहेगा। रवि योग में पूजापाठ करना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है।

शादी के बाद की पहली तीज है खास

हरियाली तीज की पूजा दोपहर बाद ही होती है। इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, जो कि जरूरी रस्म होती है। इसके अलावा घेवर खाती हैं। असल में इस पर्व का नाम मधुश्रवा हरियाली तीज है। यह नाम इसीलिए पड़ा कि इसमें मधु टपकता है। मिष्ठान्न खाने को मिलते हैं। खासकर नवविवाहिता की पहली तीज पर खास आयोजन होता है। ससुराल से उसके लिए सिंधारा आता है। इसमें घेवर, फेनी, कपड़े, मिष्ठान्न, फल आदि आते हैं।

हरियाली तीज परम्पराएं

सावन के माह में आने वाले त्यौहारों को नवविवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाने की परम्परा है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, साथ ही हरियाली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। यह सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी मानी गई है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती हैं। अगर सास नहीं हो तो सुहागा जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से मां पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले झूलती हैं और लोक गीत पर नृत्य करती हैं।

पूजा विधि

शिव पुराण में हरियाली तीज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था इसलिए इस व्रत की विवाहित स्त्रियों के लिए बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती के लिए व्रत एवं उनका पूजा-अर्चना करती हैं। हरियाली तीज के दिन साफ-सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, माँ पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी-देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। माँ पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किये जाते हैं।

ऐसे मिला था देवी पार्वती को तप का फल

भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती! इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था। उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूं। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि इस कथा को जो भी स्त्री पढ़ती या सुनती है वहअखंड सौभाग्यवती होती है।

हरियाली तीज से है चंद्रमा का संबंध, जानें दुर्लभ तथ्य

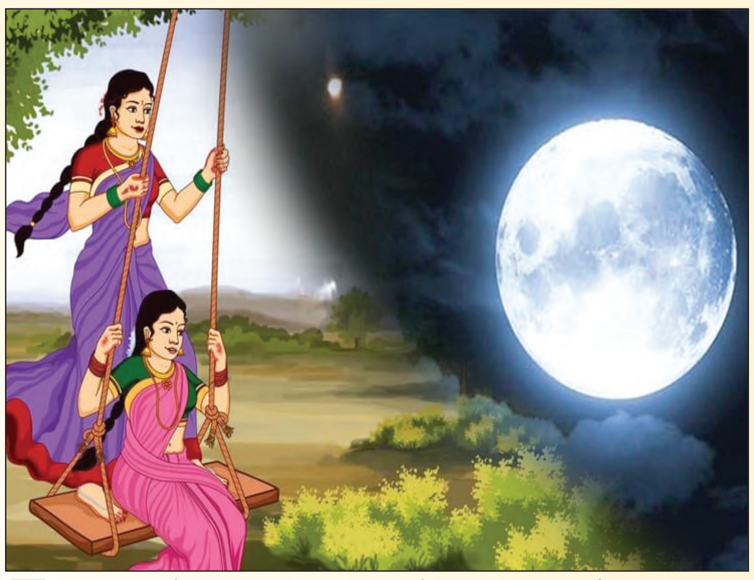

हरियाली तीज केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह स्त्री के अंतर्मन और प्रकृति के बीच की सूक्ष्म ऊर्जा के सामंजस्य की प्रतीक है। इस दिन महिलाएं न सिर्फ श्रृंगार और पूजा के माध्यम से अपने वैवाहिक जीवन की समृद्धि की प्रार्थना करती हैं, बल्कि मानसिक अनुशासन और आत्म-संयम का अभ्यास भी करती हैं।

वेदों और ज्योतिषीय ग्रंथों में चंद्रमा को 'मन' का स्वामी माना गया है - वह ग्रह जो विचार, भावना और कल्पनाशीलता का संचालन करता है। श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को जब हरियाली तीज मनाई जाती है, तब चंद्रमा अपने उज्ज्वल पक्ष में होता है। इस समय मानसिक ऊर्जा अत्यंत सक्रिय रहती है, जिससे मन अधिक चंचल और संवेदनशील हो सकता है।

हरियाली तीज का व्रत: मन की चंचलता पर संयम का अभ्यास

ऐसे में तीज का व्रत - विशेष रूप से निर्जल व्रत - इस चंचलता को नियंत्रित करने का माध्यम बनता है। जब शरीर अन्न और जल से विरत होता है, तो मन बाह्य आकर्षणों से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है। पूजा, कथा और भक्ति गीत जैसे कर्म मानसिक एकाग्रता को बढ़ाते हैं।

तीज की रात को महिलाएं जागरण करती हैं - यह न केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि चंद्रमा की मानसिक तरंगों को आत्मसात करने की एक साधना भी है।

यह पर्व हमें सिखाता है कि व्रत और त्यौहार केवल परंपरा निभाने के कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्म-अनुशासन और मानसिक स्थिरता के प्रयोग हैं। हरियाली तीज का व्रत एक प्रकार का 'मानसिक उपवास' है, जो चंद्र ऊर्जा के माध्यम से मन को शांत करने और रिश्तों में संतुलन लाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

इस दृष्टिकोण से देखें तो हरियाली तीज केवल हरे वस्त्रों और झूलों का पर्व नहीं, बल्कि यह एक 'चंद्र साधना' है - जो स्त्री के भीतर छिपी प्रकृति और चेतना के साथ संवाद स्थापित करती है।

हरियाली तीज पर महिलाएं रखें इन बातों का विशेष ख्याल

* इस महिलाओं को हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और हरी चूड़ियां भी।
* हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को सोलह श्रृंगार का सामान अर्पित करें और शादीशुदा महिलाएं खुद भी सोलह श्रृंगार करें।
* जो महिलाएं व्रत कर रही हैं उन्हें भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। खाने पीने से व्रत अधूरा माना जाता है।
* साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र और चूड़ियां भूलकर भी न पहनें।

हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि

हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

इसके बाद सबसे पहले अपने पूजाघर को साफ करें और गंगाजल छिड़ककर पूजा घर को पवित्र करें।

इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें।

इसके बाद घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और फिर माता पार्वती को श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें की माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बालू से बनी होनी चाहिए। अगर बालू की प्रतिमा न हो तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं।

इसके बाद सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती की आवाहन करें और इसके बाग शिवजी का अभिषेक करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें।

इसके बाद हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करें और अंत में शिव पार्वती की आरती करे और हाथ जोड़कर पूजा में हुई कोई भी भूल चूक के लिए माफी मांगे।

अगले दिन बालू से बनी प्रतिमा को किसी नदी में विसर्जित कर दें।

तीज पर व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी नियमों करें पालन

सावन का महीना हरियाली, उत्सव और नारी शक्ति की आभा से जगमगाता है। खासतौर पर हरियाली तीज का पर्व महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख-शांति के लिए व्रत रखती हैं। सजी-धजी महिलाएं, हाथों में मेंहदी और झूलों की रौनक - तीज का दृश्य किसी पर्व से कम नहीं। लेकिन इस व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन भी बहुत ज़रूरी है।

निर्जला व्रत का पालन करें

तीज का व्रत बिना पानी के (निर्जला) रखा जाता है। कई महिलाएं अनजाने में चाय या फल ले लेती हैं, जिससे व्रत टूट सकता है। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो बिना पानी के व्रत रखें। अस्वस्थ या गर्भवती होने की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लें।

व्रत के दिन हरा रंग पहनना शुभ

हरे रंग को हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। काले और सफेद रंग से बचें और हरा, लाल या पीला रंग पहनें।

सोलह श्रृंगार है जरूरी

बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और मेंहदी जैसी सुहाग की निशानियों के बिना तीज का व्रत अधूरा माना जाता है।

नुकीली चीजों से परहेज करें

सुई-कैंची जैसी चीजोंका उपयोग न करें। तुलसी के पत्ते भी न तोड़ें, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बाधित हो सकती है।

मन को शांत रखें

इस दिन झगड़ा या बहस करने से बचें। भक्ति और भजन में समय बिताएं, जिससे मन और व्रत दोनों पवित्र बने रहें।

दिन में न करें सोना

हालांकि शरीर थक सकता है, फिर भी दिन में सोना वर्जित माना गया है। पूजा और भजन करना अधिक फलदायी होता है।

व्रत के बाद करें दान

व्रत पूर्ण होने के बाद अन्न, जल और वस्त्रों का दान करना आवश्यक है। यह व्रत को पूर्णता देता है और पुण्य में वृद्धि करता है। हरियाली तीज सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री श्रद्धा, शक्ति और सौभाग्य का पर्व है। श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए किया गया यह व्रत आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है।

शनिवार को इनमें से कोई एक चीज जरूर खाएं

शनिदेव चमका देंगे भाग्य, जल्दी पाएंगे लाभ और तरक्की

शनिवार के स्वामी देवता भगवान शनि को माना जाता है। शनि के बारे में ज्योतिषशास्त्र में कहा गया है कि यह भाग्य को चमका भी सकते हैं और नाराज होने पर राजा को भी रंक बना देते हैं। ऐसे में शनि महाराज को अनुकूल बनाए रखना हर किसी के लिए जरूरी माना गया है। चाहे आपकी साढ़े साती, ढैय्या नहीं भी चल रही हो या शनि की दशा के प्रभाव में भी आप नहीं हो लेकिन फिर भी आपको शनि के उपाय हर शनिवार को जरूर करना चाहिए ताकि जब शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या दशा आए तो शनिदेव आपका अहित न करें साथ ही प्रसन्न होकर आपका सोया भाग्य चमका दें और तरक्की दिलाएं। इसके लिए कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो खानपान से जुड़े हुए हैं। तो आप व्रत करने की बजाय रुचिकर भोजन का आनंद लेते हुए भी शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते है, तो आइए जानते हैं कि शनिवार के दिन किन-किन चीजों को खाने से शनिदेव कृपा बरसाते हैं और आपको तरक्की दिलाते हैं।

शनिवार को खिचड़ी खाने के लाभ

शनिवार के दिन बहुत से लोग खिचड़ी जरूर खाते हैं। अगर आप अब तक ऐसा नहीं करते हैं तो शनिवार के दिन खिचड़ी खाने का यह फायदा जानेंगे तो आप भी इसे आदत बना लेगे। ऐसी मान्यता है कि उड़द की दाल जो शनिदेव से संबंध रखता है उससे खिचड़ी बनाकर खाने से और शनिदेव को भोग लगाने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और आपके ऊपर से शनि का प्रकोप भी दूर हो जाता है। अगर उड़द दाल नहीं हो तो आप जिस भी दाल को पसंद करें उससे भी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। यह भी लाभकारी होता है।

शनिवार को भुने हुए चने खाने का फायदा

आपने देखा होगा कि बहुत से लोग शनिवार के दिन बंदरों को काले चने खिलाते हैं। यह उपाय भी शनि के प्रकोप को कम करता है। लेकिन आप बंदरों को चने खिलाने के साथ-साथ भुने हुए काले चने खुद भी खाएं तो यह और भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। मान्यताओं के अनुसार काले चने का संबंध शनिदेव से है। इसे खाने से शनि ग्रह से संबंधित जो शारीरिक दोष होता है वह भी दूर हो जाता है। और शनिदेव के प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव होता है।

शनिवार को काले तिल खाने के फायदे

काले तिल को भगवान विष्णु से उत्पन्न माना जाता है। काले तिल के विषय में कथा है कि यह शनि महाराज को भी बहुत प्रिय है जो भक्त नियमित शनिवार के दिन काले तिल से पीपल की पूजा करता है और शनिवार के दिन काले तिल का प्रसाद शनि महाराज को अर्पित करता है और काले तिल का सेवन करता है उसके सभी पाप कट जाते हैं और शनि महाराज भी अपने ऐसे भक्त पर प्रसन्न होकर तरक्की दिलाते हैं।

शनिवार को काला जामुन खाने के फायदे

शनिवार के दिन आप काले जामुन का सेवन करें तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जामुन सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक माना जाता है। यह शुगर सहित कई रोगों में लाभदायक होता है। जब जामुन का मौसम समाप्त हो जाए तो आप मिठाई वाला काला जमुन भी खा सकते हैं। लाल किताब के उपाय में कौए और कुत्ते को काला जामुन खिलाना भी ग्रहों के दोष को दूर करने वाला बताया गया है।

भाग्यनगर कांवड़ सेवा संघ की 28वीं भव्य कांवड़ यात्रा कल

हैदराबाद-सिकंदराबाद में शिवभक्ति का संगम हजारों कांवड़िये करेंगे जलाभिषेक

भाग्यनगर कांवड़ सेवा संघ द्वारा आयोजित होने वाली 28वीं भव्य पैदल कांवड़ यात्रा 2025 का आयोजन इस वर्ष 27 जुलाई को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया जाएगा। यह कांवड़ यात्रा चारमीनार स्थित श्री महादेव मंदिर से आरंभ होकर मंचीरेवुला स्थित ब्रह्मसूत्र ओंकारेश्वर स्वामी देवालयम (प्राचीन शिव मंदिर) तक जाएगी।

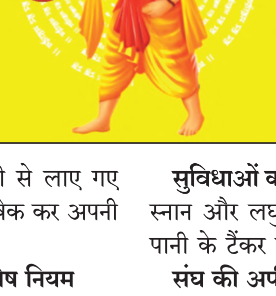

भाग्यनगर कांवड़ सेवा संघ के अध्यक्ष मांगेराम तायल ने बताया कि यह यात्रा अपनी भव्यता और विशेषता के लिए जानी जाती है, जिसमें हर वर्ष हजार से अधिक कांवड़िये शामिल होते हैं। कांवड़धारी हरिद्वार की हर की पौड़ी से लाए गए पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे।

सुरक्षा और अनुशासन के लिए विशेष नियम

संघ के अध्यक्ष मांगेराम तायल ने बताया कि सभी कांवड़ियों और शिवभक्तों की सुरक्षा और यात्रा की सुचारू रूप से पूर्णता के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। उन्होंने सभी से इन नियमों का पालन करने का आग्रह किया।

कांवड़ यात्रा के मुख्य नियम

चमड़े की कोई वस्तु न पहनें – कांवड़ियों के शरीर पर जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स आदि किसी भी प्रकार की चमड़े की वस्तु नहीं होनी चाहिए।

सात्विक भोजन ही ग्रहण करें – केवल संघ द्वारा उपलब्ध कराया गया सात्विक भोजन लें। बाहर से केवल पानी लेना अनुमत है।

डीसीएम रस्सी के अंदर चलें – संघ द्वारा डीसीएम (वाहन) में बांधी गई रस्सी के अंदर सभी को चलना होगा। शिव का जाप करते हुए अपनी पंक्ति में अनुशासित रूप से चलें।

क्रम संख्या का पालन करें – सभी कांवड़ियों को क्रम संख्या के अनुसार छोड़ा जाएगा। खड़ी कांवड़ उठाना आस्था का प्रतीक है, अतः अपने क्रम का धैर्यपूर्वक इंतजार करें।

संघ की व्यवस्था में बाधा न डालें – डीसीएम के आगे जाने या भीड़ में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास न करें।

सुविधाओं का सही उपयोग करें – पानी की गाड़ियां, स्नान और लघुशंका के लिए सुलभ की गाड़ियां तथा पानी के टैंकर उपलब्ध रहेंगे।

संघ की अपील – श्रद्धा और सुरक्षा दोनों जरूरी

मांगेराम तायल ने कहा, संघ हमेशा यही प्रयास करता है कि किसी भी कांवड़धारी या शिवभक्त को कोई परेशानी न हो। लेकिन सभी को अपनी और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। किसी भी अप्रिय घटना के लिए संघ जिम्मेदार नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि सभी अनुशासन का पालन करते हुए यात्रा का आनंद लेंगे और महादेव की भक्ति में लीन रहेंगे।

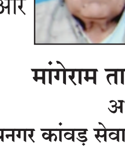

मांगेराम तायल
अध्यक्ष
भाग्यनगर कांवड़ सेवा संघ

शुभ लाभ — खबरें जो सोच बदल दे — हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

संपादकीय

उपराष्ट्रपति का इस्तीफा

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संवैधानिक पद से अचानक ही इस्तीफा देकर देश को चौंका दिया। वह देश के 14वें उपराष्ट्रपति थे और अभी 10 अगस्त, 2027 तक उनका कार्यकाल शेष था। बीते दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि यदि ईश्वर की कृपा रही, तो अगस्त, 2027 में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। वह देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 67-ए के मुताबिक इस्तीफे को 'तत्काल प्रभावी' मानने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेषित इस्तीफे में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट का आभार जताया है। प्रधानमंत्री के सहयोग और समर्थन को 'अमूल्य' माना है। सांसदों के स्नेह और सम्मान को धन्यवाद दिया है। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफे में भारत की प्रगति, आर्थिक विकास और परिवर्तनकारी युग का साक्षी बनने, बल्कि उसका भागीदार होने की भावुक बात कही है। आज जब वह यह पद छोड़ रहे हैं, तो उनके दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। स्वतंत्र भारत के गणतांत्रिक इतिहास में वीवी गिरि ने 20 जुलाई, 1969 को और आर. वेंकटरमण ने जुलाई, 1987 में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे दिए थे। गिरि राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते थे और वेंकटरमण राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके थे। बहरहाल उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस फैसले की पृष्ठभूमि में सेहत और बीमारी की बड़ी वजह हो सकती है। वैसे इस पद पर आसीन लोगों की बीमारियां काफूर हो जाती हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों की निरंतर निगरानी रहती है। संभव है कि अब धनखड़ के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता हो और डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी हो, लेकिन उनकी तबीयत इतनी नाजुक भी नहीं है कि वह उपराष्ट्रपति पद का दायित्व निभाने में असहाय और अक्षम महसूस कर रहे हों! यह सतही तौर का कारण हो सकता है। अलबत्ता यह कोई सामान्य घटना नहीं है। जो पत्रकार और नेता उनके संसदीय कार्यकाल के दौरान सक्रिय रहे हैं और उन्हें करीब से जानने के मौके मिले हैं, उनका स्पष्ट मानना है कि उपराष्ट्रपति बीते कुछ अंतराल से परेशान दिख रहे थे। उनका इस्तीफा यह भी सत्यापित करता है कि सरकार, सत्ता और खास कर भाजपा के भीतर सब कुछ सहज नहीं है। सरकार के भीतर विरोधाभास और संकट हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ संघ-भाजपा पृष्ठभूमि के नेता नहीं थे। वह लोकदल और जनता दल की राजनीति से आए थे। चौधरी देवीलाल ने उन्हें राजनीति में उतारा था, नतीजतन 1989 में वह राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र से चुन कर लोकसभा में पहुंचे। तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार में राज्यमंत्री भी रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में आए और 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो प्रधानमंत्री उनकी राजनीतिक सोच को अच्छी तरह जान चुके थे। फिर उन्हें 11 अगस्त, 2022 को देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया, तो फोकस था कि एक बड़े किसान और जाट नेता के तौर पर उन्हें मान्यता दी जाए। बहरहाल हम सिर्फ सेहत को ही इस्तीफे का कारण मानने को तैयार नहीं हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, तो वह राज्यसभा के सभापति के आसन पर विराजमान थे। सदन की कार्यवाही संचालित करते रहे। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मजाक करते रहे। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। शाम को विपक्ष के सांसदों से भी मुलाकात की। बेशक बीते दिनों उनके सीने में दर्द उठा था और उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती होना पड़ा था, लेकिन चिकित्सकों के बुनियादी इलाज के बाद वह बाहर आ गए। मानसून सत्र की मुलाकातों के दौरान इतना-सा भी संकेत नहीं दिया कि वह इस्तीफा देने जा रहे हैं अथवा कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, लिहाजा माना जा सकता है कि सरकार और उनके दरमियान ऐसे मतभेद उभर आए होंगे कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ठोस कारण की घोषणा वह स्वयं किसी किताब में करेंगे अथवा सरकार से छन कर सूचनाएं बाहर आएंगी। हम उन्हें जितना जानते हैं, उसके मद्देनजर दावा कर सकते हैं कि वह योद्धा किस्म के नेता रहे हैं। कोई भी, किसी भी तरह के दबाव में उन्हें इस्तीफा देने को बाध्य नहीं कर सकता। बेशक वह अक्खड़, साफगो किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन बेहद कोमल, सौहार्द और पार्टीबाज नेता भी रहे हैं। अब आगे अटकलें ही जारी रहेंगी। बाद में मिली सूचनाओं के अनुसार राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है।

> देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 67-ए के मुताबिक इस्तीफे को 'तत्काल प्रभावी' मानने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेषित इस्तीफे में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट का आभार जताया है। प्रधानमंत्री के सहयोग और समर्थन को 'अमूल्य' माना है। सांसदों के स्नेह और सम्मान को धन्यवाद दिया है। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफे में भारत की प्रगति, आर्थिक विकास और परिवर्तनकारी युग का साक्षी बनने, बल्कि उसका भागीदार होने की भावुक बात कही है। आज जब वह यह पद छोड़ रहे हैं, तो उनके दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है।

कानून की दृष्टि में अपराध केवल घटना नहीं, उस घटना के पीछे की मंशा, सबूतों की पुष्टि, प्रक्रिया की शुद्धता और निष्पक्षता का भी मूल्यांकन करता है

मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों का फैसला और उठते सवाल

ललित गर्ग

11 जुलाई 2006 को मुंबई की भीड़भरी लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया था। पीडित परिवारों के साथ-साथ जन-जन को आहत किया था। 7 जगहों पर हुए इन धमाकों में 187 निर्दोष लोगों की जान गई और 824 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। लेकिन इन बम धमाके को लेकर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कोर्ट ने विशेष मकोका अदालत की ओर से 12 अभियुक्तों को दी गई सजा को गैरकानूनी करार दिया। इन सभी आरोपियों का बरी हो जाना सवाल के साथ-साथ चिन्ता भी पैदा करता है। इसीलिये करीब 19 साल बाद आए अदालत के इस फैसले को लेकर न केवल कानूनी दायरे में, बल्कि सामाजिक व नैतिक दृष्टिकोण से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल वहीं घूमकर आ जाता है कि इतने बड़े नुकसान का दोषी कौन है? लम्बी न्यायिक प्रक्रिया एवं जांच के बाद 2015 में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 12 अभियुक्तों को दोषी करार दिया, जिसमें से 5 को फांसी और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला लगभग 8 वर्षों की सुनवाई, 250 से ज्यादा गवाहों और हजारों पन्नों की गवाही के बाद आया। लेकिन 2023 और फिर 2025 में कुछ सिविल सोसाइटी संगठनों, मानवाधिकार समूहों और कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ दोषियों को पर्याप्त सबूतों के बिना फंसाया गया, पुलिस की जांच पक्षपातपूर्ण रही और कई जगह कानून के दायरे का अतिक्रमण किया गया। इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट में जिस तरह से एक-एक करके सारे सबूतों की धज्जियां उड़ायी, उससे पूरे सिस्टम को लेकर संदेह उठता है। जब इतने अहम मामले में इतनी लचर एवं लापरवाहीपूर्ण जांच हुई, तो फिर दूसरे तमाम केस में क्या होता होगा? गवाहों के बयान दर्ज करने से लेकर सबूत जुटाने तक, हर जगह लापरवाही एवं कौताही बरती गई। कानून की दृष्टि में अपराध केवल घटना नहीं, उस घटना के पीछे की मंशा, सबूतों की पुष्टि, प्रक्रिया की शुद्धता और निष्पक्षता का भी मूल्यांकन करता है। "दोषी को सजा मिलनी चाहिए"-यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, लेकिन "निर्दोष को दंड न मिले"-यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है। भारतीय दंड संहिता, मकोका और गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) जैसे सख्त कानून आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए, लेकिन इनका उपयोग अक्सर राजनीतिक प्रभाव, मीडिया ट्रायल, या जनभावनाओं को शांत करने के लिए किया गया है। ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में अनेक ज्वलंत सवाल खड़े हुए हैं कि क्या सभी दोषियों को वास्तव में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर दोषी ठहराया गया है? यदि नहीं, तो यह न्याय व्यवस्था के लिए एक गंभीर प्रश्न है। क्या पुलिस या जांच एजेंसियों ने निष्पक्ष जांच की? कई बार जांच एजेंसियों पर 'नतीजे पहले, जांच बाद में' का आरोप लगा है। क्या विशेष अदालतों का गठन निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है या त्वरित दंड की नीति अपनाता है? क्या कानून केवल सख्ती का पर्याय बन गया है या उसमें मानवीय संवेदना का स्थान है? क्या मीडिया ट्रायल ने वास्तविक न्याय को प्रभावित किया? इन प्रश्नों के उत्तर मिलना ही चाहिए। देश के सामने आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चुनौती है, तो वहीं न्याय की नैतिकता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। अगर कानून का इस्तेमाल अन्याय के लिए किया गया, तो आतंकवाद के खिलाफ जंग की नैतिकता ही सवालों में पड़ जाएगी। न्याय केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि नैतिक और विधिसम्मत संतुलन का नाम है। जो निर्दोष है, उसे दोषमुक्त करना और जो दोषी है, उसे यथोचित दंड देना- यही कानून का आदर्श उद्देश्य है। मुंबई बम धमाके जैसी वीभत्स घटनाएं देश के लिए चुनौती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के नाम पर अगर हम न्याय और कानून के मूलभूत सिद्धांतों से समझौता करते हैं, तो हम एक असुरक्षित और अन्यायपूर्ण समाज की नींव रखेंगे। आवश्यक है कि न्याय केवल न्यायालयों की प्रक्रिया न रहे, वह जनविश्वास का प्रतीक बने। एक बड़ा सवाल है कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा कैसे बना रहे? इसके लिये जरूरी है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी हो, आरोपों की पुष्टि डिजिटल और वैज्ञानिक सबूतों से हो। अदालतें किसी दबाव, राजनीतिक प्रभाव या जनभावना से परे निर्णय लें। न्याय में देरी भी अन्याय है, लेकिन जल्दबाजी में न्याय भी गलत निर्णय की आशंका बढ़ाता है। सभी मामलों में उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनरावलोकन की व्यवस्था रहे। निचली अदालते हो या सर्वोच्च अदालते- न्यायिक फैसलों का बदलना न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता के लिये गंभीर चुनौती है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें निचली अदालतों में दिये गये मौत की सजा को ऊपरी अदालतों ने बदल दिया। जांच में खामियों, गवाही में कमी और कमजोर सबूतों के चलते ऊपर की अदालतों में केस खारिज होते हुए बार-बार देखे गये हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक आरोपी की मौत की सजा को खारिज करते हुए कहा कि 'जब दांव पर इंसानी जिंदगी लगी हो और उसकी कीमत खून हो, तो मामले को पूरी ईमानदारी से देखा जाना चाहिए।' दुर्भाग्य से मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट की जांच में इस भावना का सही से पालन नहीं किया गया। इस मामले में सभी आरोपियों का बरी हो जाना न केवल न्याय प्रक्रिया पर बल्कि जांच एजेंसियों पर सवाल पैदा करता है। प्रश्न है कि अगर 12 लोग निर्दोष थे तो इतने बरसों तक आतंकी होने का दाग लिए जिल्लत की जिंदगी क्यों जीते रहे? अगर ये दोषी थे तो जांच इतनी कमजोर क्यों हुई? यह केस निचली अदालतों के कामकाज के तरीकों पर भी बड़ा सवालिया निशान है। सबूतों को लेकर इतने संदेह थे, लेकिन निचली अदालत ने उन पर गौर नहीं किया। यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी न्याय प्रक्रिया की विसंगति ही है। यह पहला मामला नहीं, जहां जांच में खामियों, गवाही में कमी और कमजोर सबूतों के चलते ऊपर की अदालतों में केस खारिज हो गया हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते तीन लोगों की मौत की सजा रद्द करते हुए उन्हें हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था। पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने भी 2011 में हुई दोहरी हत्या और रेप के आरोपी को छोड़ने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने जांच में गंभीर कमियां गिनाई थीं। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि झूठे मुकदमों की वजह से जिन्हें लंबा समय जेल में बिताना पड़ा है, उन्हें मुआवजा देने के लिए कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। अब मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार लोकल ट्रेन बम धमाके में आरोपियों को निर्दोष छोड़ने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की है। देश उम्मीद करता है कि इस बार तथ्यों को सही ढंग से रखा जाएगा। यह केवल एक केस नहीं, न्याय व्यवस्था पर आम लोगों के यकीन का मामला है। भारत में न्याय प्रणाली पर आम धारणा है कि पुलिस और अदालतें लोगों की जिंदगी को तबाह कर देती हैं, वर्षों लम्बी न्याय प्रक्रिया झेलने के बाद भी लोगों को समुचित न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है, न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी आदर्श न्याय व्यवस्था में आम व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिये।

> पीडित परिवारों के साथ-साथ जन-जन को आहत किया था। 7 जगहों पर हुए इन धमाकों में 187 निर्दोष लोगों की जान गई और 824 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। लेकिन इन बम धमाके को लेकर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कोर्ट ने विशेष मकोका अदालत की ओर से 12 अभियुक्तों को दी गई सजा को गैरकानूनी करार दिया। इन सभी आरोपियों का बरी हो जाना सवाल के साथ-साथ चिन्ता भी पैदा करता है। इसीलिये करीब 19 साल बाद आए अदालत के इस फैसले को लेकर न केवल कानूनी दायरे में, बल्कि सामाजिक व नैतिक दृष्टिकोण से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

देश दुनिया से

राजस्व विभाग के दावे और किसान

एक शायर की निम्न पंक्तियां राजस्व विभाग की भ्रष्ट व्यवस्था की दुखद अभिव्यक्ति हैं, और लगता है कि उसने भी जरूर व्यक्तिगत तौर पर इसके दंश झेले होंगे। 'जिस जमीन को समझते हो तुम अपनी मलकीयत मियां, महकमा माल के हाकिमों और वकीलों का मुकद्दर है वो।' हम मानते हैं कि जर, जोरू और जमीन ही हर विवाद की जड़ है। फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि जिस भी व्यक्ति का निजी जमीन से थोड़ा सा भी संबंध है, वह राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली से भली प्रकार परिचित है। विभाग में अच्छे और ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन उनकी सुनता कौन है? मु_ी भर शातिर लॉबी सब पर भारी है। भू-माफिया, शातिर ग्रामीण और भ्रष्ट कर्मचारी लॉबी ने 90 फीसदी लोगों की नाक में दम कर रखा है। पुलिस और प्रशासन पर इनकी पूरी पकड़ है। ऊपर से राजनेताओं का इनके सिर पर वरदहस्त होता है। ये लोग कुछ भी करें, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न्याय व्यवस्था की कछुआ चाल को देख कर उससे न्याय की अपेक्षा रखना बहुत बड़ी भूल है। दशकों से न्यायालयों में केस लंबित पड़े हैं। वकीलों के वारे-न्यारे हैं। भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना खतरे से खाली नहीं है। अन्याय का प्रतिकार कुर्बानी मांगता है जो सबके वश की बात नहीं है। फिर वह इश्तामाल हो, बंदोबस्त हो या वर्तमान मुहाल की व्यवस्था, सबने मिलकर असमर्थ लोगों का कचूमर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पीड़ित लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला और न ही निकट भविष्य में मिलने की कोई उम्मीद है। पता नहीं हमें क्या हो गया है। लगभग सभी का फोकस धन-दौलत बटोरने पर है। और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और यही हमारा दुर्भाग्य है। 1970 के दशक में हरसौर (बड़सर) के एक गांव में इश्तामाल की प्रक्रिया शुरू हुई। सुरा और सुंदरी के दौर में चाम के दाम चलने लगे। चार कोस तक तक मुर्गा प्रजाति लुप्त हो गई। यौन शोषण के विरुद्ध नारी शक्ति प्रचंड हो गई जिसने एक गरदावर को पीट-पीट कर मृत्यु दंड दे दिया। गनीमत यह रही कि घर जाकर जिंदगी और मौत से जूझते हुए कई दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई। वास्तव में यह जन-साधारण के विद्रोह की परिणति थी। कालांतर में एक पंजाबी गरदावर की प्रतिनियुक्ति हुई। रंजिश और खुंदस के चलते वह दिवंगत गरदावर से भी आगे निकल गया क्योंकि शातिर लॉबी उसके समर्थन में खड़ी थी जिसने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया। परिणति यह रही कि सीमा पर बुर्जियां संदिग्ध, रास्ते बस्तियों तक नहीं पहुंचे। वर्तमान सडक़ किसी की मलकीयत है और जो कागजों में सडक़ है, वहां किसी ने फसल बीजी है और किसी ने निर्माण कर दिया है। लगता है कई पीढियां कोर्ट में ही अपनी जिंदगी गुजार देंगी। जहां तक बंदोबस्त का सवाल है, रही सही कसर उसने निकाल दी है। करमों से मीटर बनाते समय पांच से दस मीटर की कमीबेशी साधारण सी बात है। किसी के रकबे की चौड़ाई 11 करम से 16 मीटर की बजाय 20 मीटर कर दी गई और रकबा बढ़ जाने के डर से लंबाई की भुजाओं से 5 से 10 मीटर कम कर दिए गए। ऐसा एक नहीं, अनेक खसरा नंबरों में हुआ है। बाजार में तीन करम की चौड़ाई में बनी दुकानों को केवल चार मीटर दिए गए। पड़ोसी ने इसका लाभ उठा कर निशानदेही लेकर 22 मीटर लंबी जमीन पर कब्जा करके तीन मंजिलें खड़ी कर दी। स्थानीय पंचायत ने कहा- निशानदेही लेकर निर्माण हुआ है, इसमें अतिक्रमण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बाजारों और बस्तियों में करमों के हिसाब से बने भवनों को पूर्व स्थिति के आधार पर मीटर दशमलव में लिखे जाने चाहिए, यह बहुत ही संवेदनशील मसला है। हैरत की बात है कि एक अदद दुरुस्ती के लिए वर्षों का समय और हजारों रुपए वकीलों की फीस लगती है। जिस बेचारे किसान की पंद्रह-बीस दुरुस्तियां बकाया हैं, उनकी दुरुस्ती के लिए उसकी उम्र भी कम पड़ जाएगी। गलती एक पटवारी की और उसकी सजा व्यस्तताओं से घिरे किसान को ताउम्र भुगतनी पड़ती है। वाह री व्यवस्था। किसान की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई होगी। दुरुस्ती की प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए कि किसान को पता ही न चले और दुरुस्ती हो जाए। सरकारें राजस्व प्रणाली में बड़े सुधारों का ढिंढोरा पीटती हैं। लेकिन धरातल पर व्यवस्था टस से मस नहीं होती। इतने में सरकारें ही बदल जाती हैं। दशकों से तकसीम के मामले लंबित पड़े हैं। अपीलों के निपटारे में वर्षों लग जाते हैं। तहसील से लेकर एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर, बंदोबस्त अधिकारी, डिवीजनल कमिश्नर, एफसी, इसके अतिरिक्त ज्यूडीशियरी के भी हाई कोर्ट तक कई पड़ाव हैं। सामर्थ्यवान और शातिर लोग जन साधारण को उपरोक्त सभी पड़ावों तक घसीटते हुए उसका दम तोड़ देते हैं। क्योंकि 'समरथ को नांहि दोष गोसाईं।' मैंने ऊपर भी कहा कि उपरोक्त अपीलों के निपटार में वर्षों लग जाते हैं। और इस दौरान अनेक लोगों का निधन भी हो जाता है और तकसीम की गाड़ी वहीं पार्क हो जाती है। इतने में जमाबंदियां बदल जाती हैं। फिर तकसीम कैसे होगी। दफ्तरों और फील्ड में निरंतर स्टाफ की कमी के चलते दैनिक प्रक्रिया ही विभाग के गले की फांस बन गई है। फिर भूतकाल में हुई बंदोबस्त, इश्तामाल और मुहाल में हुई धांधलियों, त्रुटियों और ढेर सारी अपीलों का निपटारा कब और कैसे होगा। संप्रति सभी असमंजस में हैं। ईश्वर सद्बुद्धि दे। वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मेरा ऐसा विश्वास है कि निकट भविष्य में किसी न किसी दिव्य विभूति का अवतरण अवश्य होगा, जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सारी की सारी व्यवस्था को बदल कर रख देगा।

आप का नजरिया

जाति जनगणना : भारत में सामाजिक न्याय की पुनर्परिभाषा

सामाजिक न्याय की पुनर्परिभाषा इंशा वारसी एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को मंज़ूरी दे दी है, जो आज़ादी के बाद बंद हो चुकी एक बड़ी प्रथा की वापसी का प्रतीक है। समाज सुधारकों, विद्वानों और नीति निर्माताओं द्वारा लंबे समय से मांगे जा रहे इस पैसले की देश में समानता को बढ़ावा मज़बूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में सराहना की जा रही है। ऐसे समय में जब समावेशी विकास राष्ट्रीय विमर्श का वेंद्र बिदु है, जाति जनगणना आँकड़ों पर आधारित नीति निर्माण के एक ऐसे युग की शुरुआत का वादा करती है जो वास्तव में भारत के जटिल सामाजिक ताने-बाने को दर्शाता है। जाति जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना प्र्वरिया के एक भाग के रूप में किसी व्यक्ति की जातिगत पहचान पर आँकड़ों का व्यवस्थित संग्रह है। इसका उद्देश्य विभिन्न जाति समूहों के सामाजिक-आर्थिक वितरण की सटीक और विस्तृत समझ हासिल करना है, जिससे सरकार सबसे वंचितों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियाँ बना सके। ऐतिहासिक रूप से, 1931 तक औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जाति संबंधी आँकड़े नियमित रूप से एकत्र किए जाते थे। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद, जाति गणना अनुसूचित जातियों (एणे) और अनुसूचित जनजातियों (एऊे) तक ही सीमित थी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (छ्वे) और अन्य को व्यापक राष्ट्रीय आँकड़ों से बाहर रखा गया था। इस कमी को पूरा करने का अंतिम प्रयास, 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एण्ण), आंकड़ों की विसंगतियों और अविश्वसनीयता से प्रभावित रही, जिसका मुख्य कारण एक मानक जाति सूची का अभाव था। भारत ने ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक वादे किए हैं, लेकिन विश्वसनीय जाति आँकड़ों के बिना, सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ अक्सर अँधेरे में ही चलती हैं। वर्तमान में, छ्वे के लिए आरक्षण नीतियाँ 1931 की जनगणना के अनुमानों पर आधारित हैं, जो छ्वे की जनसंख्या को 52™ बताती हैं। हालाँकि, राज्यस्तरी य सव्रेक्षण, जैसे कि बिहार का 2023 का जाति सव्रेक्षण, दर्शाता है कि छ्वे और सबसे पिछड़े वर्ग राज्य की जनसंख्या का 63™ से अधिक हिस्सा हैं। इस तरह के निष्कर्ष कल्याणकारी लाभों और आरक्षणों के समान वितरण को सुनिाति करने के लिए एक अदृातन राष्ट्रीय जाति डेटाबेस की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने एसईसीसी 2011 की कमियों को दूर करते हुए एक बेहतर गणना पद्धति की पुऱजोर वकालत की है, जहाँ खुली जाति रिपरेटिंग के परिणामस्वरूप 46 लाख से ज़्यादा अलग-अलग प्रविष्टियाँ और 8 करोड़ से ज़्यादा त्रुटियाँ हुईं। आगामी जाति जनगणना का उद्देश्य डेटा संग्रह की एक अधिक व्यवस्थित और सत्यापन योग्य प्रायिा के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना है। पहचान सत्यापन के लिए आधार को जोड़ना, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और छंटाई और वगाकरण के लिए एआई उपकरणों का लाभ उठाना इस प्रायिा की विश्वसनीयता सुनिाति करने के प्रस्तावित उपायों में से हैं। केवल एक संख्यात्मक प्र्वरिया से कहीं अधिक, जाति जनगणना के सामाजिक समता और शासन पर गहरे प्रभाव हैं। विभिन्न समुदायों के वास्तविक जनसांख्यिकीय वितरण को उजागर करके, यह न्यायमरूति रोहिणी आयोग की सिफारिश के अनुसार, ओबीसी के भीतर पिछड़े समूहों के उप-वगाकरण की अनुमति देता है। यह सुनिाति करता है कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचितों तक पहुँचे, न कि प्रमुख उपसमूहों द्वारा एकाधिकार कर लिया जाए। इसी प्रकार, सटीक जातिगत आँकड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व को पुनर्संतुलित करने और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज़ देकर लोकतंत्र को मज़बूत करने में मदद कर सकते हैं। इस कदम के महत्व को भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 340 राज्य को पिछड़े वर्गो की पहचान करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने का अधिकार देता है, और जाति जनगणना इसी अधिदेश के अनुरूप है। यह अनुच्छेद 15 और 16 के उद्देश्यों को प्रतिध्वनित करता है, जो भेदभाव का निषेध करते हैं और अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। हालाँकि, विश्वसनीय आँकड़ों के बिना, इन संवैधानिक विचारों के प्रतीकात्मक संकेतों में सिमट जाने का खतरा है। हालाँकि यह चिता जताई गई है कि जातिगत जनगणनाएँ जातिगत पहचान को मज़बूत कर सकती हैं या राजनीतिक शोषण का साधन बन सकती हैं, ऐसे जोखिमों को पारदशा, नैतिक और न्यायसंगत कार्यान्वयन के माध्यम से कम किया जा सकता है। जातिगत जनगणनाओं को राजनीतिक के बजाय विकासात्मक साधन के रूप में उपयोग करने से वे समावेशी विकास के उत्प्रेरक में बदल सकती हैं। निगरानी तंत्र, कानूनी सुरक्षा उपाय और नीति मूल्यांकन को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिाति हो सके कि आँकड़े केवल सामाजिक न्याय की सेवा करें, चुनावी अंकगणित की नहीं।

कुछ अलग

शादी का नया उपन्यास

शादी का एक नया उपन्यास और बहुपति प्रथा का विन्यास सिरमौर में हो रहा है। डा. वाईएस परमार के शोध में उस समय उफान आया जब सिरमौर के दो भाइयों प्रदीप व कपिल नेगी ने कुन्हाट गांव की एक बेटी सुनीता से शादी रचा ली। जाहिर है इस प्रथा और परंपरा की गवाही में सैकड़ों लोग जुटे और प्रचार की सीमा को लांघता यह विवाह बहस का मुद्दा बन गया। बहस प्रथा के बाहर, संविधान के साथ और आधुनिकता के बोध में यह है कि क्या स्त्री स्वाभिनान, संस्कृति के परिचालन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता में आज भी उन्हीं मान्यताओं की बंधुआ है, जो उसे एक निश्चित सांचे में रखती हैं। पत्नी को संपत्ति मान लेना न्यायसम्मत नहीं हो सकता। न औरत आर्थिक मशीन है और न ही भूमि के रिकार्ड की शिला। आखिर ऐसी शादियां बचा किसे रहीं। जमीन की हिस्सेदारी या परंपराओं के स्वनिर्धारित उसूलों को। बेशक तीन लोगों की सहमति से इस शादी की वैचारिकी को सामाजिक समर्थन मिल जाए या तारीफ यह हो कि दो भाई अपने समुदाय की ताजपोशी में एक सेहरा-एक पत्नी हो गए, लेकिन इस घटनाक्रम ने देश और प्रदेश की तस्वीर में एक चुनौती परोस दी है। कल अगर परंपरावादी समाज लौटकर देश के हर हिस्से में प्राचीन मान्यताओं को जिंदा रखेगा, फिर हर तर्क के तीरों से बंधे हम ही होंगे। मसलन जिन पोथियों में पढ़ कर दो पति एक पत्नी की कहानी में अमर होने लगे, वहां पत्नी का पुनः सती होना भी नागरिक समाज को अपना गौरव खोज लाएगा।

दृष्टि कोण

अतिवृष्टि की बाढ़ से घिरा जनजीवन

जब से ऋतुचक्र बिगड़ा है तब से वर्षा का वर्षण भी अनिश्चित हो चुका है। इसी वर्षा ऋतु से पहले चारों ओर अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ ने जनजीवन के लिए मृत्यु से लेकर अनेक अन्य संकट उत्पन्न कर दिए हैं। पंचांग तथा वार्षिक अंकपत्र के अनुसार श्रावण मास अब कुछ दिन पूर्व ही आरंभ हुआ है, किंतु अत्यधिक वर्षा के कारण देश के अधिसंख्य प्रांत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के कई प्रांतों में भी बाढ़ की स्थितियां-परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। मई के अंत से लेकर पूरे जून माह तक राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम में अनिश्चित, अनियंत्रित तथा उथल-पुथल मचाने वाली वर्षा ने जनजीवन को संकट में डाल दिया था। और अब जुलाई के पहले पंद्रह दिनों में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। अप्रैल के बाद अब सावन के आगमन तक देश में बादल फटने, बिजली गिरने तथा अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया इत्यादि देशों में भी अत्यधिक वर्षा के कारण आई जलप्रलय में कई सौ लोग मारे गए हैं। नगर, उपनगर, बड़े-बड़े आवासीय क्षेत्र विशाल जलराशि में डूबे हुए हैं। लाखों-करोड़ों रुपए मूल्य की व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संपत्तियां-परिसंपत्तियां नष्ट हो चुकी हैं। मृतकों के परिवार वालों के सामने अन्न-जल के संकट के साथ-साथ आवास, आजीविका और सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा की समस्याएं भी

खड़ी हैं। वर्षा ऋतु के बीतने तक उनका दैनिक जीवन बहुत अधिक कष्टकारी बना रहेगा। यह परिस्थिति प्राकृतिक प्रतिकूलताओं तथा जलवायु असंतुलन की पुनरावृत्ति के कारण गत तीस-चालीस वर्षों से हरेक वर्ष अधिक भयंकर रूप में उत्पन्न हो रही है। बाढ़ के बहते हुए पानी तथा विशाल क्षेत्र में ठहरे हुए कीचड़-गाद-गंदगी से युक्त पानी के कारण अकल्पनीय समस्याएं होती हैं। प्रकार-प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। रहन-सहन, भोजन, पेयजल, आजीविका, विद्यालय, शिक्षा, काम-धंधे, व्यवसाय, नौकरी, सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है। अतिवृष्टि तथा बाढ़ के उपरांत निरंतर आकार लेने वाली जलजनित समस्याओं का निदान कुछ दिनों, सप्ताहों अथवा माहों में नहीं हो पाता। ऐसी समस्याएं वर्षोंवर्ष बनी रहती हैं तथा समस्याग्रस्त लोगों के जीवन को अकल्पनीय बुराइयों के अधीन करके भयंकर ढंग से असुरक्षित कर देती हैं। भारत जैसे देश में जहां भूक्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर यूरोपीय देशों के बराबर अथवा उनसे भी विशाल 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश विद्यमान हैं तथा पूरे विश्व में जिस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, वहां अतिवृष्टि की बाढ़ द्वारा सामान्य लोगों का जीवन किस सीमा तक प्रभावित होता होगा, इसका आभास बाढ़ से घिरे सामान्य लोगों के साथ रहकर ही हो सकता है। ऐसी स्थितियों-परिस्थितियों से घिरे लोगों की जीवन-असुरक्षा अत्यंत भयाक्रांत होती है। इस लेखक ने उत्तराखंड के एक जनपद मुख्यालय से कुछ दूर स्थित एक लघु उपनगर में रहते हुए निरंतर दो वर्षों तक वर्षा की अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ में अपने आवास तथा उसके चहुंओर के क्षेत्र को निरुपाय होकर केवल और केवल ईश्वर के भरोसे सुरक्षित होने की प्रार्थना करते देखा व भोगा है। ऐसी अतिवृष्टि, ऐसी बाढ़, ऐसी आपदा से प्रत्यक्ष प्रभावित लोग भाग्य के बूते ही जीवित रह पाते हैं। जिनका भाग्य निर्बल होता है, वे असुरक्षित पर्यावास के उजडऩे-बहने के कारण मृत्यु के मुख में समा जाते हैं। जीवित लोग भी केवल अपने शरीर के साथ जीवित होते हैं। उनका आवास, जीवनचर्या के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुएं, सभी कुछ आपदा में नष्ट हो जाता है। उनके लिए जीवन में प्रत्येक आवश्यकता, सुविधा तथा वस्तु को पुनः क्रय करके संग्रहीत करना अत्यंत कठिन हो जाता है।

आज का राशिफल

मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ

आज दिल और दिमाग को शान्त रखना होगा जो भी काम हाथ पर आए उसे तुरंत करते जाए .आज आपको अपने नौकरी या बिजनेस के टारगेट पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए. एकाग्रता से काम निपटाने की कोशिश करें. नए व्यक्ति से मुलाकात या दोस्ती होने के योग हैं. परिवार के कुछ लोगों से अपने कामकाज और प्लानिंग शेयर कर सकते हैं.परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा,कोई आर्थिक कमजोरी हैं तो परिवार की मदद से दिक्कतें दूर होंगी ।

वृषभ – इ,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो

आप को घर के बुजुर्गों को पूरा समय देना चाहिए बच्चों के साथ खेल कूद मे समय बिताना चाहिए आर्थिक रूप से दिन शुभ है और कुछ महत्वपूर्ण सौदे भी हो सकते है. मित्रों के साथ साझेदारी कारोबार में प्रवेश कर सकते हैं. कोर्ट–कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी . पेशेवर रूप से आप लोकप्रियता और प्रशंसा हासिल करेंगे. आप के नये नये प्रयोग वित्तीय लाभ कराएंगे . व्यक्तिगत संबंधों में खुशी और आनंद प्राप्ति होगी. आप का समय सामाजिक कार्य मे व्यतीत होगा पारिवारिक जीवन यथावत रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मिथुन – क,कि,कृ,घ,ड़,छ,के,को,ह

रिश्तो की नजदीकियों को नजरअंदाज नही करना चाहिए।आज होने वाले बिजनेस के सौदे आप को फायदे मे लाकर खडा कर देंगें परन्तु मन में चिंता की लहरे उमडती रहेंगी अनेक प्रकार की अनिश्चितता के कारण मानसिक बेचैनी रहेगी. अपने उद्देश्यों की ओर शान्ति से बढ़ते रहें अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए बिलकुल उपयुक्त दिन है, क्योंकि आपके पास आराम के कुछ लम्हे होंगे. परिवार के साथ समय बिताना जीवन का सबसे सुखी पल हैं।

कर्क – ही,हु,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो

आप को शरीर मे गजब की उर्जा की जरूरत हैं दुर्गा जी का जप करें दिन ठीक–ठाक रहेगा. आज किसी पर गुस्सा करने से बचें. अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं. भाई–बहनों मे आपसी प्रेम बढेगा रिश्तों में मजबूती आयेगी.परन्तु आपको किस्मत का साथ नही मिलेगा कर्म पर ही भरोसा करना पडेगा. जरूरत से ज्यादा भावुक होना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. आप की कार्यशैली की लोग प्रशंसा करेंगे।

सिंह – म,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे

आप को अपने सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा आप अपनी बुद्धिमानी से सब संभालने की कोशिश करेंगे.छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके आप को आगे बढ़ना चाहिए . जो काम आपको दिया जाएगा, उसे निपटा लेंगे. आप जो भी करेंगे, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी रहेगी. लोग अपनी परेशानियां आपके सामने रख सकते हैं.आप को जरुरतमंदो की सामाजिक तौर पर मदद करनी चाहिए ।

कन्या – टो,प,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो

आज का दिन बहुत उतार–चढ़ाव का रहेगा । कोई भी निर्णय बहुत जल्दबाजी मे करते हैं तो आप मुश्किलों मे गिर सकते है आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. किन्तु आत्मविश्वास और कौशल के बल पर आप विजयी बनेंगे. आप को अपने विरोधियों पर नजर रखना होगा. यात्रा हो सकती है, यात्रा एकदम आरामदायक रहेगी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. अधिक खर्चा भविष्य मे दिक्कतें दे सकता हैं।

तुला – र,री,रू,रे,रो,ता,ति,तू,ते

आज क्रोध पर संयम रखें । मन मे तो दुविधा चलती रहेगी परन्तु संयमपूर्वक दृढनिश्चयी होकर एक निर्णय पर आना पडेगा । किसी के साथ वाद–विवाद या झगड़े में पड़ने से मामला खराब हो सकता है. पारिवारिक चिंता बनी रहेगी. दुष्टजनों से सतर्क रहें. समय अनुकूल है. नई शुरू की परियोजनाएं उम्मीद के मुताबिक़ परिणाम नहीं देंगी. चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में फंसने से बचें– निवेश करने में काफ़ी सावधानी बरतें. आप मीडिया मे कार्यरत हैं तो आज बहुत दिक्कतों के साथ काम पूरा होगा ओवरटाइम भी करना पड सकता हैं।

वृश्चिक – तो,न,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू

आज का दिन सुकून भरा रहेगा. आज पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे. थोड़ी– सी मेहनत करने पर ही मुकाम हासिल होगा कारोबार के लिहाज़ से आज का दिन बेहतर है. आज अपने आसपास के लोगों के इरादे आसानी से समझ जायेंगे. आप उच्चपद पर कार्यरत हैं तो धं लाभ सम्भव हैं आप अपने काम में सामाजिक संपर्कों का फायदा उठाने में सफल हो सकते हैं. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करे जीवन मे रौशनी होगी।

धनु – ये,यो,भ,भी,भू,धा,फा,ढा,भे

आज का दिन उत्साहवर्धक रखेगा । मित्रों की हरेक काम में मदद मिल सकती है. महत्वपूर्ण मामलों पर लोगों से बातचीत का मौका आपको मिल सकता है. आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए. दिनचर्या में कुछ बदलाव भी आपको करने पड़ सकते हैं. दोस्तों के साथ ज्यादा समय बीतेगा. किसी तरहका दबाव या काम का बोझ कम हो सकता है , अपने जीवन साथी के साथ सम्बन्धन मे मधुरता बना रखे जीवन की प्रत्येक तकलीफ आप को खोटी दिखाई देगी।

मकर – भो,ज,जी,खि,खू,खे,खो,ग,गि

आज नये व्यापार का योग प्रबल बन रहा हैं साझेदारी मे भी बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं. आप अपने संपर्को को बढ़ाएंगे और कुछ लाभकारी संपर्क भी स्थापित करेंगे. आर्थिक रूप से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा. आय में वृद्धि होना तय है और आपको आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी मिल सकता है. घरेलू मोर्चे पर सामंजस्य रहेगा और शादी, जन्म या धार्मिक समारोह जैसा कार्यक्रम मनाया जा सकता है.एकाएक यात्रा पर जाना पड सकता हैं दही धनिया का सेवन करके प्रस्थान करें सब मंगल होगा।

कुम्भ – गु,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द

अपनी माता का पूरा सम्मान करें आज्ञा का पालन करें , चरणों को छूकर घर से प्रस्थान करें , आज आप दूसरों के साथ मिलकर कार्य करेंगे. कुछ व्यावसायिक यात्राएं होंगी. आप अध्ययन में गहरी रुचि रखेंगे. सफर के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं है. आर्थिक सुधार होगा और धन आपकी तरफ आएगा. आपके सामने नई चुनौतियां आ सकती हैं. किसी भी तरह के जोखिम वाले काम से सम्हलकर रहें दुर्घटना सम्भव हैं महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें।

मीन – दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची

सुबह जब पूजा मे बैठते हैं उसी समय प्रभु से मन मे प्रार्थना करें आप का समय निर्विघ्न होगा । आज आपका दिन अनुकूल रहेगा. आज किसी काम से आपको बड़ा फायदा हो सकता है. कुछ निजी कामों में भाई का पूरा–पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी से आपको खूबसूरत तोहफा मिल सकता है. आज उन लोगों से बातचीत करने के लिए अच्छा दिन है, जिनसे आपकी मुलाकात कभी– कभी ही होती हैं।

आज का पंचांग

दिनांक : 26 जुलाई 2025 , शनिवार
विक्रम संवत : 2082
मास : श्रावण , शुक्ल पक्ष
तिथि : द्वितीया रात्रि 10:44 तक
नक्षत्र : आश्लेषा सायं 03:53 तक
योग : व्यतिपात रात्रि 04:06 तक
करण : बालव प्रातः 11:00 तक
चन्द्रराशि : कर्क सायं 03:53 तक
सूर्योदय : 05:53, सूर्यास्त 06:51 (हैदराबाद)
सूर्योदय : 06:04 , सूर्यास्त 06:48 (बैंगलोर)
सूर्योदय : 05:55 , सूर्यास्त 06:41 (तिरुपति)
सूर्योदय : 05:46 ,सूर्यास्त 06:41 (विजयवाडा)

शुभ चौघड़िया

शुभ : 07:30 से 09:00
चल : 12:00 से 01:30
लाभ : 01:30 से 03:00
अमृत : 03:00 से 04:30
राहुकाल : प्रातः 09:00 से 10:30
दिशाशूल : पूर्व दिशा
उपाय : उडद खाकर यात्रा का आरंभ करें
दिन विशेष : गण्डमूल चालू है , सिंधारा (श्रृंगार) , चन्द्रदर्शन , श्री स्वामी करपात्री जी जयंती

* पाण्डित्य विषय में सम्पर्क करें *

पं.चिदम्बर मिश्र (टिल्लू महाराज)
हमारे यहाँ पाण्डित्य पूर्ण यज्ञ अनुष्ठान, भागवत कथा एवं मूल पारायण, वास्तुशान्ति, गृहप्रवेश,शतचंडी, विवाह, कुंडली मिलान, नवग्रह शान्ति, ज्योतिष सम्बन्धी शंका समाधान किए जाते हैं
फक्कड़ का मन्दिर, रिकाबगंज, हैदराबाद, (तेलंगाना)
9246159232, 9866165126
chidamber011@gmail.com

झालावाड़ स्कूल हादसे में लापरवाही पर गिरी गाज

महिला प्रिंसिपल समेत चार शिक्षक सस्पेंड, आठ मासूमों की गई जान

झालावाड़, 25 जुलाई (एजेंसियां)। ज़िले के पिपलोदी गांव स्थित सरकारी स्कूल में छत गिरने से हुई 8 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। हादसे की जिम्मेदारी तय करते हुए स्कूल की महिला प्रिंसिपल समेत चार शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए की गई है, क्योंकि लगातार बारिश से जर्जर हो चुकी बिल्डिंग की शिकायतों के बावजूद कोई ऐहतियात नहीं बरता गया।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में राजनीति करने की बजाय लोगों को राहत पहुंचाने की बात करनी चाहिए। हमारे लोगों ने वहां 71 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की है।

पिपलोदी स्कूल में शुक्रवार सुबह जब बारिश हो रही थी, उस वक्त सभी बच्चों को खुले मैदान में प्रार्थना कराने की बजाय एक पुराने कमरे में बैठा दिया गया। कुछ ही देर बाद कमरे की छत भरभराकर गिर गई। 35 बच्चे मलबे में दब गए। 8 बच्चों की जान चली गई, जबकि 27 घायल हो गए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। स्कूल की महिला प्रिंसिपल और तीन अन्य शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि स्कूल की बिल्डिंग पहले से जर्जर थी, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी गई। लापरवाही का यह रवैया 8 मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ गया।ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद न तो शिक्षा विभाग ने ध्यान दिया, न ही प्रशासन ने निरीक्षण किया। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया है।

झालावाड़ स्कूल हादसे में पीड़ित परिवार ने कहा

प्रशासन को दी थी शिकायत, किसी ने नहीं दिया ध्यान

झालावाड़, 25 जुलाई (एजेंसियां)। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पलोदी गांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गांव के सरकारी स्कूल की छत गिरने से करीब 20 बच्चे घायल हो गए हैं। इस हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत की पुष्टि की गई है।

इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में मातम पसर गया है और प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गया है। यह घटना सुबह उस समय घटी जब विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद बच्चे हाल में बैठे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के वक्त 35–40 बच्चे वहां उपस्थित थे, तभी अचानक स्कूल की छत गिर गई। घटना के बाद स्कूल में चीख–पुकार मच गई और गांव में अफरा–तफरी फैल गई। घटना के तुरंत बाद गांववाले दौड़कर स्कूल पहुंचे और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया गया और बच्चों को बाहर निकाला गया। चार बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि तीन बच्चों ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल और मनोहरथाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि इस हादसे में कुल 7 बच्चों की मृत्यु हुई है और 20 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। नौ बच्चों का इलाज मनोहरथाना अस्पताल में जारी है, जबकि 11 बच्चों को झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।इस हादसे में जान गंवाने वाले तीन बच्चों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं, जबकि चार बच्चों के शव मनोहरथाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की इमारत लगभग 50 साल पुरानी है और उसकी हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी थी।

झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षामंत्री ने जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ किए मंजूर

भरतपुर, 25 जुलाई (एजेंसियां)। झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद शिक्षा मंत्री ने तत्काल अपना भरतपुर दौरा रद्द कर झालावाड़ के लिए रवाना हो गए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन भवनों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मदन दिलावर दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भरतपुर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें झालावाड़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छत गिरने की जानकारी मिली, उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से संक्षिप्त बातचीत की और दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद वे तत्काल झालावाड़ रवाना हो गए।

मंत्री ने कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। उन्होंने भरोसा

दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री के इस निर्णय को जनता के बीच संवेदनशीलता और त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। आमजन का मानना है कि सरकार ने हादसे को गंभीरता से लिया है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की दिशा में तत्परता दिखाई है।

झालावाड़ हादसे ने एक बार फिर से प्रदेश के स्कूल भवनों की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की ताजा कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि अब स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों की जान की हिफाजत सुनिश्चित की जा सकेगी।

जर्जर सार्वजनिक भवनों का निरीक्षण कर त्वरित रूप से शुरू किए जाएं मरम्मत कार्य : भजनलाल शर्मा

जयपुर, 25 जुलाई (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर झालावाड़ जिले के पीपलोदी ग्राम के सरकारी स्कूल में हुए दुखद हादसे के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने समस्त जिलों के जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यकारी एजेंसी, समसा एवं आरएसआरडीसी सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाए जाएं। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए, जो 5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीपलोदी हादसे से हम सब दुखी हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में जिन भवनों की मरम्मत का काम किया गया है, उनकी भी जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित करें तथा कमी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर और

उपयोग के लिए असुरक्षित पाए जाने पर भवनों को तुरंत खाली करवाया जाए और प्रभावितों का अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाए। उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कर उनके लिए अस्थायी कक्षाओं का संचालन सामुदायिक भवनों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर किया जाए। उन्होंने इसके लिए शिक्षा विभाग को तुरंत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2024–25 में प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं और 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट घोषणाएं की थी। साथ ही, बजट 2025–26 में भी भवनविहीन व जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए 375 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों के लिए 28 करोड़ रूपये दे रहे हैं। साथ ही डांग, मगरा, मेवात क्षेत्र विकास योजना, एमएलए लेड, एमपी लेड और जनजाति क्षेत्र विकास योजनाओं की राशि से भी ये कार्य करवाए जा सकते हैं।

यदि शिक्षा विभाग सजग होता तो ये मासूम आज हमारे बीच होते : वसुंधरा राजे

झालावाड़, 25 जुलाई (एजेंसियां)। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ जिले में हुए स्कूल भवन हादसे को बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक बताते हुए कहा कि यह घटना प्रशासन की गंभीर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा विभाग पहले ही उन स्कूलों को चिन्हित कर लेता जो जर्जर अवस्था में हैं और बच्चों को किसी सुरक्षित भवन में स्थानांतरित कर देता, तो आज सात मासूम बच्चे काल का ग्रास नहीं बनते।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे परिवार के सात बच्चों को भगवान ने हमसे छीन लिया। यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी मिली, मैं तत्काल सांसद दुष्यंत सिंह जी के साथ दिल्ली से यहां रवाना हो गई।

राजे ने शिक्षा विभाग से आग्रह किया कि पूरे प्रदेश के स्कूल भवनों का तत्काल सर्वे कराया जाए और जो भी भवन खतरनाक स्थिति में हैं, उन्हें तुरंत खाली कराकर बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि पुराने, जर्जर भवनों को गिराकर नए भवनों का निर्माण कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ मासूम जिंदगियों को छीनती हैं, बल्कि बच्चों और अभिभावकों के मन में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करती हैं।

जींद और रोहतक की वारदातों से प्रदेश में दहशत का माहौल : भूपेंद्र सिंह

चंडीगढ़, 25 जुलाई (एजेंसियां)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी सरकार के दौरान प्रदेश का कोई बाशिंदा सुरक्षित नहीं है। विधायक, पूर्व विधायक से लेकर पुलिस तक, सभी बदमाशों की गोलियों, हमलों और धमकियों के शिकार हो चुके हैं। इस सरकार के दौरान खुद सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं का परिवार तक सुरक्षित नहीं है। इसका ताजा उदाहरण जींद में देखने को मिला। यहां बीजेपी नेता के जवान बेटे की सरेराह, चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। ऐसे में आम आदमी की कितना असुरक्षित होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है।

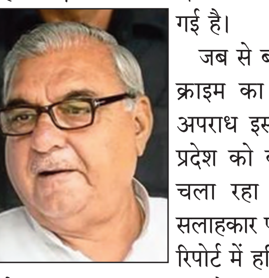

हुड्डा ने कहा कि जींद से पहले रोहतक में एक महिला के टुकड़े–टुकड़े करके मार डाला गया। जींद और रोहतक की वारदातों से पूरे हरियाणा में दशहत का माहौल है। क्योंकि प्रदेश सरकार लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने में बार–बार नाकाम साबित हो रही है। हत्या, लूट, डकैती और फिरौती की वारदातें लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गई हैं और ऐसी गंभीर वारदातों को नजरअंदाज करना सरकार आदत हो गई है।

जब से बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता संभाली है, क्राइम का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। अपराध इस कदर बेकाबू हो चुका है, मानो प्रदेश को कोई सरकार नहीं, बल्कि माफिया चला रहा है। खुद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2022 में एक साल के भीतर प्रदेश में 1020 हत्याएं यानी रोज 3 हत्याएं हुई। 2022 के दौरान ही हरियाणा में 1786 रेप की वारदातें हुईं यानी रोज 4–5 रेप हुए।

भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते हरियाणा से चावल उद्योग का हो रहा है पलायन: सैलजा

चंडीगढ़।, 25 जुलाई (एजेंसियां)। हरियाणा में भाजपा सरकार की विफल और जनविरोधी औद्योगिक नीतियों के कारण प्रदेश से उद्योगों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, जिससे प्रदेश को दोहरी क्षति हो रही है, एक ओर युवाओं का रोजगार छिन रहा है और दूसरी ओर सरकार को भारी राजस्व घाटा उठाना पड़ रहा है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में हरियाणा से 90 से अधिक चावल मिलें मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो चुकी हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और प्रदेश के औद्योगिक भविष्य पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है। सरकार को अपनी नीतियों पर चिंतन और मंथन करना होगा, हाल ही में बिजली की दरों में की गई वृद्धि से अनेक उद्योग पलायन की तैयारी में हैं।

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि देश में चावल निर्यात में हरियाणा की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत रही है जो अब घटकर 40 प्रतिशत रह गई है। इतना ही नहीं एक ओर जहां हर साल प्रदेश को कम से कम 100 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा वहीं हर साल 15 से 20 हजार रोजगार भी कम हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे स्थान पर पहुंची : सैनी

चंडीगढ़, 25 जुलाई (एजेंसियां) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के संबंध में एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री सैनी ने यह जानकारी आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान केशाऊ बांध सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा, राज्य में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया गया । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीव्र गति से कार्य किया है। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से उठाकर चौथे स्थान तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा है।

मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि सीईटी परीक्षा को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में 26 व 27 जुलाई को लाखों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह

भी कहा कि हरियाणा पुलिस में शीघ्र ही कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए भी अधिकारियों को सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से गरीबों, किसानों, गांवों और शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिससे देश के हर नागरिक का जीवन सरल, सुगम और सशक्त बन रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हो रहा तेज़ विकास विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 19 किस्तों के माध्यम से लाखों किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इन योजनाओं के माध्यम से देश के लगभग 25 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बिहार दौरे के दौरान एक कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बिहार प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक–एक पंचायत में 700 से 900 तक मकान बनाकर गरीबों को प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, देशभर में गरीब परिवारों को हर माह राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं, जो गरीबों की चिंता ईमानदारी से करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की स्थिति को बदतर बना दिया था , जिसके कारण वहाँ की जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर यमुना नदी की स्वच्छता सहित कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर समन्वित रूप से कार्य कर रही है।

शुभ लाभ
खबरें जो सोच बदल दे
हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

26वीं वाहिनी पीएसी के लिए 11 मंजिला बैरक टावर का लोकार्पण

कानून व्यवस्था का मानक पेश कर रहा उत्तर प्रदेश : योगी

गोरखपुर, 25 जुलाई (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश आठ वर्ष पहले तक दंगा प्रदेश के रूप में बदनाम था, गुंडों-माफिया से तबाह था, वही उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था का मानक पेश कर रहा है। दंगामुक्त और गुंडामुक्त उत्तर प्रदेश आज अनुशासित और उत्सव प्रदेश की पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने 26वीं वाहिनी पीएसी परिसर में 11 मंजिला बैरक टावर तथा 30 बेड के हॉस्पिटल का लोकार्पण किया।

सीएम योगी ने कहा कि आज कोई भी बाहरी व्यक्ति कानून व्यवस्था के मामले में यूपी पर हंस नहीं सकता, उंगली नहीं उठा सकता। यूपी का नौजवान आज कहीं भी जाता है तो सम्मान पाता है जबकि आठ वर्ष पहले यहां के नौजवान को यूपी के नाम पर एक कमरा तक नहीं मिलता था। यूपी के नाम पर बाहर के लोगों के सामने डरावना दृश्य होता था। आज इन सबसे उबरकर नए भारत का नया उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की नजीर प्रस्तुत करने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेना देश की बाह्य सुरक्षा का दायित्व संभालती है तो आंतरिक मामलों और कानून व्यवस्था के लिए सिविल पुलिस की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर की पुलिस, लगातार पुलिसकर्मियों की कमी और अवस्थापना सुविधाओं की चुनौतियों से जूझ रही थी। आठ साल पहले यहां शांति की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, यह सपना था। तब पुलिस के लाखों पद खाली थे लेकिन नियत सही न होने से तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती थीं। कभी भर्ती में खामी तो कभी बेईमानी, भ्रष्टाचार के चलते कोर्ट से रोक लग जाने के चलते नौजवान भटकने को मजबूर थे।

सीएम योगी ने अपनी सरकार के दौरान पारदर्शी पुलिस भर्ती प्रक्रिया की चर्चा करते हुए बताया कि आठ साल में 2 लाख 16 हजार भर्तियां यूपी पुलिस में की गई हैं। इसमें न सिफारिश की गुंजाइश थी और न ही भ्रष्टाचार की। इन भर्तियों में हाल ही में हुई दुनिया की सबसे बड़ी 60244 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ साल पहले उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता केवल तीन हजार की थी। जबकि आज यह कई गुना बढ़ गई है। आज 60 हजार से अधिक प्रशिक्षु प्रदेश के 112 प्रशिक्षण केंद्रों पर एकसाथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के दो माह बाद लखनऊ पुलिस लाइन के निरीक्षण के दौरान जर्जर अवस्थापना सुविधाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि तब पुलिस कार्मिकों के लिए सुविधाओं का काफी अभाव था। इसे देखते हुए उन्होंने हर थाने, पुलिस लाइंस और पीएसी की वाहिनियों में अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। आज इस बात की प्रसन्नता है कि यूपी के हर थाने, पुलिस लाइंस और पीएसी की वाहिनियों में अवस्थापना सुविधाओं का जबरदस्त विस्तार हुआ है। कई जिलों में तो जो सबसे ऊंची मिनारनुमा बिल्डिंग होगी वह यूपी पुलिस के बैरक के रूप में होगी। सरकार एक तरफ अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ पूरी पारदर्शिता से भर्ती प्रक्रिया को सम्पन्न कर रही है।

इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि पुलिस बल का लगातार मनोबल बढ़ाने और हर संसाधन देने के चलते योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए देश ही नहीं विदेश में भी जानी जाती है। यूपी पुलिस में इतनी भर्तियां कभी नहीं हुईं जितनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई हैं। सीएम योगी की ताकतवर सोच से ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। पीएसी के एडीजी डॉ. रामकृष्ण स्वर्णकार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए लोकार्पण की दोनों परियोजनाओं, बैरक टावर और हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अन्य वाहिनियों में भी बहुमंजिला बैरक बनाया जा रहा है। यूपी में पहली बार महिला बटालियन का गठन और बटालियन भवन निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत गोरखपुर, लखनऊ और बदायूं में निर्माण जारी है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस में भर्तियों का नया रिकॉर्ड कायम किया है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है।

अखिल भारतीय संत समिति की घोषणा

प्रभावशाली 1000 हिंदुओं की तैयार होगी सूची

वाराणसी, 25 जुलाई (एजेंसियां)। दुनिया के प्रभावशाली 1000 हिंदुओं की सूची तैयार करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति ने अध्ययन शुरू कराया है। इसकी शुरुआत सतयुग से होगी। सनातन के वैभव को दुनिया को बताने के लिए हिंदू समाज के प्रभावशाली लोगों की सूची तैयार की जा रही है। पहली सूची में सनातन धर्म के एक हजार प्रभावशाली लोगों को शामिल किया जाएगा। प्राचीन काल से वर्तमान तक के सभी प्रभावशाली सनातनी हिंदू इस सूची में होंगे। अखिल भारतीय संत समिति अक्तूबर 2025 में होने वाली संस्कृति संसद में इस सूची को सार्वजनिक करेगी।

अखिल भारतीय संत समिति ने इसके लिए देश भर में शोध आरंभ कर दिया है। पहले चरण में 500 मृत और 500 जीवित हिंदुओं को शामिल किया गया है। संत समिति को हर साल इसे वैश्विक स्तर पर जारी किया जाएगा। इसमें देश ही नहीं विदेश में रहने वाले हिंदू समाज के प्रभावशाली लोगों को भी शामिल किया जाएगा। सूची में हिंदू वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, लेखक के साथ ही समाज पर विशेष प्रभाव डालने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। इस सूची में महाभारत के रचयिता वेदव्यास, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, पंतजलि, आर्यभट्ट, वराहमिहिर के साथ ही गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर और गंगा विज्ञानी प्रो. जीडी अग्रवाल का भी नाम शामिल है। सूची पर अंतिम मुहर सितंबर माह में लगेगी। सूची में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, रबींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रफुल्ल चंद्र रे, जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुजन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाद साहा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉ. बीआर अंबेडकर के नाम प्रमुख हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, हिंदू समाज के गौरवशाली इतिहास और सामर्थ्य को विश्व स्तर पर बताने के लिए यह सूची तैयार कराई जा रही है। हिंदू समाज का देश ही नहीं दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान है। इस सूची के जरिए हम अपने योगदान को पूरे विश्व को बताएंगे कि हमने दुनिया को क्या दिया है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, योग सूत्र के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिलमुनि, न्यास दर्शन के गौतम, एटामिक थ्योरी के दार्शनिक कन्नडा, मीमांसा के जैमिनी, आदि शंकराचार्य, तमिल दार्शनिक थिरुवल्लुअर, पाणिनी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर, चरक, सुश्रूत आदि का नाम शामिल किया गया है।

---

42 साल बाद एक साथ खुले मंदिर और गुरुद्वारा के द्वार

वाराणसी, 25 जुलाई (एजेंसियां)। वाराणसी के जगतगंज इलाके में एक धार्मिक स्थल पिछले 42 वर्षों से बंद पड़ा था, उसे अब दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। यह स्थल एक तरफ सिखों के पवित्र गुरुद्वारे और दूसरी ओर हिंदू समुदाय बड़े हनुमान मंदिर के रूप में श्रद्धा का केंद्र रहा है। 1984 के दंगों के दौरान इस जगह को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नारायण सिंह की मध्यस्थता और दोनों पक्षों की सहमति के बाद अब इसे फिर से खोल दिया गया है। 21 जुलाई को परिसर के दरवाजे पर लगे जंग लगे ताले हटने के बाद सिख और हिंदू समुदाय के लोगों में खुशी की लहर है।

इस जगह का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व दोनों समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार, सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर करीब दो सौ साल पहले जब काशी आए थे, तब वे नीचीबाग क्षेत्र (जहाँ वर्तमान में गुरुद्वारा है) में रुके थे। वे अपने अनुयायियों से मिलने के लिए कई बार जगतगंज भी आए थे। इसलिए यह भूमि सिख समुदाय के लिए पूजनीय मानी जाती है। समय के साथ यहां एक गुरुद्वारा भी स्थापित हुआ। वहीं हिंदू समुदाय द्वारा यहां श्री बड़े हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी। दोनों धार्मिक स्थल कई सालों से अस्तित्व में रहे और लोगों की आस्था का केंद्र बने रहे।

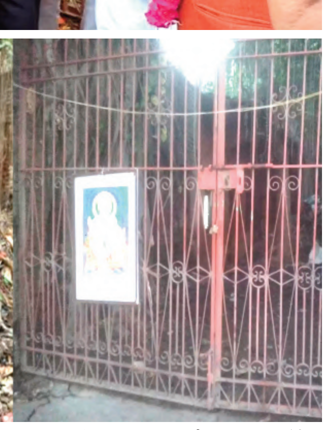

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। जगतगंज में स्थित यह स्थल गुरुद्वारा और मंदिर दोनों के लिए एक स्थान था। इसलिए प्रशासन ने किसी भी सांप्रदायिक तनाव या टकराव को रोकने के उद्देश्य से इस स्थल को सील कर दिया। उस समय मंदिर और गुरुद्वारा दोनों का पूरा तरह से निर्माण नहीं हुआ था। जिले में बढ़ते तनाव को देखते हुए, प्रशासन ने इस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया ताकि कोई हादसा न हो।

समय बीतने के साथ, इस जमीन के मालिक हक और कब्जे को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद गहराता चला गया। जिसके बाद मंदिर प्रबंध समिति और गुरुद्वारा प्रबंध समिति, दोनों ने ही उस जगह को लेकर अपना-अपना दावा किया।

यह विवाद लोकल कोर्ट में पहुंच गया, जहां यह मामला कई दशकों तक लंबित रहा। तीन हजार से साढ़े तीन हजार वर्गफीट भूमि को लेकर चल रहे इस विवाद में समय-समय पर अस्थायी निर्माण होते रहे, जिससे विवाद बढ़ता गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कई कोशिशें हुईं, लेकिन सफल नहीं हो पाईं। इस दौरान धार्मिक भावनाएँ भी गहराती रहीं, जिससे विवाद बढ़ता गया। लगभग दो महीने पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगत सिंह के वंशज और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नारायण सिंह ने एक बार फिर दोनों पक्षों को सुलह के लिए तैयार किया। इसके बाद दोनों पक्षों में कई बार बातचीत भी हुई।

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह प्रक्रिया और तेज हुई। आखिरकार श्री बड़े हनुमान मंदिर समिति के व्यवस्थापक श्याम नारायण पांडे और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार करन सिंह सभरवाल के बीच सहमति बनी। दोनों ने यह तय किया कि भूमि को बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा और दोनों समुदाय अपनी-अपनी आस्था के अनुसार गुरुद्वारा और मंदिर का निर्माण करेंगे। बनारस की संस्कृति एक बार फिर दुनिया के सामने एक आदर्श बनकर उभरी है, जहां इस ऐतिहासिक समझौते के बाद दोनों पक्षों ने अदालत में सुलहनामा दाखिल किया और जिला प्रशासन से जगह को फिर से खोलने की अनुमति मांगी। वाराणसी के अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार की निगरानी में आवश्यक जांच-पड़ताल पूरी करने के बाद 21 जुलाई को ताले तोड़े डाले गए और जगह को दोनों समुदायों के लिए खोल दिया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह अहलूवालिया ने इसे सिख समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि जल्द ही यहां भव्य गुरुद्वारा बनेगा, जहां दुनिया भर से सिख श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे। वहीं मंदिर समिति भी इस जगह पर बड़े हनुमान जी के भव्य मंदिर के निर्माण की तैयारी में है।

धर्मांतरण के ग्लोबल नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक लड़ाई

जलालुद्दीन छांगुर हो या आगरा के जेहादी, सबका होगा हिसाब

लखनऊ, 25 जुलाई (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश में हिंदू बेटियों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे सुनियोजित धर्मांतरण के नेटवर्क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कड़ा प्रहार शुरू हो गया है। हाल के दिनों में बलरामपुर, आगरा और प्रयागराज जैसे विभिन्न जिलों में सामने आई घटनाएं यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि यह केवल छिटपुट आपराधिक प्रकरण नहीं, बल्कि एक गहरी, सुनियोजित और अंतरराष्ट्रीय साजिश है, जो भारत की सनातन संस्कृति और सामाजिक संरचना को भीतर से तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है। योगी सरकार इसे सॉफ्ट टेरर मानते हुए अब निर्णायक कार्रवाई की दिशा में बढ़ चुकी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट चेतावनी सनातन धर्म के विरुद्ध किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा को चरितार्थ करते हुए राज्य पुलिस ने हाल के दिनों में बड़े धर्मांतरण गिरोहों का पर्दाफाश किया है। आगरा से लापता दो बहनों के रहस्यमयी मामले की जांच करते हुए पुलिस ने ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसकी जड़ें छह राज्यों तक फैली थीं। तो बलरामपुर में जलालुद्दीन छांगुर के बहुराष्ट्रीय धर्मांतरण गिरोह की कहानियों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बलरामपुर की घटना में उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ता ने धर्मांतरण गिरोह और अवैध वित्तपोषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की हिरासत ले ली है। एटीएस अवैध वित्तपोषण से खरीदी गई बेनामी सम्पत्तियों का भी पता लगाएगी। एटीएस ने 5 जुलाई को जलालुद्दीन और नसरीन को बलरामपुर में माधपुर गांव से गिरफ्तार किया था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन पर वित्तीय प्रोत्साहन, शादी के प्रस्ताव और दबाव बनाकर कमजोर तबके के लोगों को इस्लाम कबूल कराने का आरोप है. जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। दो अन्य आरोपियों, नवीन उर्फ जलालुद्दीन और महबूब (जलालुद्दीन के बेटे) को अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में ये लखनऊ की जेल में बंद हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके सहयोगियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। लगभग एक एकड़ क्षेत्र में फैले छांगुर और उसके सहयोगी नीतू की सम्पत्तियों पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया था जिसमें अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया था। छांगुर की कोठी करीब एक एकड़ भूभाग में बनी थी जिसमें 2 बिस्वा जमीन सरकारी थी जिस पर अवैध निर्माण किया गया था। इसी मामले में एक आरोपी रऊफ के खिलाफ पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यही नहीं, स्थानीय प्रशासन ने रऊफ के घर को अवैध निर्माण मानते हुए बुलडोजर कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। यह सीएम योगी की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत संगठित अपराधों में शामिल लोगों की अवैध कमाई से अर्जित सम्पत्तियों को ध्वस्त कर उन्हें आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ा जा रहा है।

इसी तरह, आगरा के मामले में पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह सुनियोजित तरीके से हिंदू युवतियों को प्रेमजाल, प्रलोभन, भय, विवाह और बहकावे जैसे हथियारों के माध्यम से फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण कर रहा था। यही नहीं, इनके पास से ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनसे साफ संकेत मिलता है कि इनका संबंध अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी हो सकता है। एक आरोपी के पास से फिलीस्तीन का नक्शा और अरबी में छपे कट्टर इस्लामी विचारधारा वाले पोस्टर बरामद हुए हैं। साथ ही ईसाई मिशनरी से जुड़ा साहित्य भी मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह नेटवर्क हिंदू विरोधी एजेंडे के साथ सक्रिय था। अब तक की जानकारी के मुताबिक यह गिरोह केवल एक दो शहरों तक सीमित नहीं था। इसके नेटवर्क का विस्तार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक फैला हुआ था। आरोपी युवकों को बाकायदा प्रशिक्षित किया जाता था कि कैसे हिंदू बेटियों को टारगेट करना है। पुलिस की विवेचना में ऐसे दर्जनों ऐसे मामलों की पहचान हुई है, जिनमें लव जेहाद के माध्यम से लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण किया गया। इनमें से कई लड़कियों को शादी के झांसे में फंसाकर इस्लाम कबूल कराया गया, कुछ को दुबई भेजने की तैयारी थी, और कुछ को गोद लिया गया बताकर ईसाई मिशनरियों के पास भेजा गया। इस गंभीर प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तत्परता, स्पष्टता और प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित कराई है, वह बताता है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी हाल में धर्मांतरण उद्योग का अड्डा नहीं बनने देगा। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि हमारी बहन-बेटियों की आस्था और पहचान को खत्म करने का दुस्साहस कोई करे। सनातन विरोधी इस कुचक्र को जड़ से समाप्त किया जाएगा। प्रदेश पुलिस और विशेष टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से जो सघन कार्रवाई की है, वह सराहनीय ही नहीं, बल्कि मिसाल के रूप में पूरे देश के लिए प्रेरणा है। 18 टीमें गठित की गईं, जिनमें तकनीकी विशेषज्ञों और साइबर सेल को भी जोड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच से गिरोह की सम्पूर्ण गतिविधियों का डिजिटल नक्शा खींचा गया। इस जांच से यह भी पता चला कि ये लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों का इस्तेमाल कर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते, फिर उन्हें बहला-फुसलाकर कट्टरपंथी संगठनों के जाल में फंसाते थे।

आगरा, मेरठ, हापुड़, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, और गाजियाबाद जैसे शहरों में यह नेटवर्क बहुत गहराई तक फैला हुआ था। इतना ही नहीं, कई मामलों में लड़कियों को पहचान बदलने, नया नाम और नया धर्म अपनाने के लिए मानसिक, सामाजिक और शारीरिक दबाव डाला गया। कुछ युवतियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें धमकाया गया था कि अगर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा या उनके परिजनों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में धर्मांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून लागू किया गया था। उस समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था कि जो लोग लव जेहाद जैसे षड्यंत्रों के जरिए समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब इस हालिया कार्रवाई से यह फिर सिद्ध हुआ है कि प्रदेश में कानून सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि हर हाल में लागू किया जा रहा है।

काशी विद्वत परिषद ने जारी की हिंदू आचार संहिता

दहेज प्रथा, शादियों की बेमानी भव्यता और धर्मांतरण पर लगाएगी अंकुश

वाराणसी, 25 जुलाई (एजेंसियां)। काशी विद्वत परिषद ने नई हिंदू आचार संहिता जारी की है, इसके जरिए दहेज प्रथा, भव्य शादियों और धर्मांतरण पर अंकुश लगाने की कवायद की जाएगी। काशी विद्वत परिषद ने हिंदू परंपराओं और सामाजिक व्यवहार में सुधार के लिए एक नई हिंदू आचार संहिता जारी की है। 400 पन्नों के इस दस्तावेज को देश भर के विद्वानों, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों और संतों के साथ लंबे विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। नई संहिता में दहेज पर पूर्ण प्रतिबंध, शादियों में फिजूलखर्ची पर रोक और दिन में वैदिक तरीके से विवाह करने की सलाह दी गई है।

अंतिम संस्कार के बाद होने वाले भोज में केवल 13 लोगों को शामिल करने की सीमा तय की गई है। इसके साथ ही प्री-वेडिंग शूट और सगाई जैसी आधुनिक प्रथाओं को भी हतोत्साहित किया गया है। संहिता में हिंदू धर्म में वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जिन लोगों ने किसी दबाव में धर्म परिवर्तन कर लिया था, वे लोग अपने गोत्र और नाम सहित हिंदू धर्म में वापस लौट सकेंगे। इसके साथ ही मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिरों के गर्भगृह में केवल पुजारियों और संतों के प्रवेश की अनुमति होगी। काशी विद्वत परिषद के महासचिव राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि इस संहिता को 70 विद्वानों द्वारा विकसित किया गया है। ये विद्वान 11 टीमों और तीन उप-टीमों में विभाजित थे। प्रत्येक टीम में उत्तरी और दक्षिणी भारत के पांच विद्वान शामिल थे। संहिता को अंतिम रूप देने के लिए 40 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं। उन्होंने बताया कि इस संहिता की 5 लाख प्रतियां पूरे देश में बांटी जाएंगी।

इस संहिता को तैयार करने में मनुस्मृति, पराशर स्मृति, देवल स्मृति के साथ-साथ गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अंशों को शामिल किया गया है। अक्टूबर 2025 में शंकराचार्यों, रामानुजाचार्यों और प्रमुख संतों की स्वीकृति के बाद इस संहिता को आधिकारिक तौर पर लागू किया जाएगा।

फिडे महिला विश्व कप में पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी बनेगा विजेता, हम्पी की दिव्या से टक्कर

नई दिल्ली,25 जुलाई (एजेंसियां) ।

स्टार महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख शनिवार को होने वाले फिडे महिला विश्व कप फाइनल में एक-दूसरे के सामने होंगी जिससे पहली बार इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी विजेता बनेगा। इस प्रतियोगिता के इतिहास में यह पहली बार है जब दो भारतीय फाइनल में आमने-सामने होंगी। हम्पी और देशमुख दोनों ने फाइनल में पहुंचकर अगले साल होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हम्पी खिताब की प्रबल दावेदार बड़े मुकाबलों में खेलने के अपने अनुभव के आधार पर हम्पी फाइनल में हमवतन देशमुख के खिलाफ प्रबल दावेदार के रूप में उतरेंगी। हम्पी ने गुरुवार को सेमीफाइनल में चीन की टिंगजी लेई को टाईब्रेकर में हराकर जीत हासिल की जबकि देशमुख ने अंतिम-चार चरण के दूसरे गेम में पूर्व विश्व चैंपियन चीन की ही झोंगयी टैन को हराया। 38 वर्षीय ग्रैंडमास्टर हम्पी विश्व महिला रैपिड टूर्नामेंट की विजेता थीं और हाल में महिला ग्रां प्री में भी संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहीं। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। पिछले कई वर्षों में उनका जज्बा और दृढ़ संकल्प जरा भी कम नहीं हुआ है। हम्पी ने फिडे वेबसाइट से कहा, शतरंज प्रेमियों के लिए यह सबसे खुशी के पलों में से एक है क्योंकि अब खिताब निश्चित रूप से भारत के पास जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से एक खिलाड़ी के रूप में कल का मैच भी काफी कठिन होगा। दिव्या ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम्पी से आधी उम्र की अंतरराष्ट्रीय मास्टर देशमुख इस प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में शामिल तीन खिलाड़ियों को हराकर उलटफेर कर चुकी हैं। उनका पहला शिकार चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त जिनर झू थीं जिन्होंने डी हरिका को बाहर कर दिया था। सेमीफाइनल में देशमुख ने टैन को हराया नागपुर की 19 वर्षीय देशमुख ने सेमीफाइनल में चीन की पूर्व महिला विश्व चैंपियन झोंगयी टैन को हराया। उन्होंने फाइनल में पहुंचने के बाद कहा, मुझे बस थोड़ी नींद और थोड़ा खाना चाहिए। इन दिनों मैं काफी चिंतित हूं। देशमुख ने अपनी सेमीफाइनल बाजी के बारे में कहा, मुझे लगता है कि मैं और बेहतर खेल सकती थी। एक समय मैं जीत रही थी और फिर चीजें मुश्किल हो गई। मुझे लगता है कि मैंने बीच में गलती कर दी, वर्ना मुझे और भी आसान जीत मिल सकती थी। मुझे लग रहा था कि यह ड्रॉ रहेगा। पर अंत में मैं भाग्यशाली रही। टूर्नामेंट के विजेता को मिलेगी मोटी रकम हम्पी को प्री-क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन स्विट्जरलैंड की एलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुक ने टाईब्रेकर तक खींचा और इसके बाद उन्होंने युक्सिन सोंग के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया।

न्यूज ब्रीफ

वाराणसी की हैंडबॉल खिलाड़ी नैना यादव चीन में मोस्ट वेल्यूबल खिलाड़ी घोषित

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद की प्रतिभाशाली हैंडबॉल खिलाड़ी नैना यादव को चीन के जिंघांगशन शहर में आयोजित 11वीं एशियन यूथ वीमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 में बीते गुरूवार की शाम मोस्ट वेल्यूबल खिलाड़ी घोषित किया गया। नैना यादव भारतीय टीम की उप कप्तान भी हैं। इसी प्रतियोगिता में वाराणसी की कोमल राय भी हिस्सा ले रही हैं। दोनों खिलाड़ी के बेहतरीन प्रदर्शन पर उनके कोच और परिजनों ने खुशी जताई है। दोनों खिलाड़ी यहां परमानंदपुर स्थित विकास इंटर कालेज की 11वीं की छात्रा हैं। कालेज के प्रधानाचार्य डॉ ए.के. सिंह ने यह जानकारी दी है। चीन में आयोजित एशियन यूथ वीमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप उन्होंने दोनों खिलाड़ियों के साथ पूरी भारतीय टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामना दी है। दोनों खिलाड़ी यहां बाबू आरएन सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परमानंदपुर में डॉ आशा सिंह की देखरेख में प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। बताते चलें गांव के बेहद गरीब परिवार की दोनों बेटियां पहली बार भारतीय महिला हैंडबॉल टीम में भागीदारी कर रही हैं। दोनों के पिता राजगीर मिस्त्री (भवन निर्माण श्रमिक) हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ बेटियों के सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे हैं। परिजनों के साथ साथी खिलाड़ियों को पूरी उम्मीद है कि नैना और कोमल चीन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश और जिले का नाम रोशन करेंगी।

आर्सेनल ने वेलेंसिया के डिफेंडर क्रिस्थियन मोस्क्वेरा के साथ किया करार

लंदन। प्रीमियर लीग क्लब आर्सेनल ने गुरुवार को स्पेनिश क्लब वेलेंसिया के डिफेंडर क्रिस्थियन मोस्क्वेरा के साथ करार की घोषणा की। स्पेन की अंडर-21 टीम के इस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को लगभग 13 मिलियन पाउंड (प्रदर्शन आधारित ऐड-ऑन सहित) की शुरुआती फीस पर साइन किया गया है। उन्होंने पांच साल का अनुबंध किया है, जिसमें एक साल का अतिरिक्त विकल्प शामिल है। इस डील के साथ आर्सेनल का इस समर ट्रांसफर विंडो में खर्च लगभग 140 मिलियन पाउंड (करीब 189 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया है। 21 वर्षीय मोस्क्वेरा, जो हाल ही में आर्सेनल के पांचवें साइनिंग बने हैं, टीम के प्रमुख डिफेंडरों विलियम सलीबा और गैब्रियल को कवर देंगे। हालांकि, वह डिफेंस की किसी भी पोजीशन पर खेलने में सक्षम हैं। पिछले सीजन में मोस्क्वेरा ने वेलेंसिया के लिए 41 मुकाबले खेले थे। उन्होंने अब आर्सेनल की सिंगापुर और हांगकांग की प्री-सीजन टूर के लिए टीम को जॉइन कर लिया है। गौरतलब है कि आर्सेनल प्रीमियर लीग में लगातार तीन बार उपविजेता रहा है और वह अपना 2025/26 सीजन का पहला मुकाबला 17 अगस्त को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगा। इस बीच, क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन के स्ट्राइकर विक्टर ग्योकरेस को साइन करने की भी उम्मीद कर रहा है।

टी20 में 150 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने ईश सोढ़ी

हरारे। न्यूजीलैंड के भारतीय मूल के स्पिनर ईश सोढ़ी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ में में चार विकेट लेने के साथ ही टी20 में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए। सोढ़ी टिम साउथी और राशिद खान के बाद टी20 प्रारुप में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वह तीसरे और न्यूजीलैंड के दूसरे गेंदबाज हैं। ईश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में केवल 4 ओवर में ही 12 रन देकर 4 विकेट लिए। उनके इस शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड की टीम ने 60 रनों से मैच जीत लिया। गौरतलब है कि टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड टिम साउथी के नाम है। साउथी ने 126 मैचों में 164 विकेट लिए हैं। वहीं इस सूची में दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान हैं। इस कलाई स्पिनर ने केवल 96 मैचों में 161 विकेट लिए हैं।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम चार मैचों की श्रृंखला के लिए करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा

15 से 21 अगस्त तक पर्थ हॉकी स्टेडियम में होंगे मुकाबले

नई दिल्ली,25 जुलाई (एजेंसियां) ।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम अगस्त में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां वह पर्थ हॉकी स्टेडियम में 15 से 21 अगस्त तक चार मैचों की सीरीज खेलेगी। यह सीरीज भारत के लिए एशिया कप 2025 की तैयारियों का एक अहम पड़ाव मानी जा रही है। आठवीं रैंकिंग वाली भारतीय टीम का सामना छठी रैंकिंग वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम से होगा। मुकाबले 15, 16, 19 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। हाल ही में दोनों टीमें एफआईएच प्रो लीग 2024-25 के तहत यूरोप में आमने-सामने आई थीं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दोनों मैचों में 3-2 से हराया था। हालांकि, इससे पहले भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर इतिहास रच दिया था-यह ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की 1972 म्यूनिख खेलों के बाद पहली जीत थी। पिछले कुछ वर्षों में भले ही मुकाबले कड़े रहे हों, लेकिन समग्र आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। साल 2013 से अब तक दोनों टीमों के बीच 51 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 35 मैच जीते हैं, भारत ने 9 और 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। यह सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होने वाले हीरो एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज़ से बेहद अहम मानी जा रही है। यह टूर्नामेंट एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफिकेशन का मौका देगा, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दौरा भारत की रणनीति में एक बड़ा कदम है। इस दौरे को लेकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा,यह दौरा हमारे लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह एशिया कप से ठीक पहले आ रहा है। भले ही ये दोस्ताना मैच हों, लेकिन हमारे लिए ये तैयारी का अहम हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलना हमारी हर स्तर पर परीक्षा लेगा, और यही चुनौती हमें चाहिए भी। उन्होंने आगे कहा,हमने हाल ही में 10 दिनों का ट्रेनिंग कैंप पूरा किया है और टीम का मनोबल काफी ऊंचा है। पहले दो मैचों का इस्तेमाल हम संभावित खिलाड़ियों के चयन के लिए करेंगे।

अगले माह होगा रोमन रेंस और जे उसो का ब्रेकर और ब्रॉन्सन से मुकाबला

सेन डियागो। डब्ल्यू डब्ल्यूई में अगले महा अगस्त में रेसलर रोमन रेंस और जे उसो की टीम का मुकाबला ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड से होगा। यह मुकाबला 2 या 3 अगस्त को समरस्लैम में होगा। पॉल हेमैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके इस मुकाबले के बारे में बताया है। उन्होंने रोमन रेंस और जे उसो को चेतावनी भी दी है। हेमैन ने रोमन रेंस को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह मुकाबला उनके लिए बेहद कठिन रहेगा। हेमैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा, रोमन किसी भी दिन मुकाबला करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड की ओर से रोमन रेंस और जे उसो ने मुकाबले की चुनौती स्वीकार की है। रोमन ने इससे पहले हेमैन का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि हेमैन ने उन्हें द ट्राइबल चीफ नहीं बनाया है। रेंस ने कहा कि वह द ट्राइबल चीफ इसलिए हैं क्योंकि फैंस उन्हें अभी भी मानते हैं। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने कहा कि वह यहां के नए बिग डॉग हैं। रेंस और ब्रेकर के बीच मारपीट भी हुई थी। जे उसो ने आकर रोमनको बचाया। इसके बाद रेंस ने समरस्लैम के लिए चुनौती दी। जे उसो इस मुकाबले में रोमन रेंस के पार्टनर होंगे।

काउंटी चैंपियनशिप में भारतीयों का जलवा : तिलक वर्मा ने हैम्पशायर के लिए जड़ा शतक

नई दिल्ली,25 जुलाई (एजेंसियां) ।

काउंटी चैंपियनशिप डिविजन वन में गुरुवार को भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। खासकर तिलक वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक लगाया ।

भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने हैम्पशायर की ओर से खेलते हुए नॉटिंघमशायर के खिलाफ शानदार शतक जड़ा।

बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 13 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 112 रन बनाए। उनका यह शतक हैम्पशायर को नॉटिंघमशायर के पहली पारी के 578/8 डिक्लेयर के स्कोर की ओर ले जाने में अहम साबित हुआ। वहीं, बाएं हाथ के स्पिनर आर. साई किशोर, जो सरे की ओर से खेल रहे हैं, ने यॉर्कशायर के खिलाफ एक और विकेट हासिल कर अपनी पारी पूरी की। उन्होंने 119 रन देकर 2 विकेट झटके।

खलील अहमद, जो एसेक्स की ओर से खेल रहे हैं, ने ससेक्स के खिलाफ एक विकेट झटका और उनकी टीम जीत के करीब पहुंच गई है।

इस बीच, युजवेंद्र चहल का नॉर्थैम्पटनशायर की ओर से खेलते हुए मिडलसेक्स के खिलाफ मैच बेहद खराब रहा। चहल ने पहली पारी में कोई विकेट नहीं लिया और दूसरी पारी में गोल्डन डक (पहली गेंद पर आउट) होकर पवेलियन लौट गए।

भारतीय खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन दिखाता है कि वे इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं, हालांकि कुछ के लिए यह चुनौतीपूर्ण भी साबित हो रही है।

प्रीमियर लीग ट्रॉफी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर

लंदन में प्रीमियर लीग ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर।

यश पर अब एक नाबालिग ने लगाया बलात्कार का आरोप

मुम्बई,25 जुलाई (एजेंसियां) ।

क्रिकेटर यश दयाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले ही यौन शोषण मामले में फंसे यश पर अब जयपुर में एक नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया है। आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के क्रिकेटर यश पर इससे पहले गाजियाबाद में एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में वह कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं हालांकि वह अभी तक गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में गाजियाबाद मामले में यश की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी पर अब जयपुर में उनके खिलाफ जो मामला दायर हुआ है उससे उनका करियर भी खतरे में आ गया है।

उनपर 17 साल की नाबालिग लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यश के खिलाफ सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में नाबालिग पीड़िता द्वारा बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट में नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि यश ने पेशेवर क्रिकेट में बेहतर भविष्य का वादा करते हुए उसका दो साल तक शोषित किया।

रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता क्रिकेट के जरिये ही यश के संपर्क में आयी थी। ऐसे में यश ने उसे बेहतर क्रिकेट करियर बनाने का झांसा देते हुए दो साल तक बलात्कार किया। रिपोर्ट में आईपीएल 2025 का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि यश दयाल ने जयपुर में हुए मैच के दौरान पीड़िता को एक होटल में बुलाया और उसका शोषण किया। लंबे समय तक चुप्पी, भावनात्मक ब्लैकमेल और शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के बाद पीड़िता ने अंत में उसके खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है।. जयपुर पुलिस ने आगे बताया कि जब बलात्कार की पहली घटना तब हुई थी जब पीड़िता 17 साल की नाबालिग थी, इसलिए यश के खिलाफ पास्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें दोषी पाये जाने पर यश को लंबे समय की सजा होना तय है।

ऋषभ के चोटिल पैर को निशाना बनाने वाले स्टोक्स पर भड़के लोग

मैनचेस्टर,25 जुलाई (एजेंसियां) ।

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन पैर की अंगुली में फ्रैक्चर के बाद भी बल्लेबाजी के लिए उतरे। उनके इस जज्बे की जहां लोगों ने प्रशंसा की और उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की कड़ी आलोचना की है। स्टोक्स इस मैच में जानबूझकर ऋषभ के चोटिल पैर पर यॉर्कर गेंदें कर रहे थे। वहीं जब ऋषभ ने एक रन लिया तब भी स्टोक्स ने बहुत ही ध्यान से उनके पैर के उस पंजे को देखा जिसमें फ्रैक्चर हुआ था। उन्होंने टूटी उंगली को लक्ष्य कर लगातार यॉर्कर गेंदें फेंकीं। ऋषभ तब भी बिना डरे जमे रहे और उन्होंने एक पैर से खेलते हुए आक्रामक शॉट लगाये। जोफ्रा आर्चर ने भी उनके पैर पर ही निशाना साधार पर इस बल्लेबाजी ने शानदार छक्का लगा दिया।

इस प्रकार किसी बल्लेबाज के चोटिल पैर को ही गेंद से टारगेट करने की स्टोक्स की रणनीति की सोशल मीडिया में जमकर आलोचना हुई है। लोगों ने कहा कि खेल है, खेल ही रहने दो। क्या आउट करने के लिए फ्रैक्चर पर ही टारगेट करना जरूरी था यह आउट करने की रणनीति थी या विरोधी को जानबूझकर और ज्यादा चोटिल करने की बेहद शर्मनाक कोशिश साथ ही कहा कि स्टोक्स ने क्रिकेट भावना, खेल भावना, जेंटलमेन गेम जैसे बातों का अपमान किया है।

अभी दो दिन पहले ही पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने कहा था कि इंग्लैंड सहित कुछ टीमें खेल भावना शब्द का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार करती हैं। मैनचेस्टर टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी में 358 रन बनाए हैं। फ्रैक्चर होने के बावजूद ऋषभ ने दूसरे दिन बल्लेबाजी की और 54 रन बनाकर आउट हुए।

सचिन तेंदुलकर सहित दिग्गजों ने ऋषभ पंत के साहसिक जज्बे को सलाम किया

मुम्बई। सचिन तेंदुलकर सहित कई दिग्गज क्रिकेटरों ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में चोटिल होने के बाद भी बल्लेबाजी के लिए उतरने पर उनके जज्बे को सलाम किया है। ऋषभ जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो टीम मुश्किल हालातों में थी पर उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलकर उससे 358 रनों के अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। पहली पारी में जब वह पहले दिन बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके पैर पर एक तेज गेंद लगी थी। क्रिस वोक्स की ये गेंद सीधे ही उनके पैर के अंगूठे पर लगी जिससे उसमें फ्रैक्चर हो गया। मैदान से उनको एम्बुलेंस में बिठाकर ले जाना पड़ा और डॉक्टरों ने उनको करीब छह सप्ताह तक खेल से दूर रहने को कहा पर इसके बाद भी वह दूसरे दिन पेन किलर लेकर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने लंगड़ाते मेजबान इंग्लैंड टीम के गेंदबाजों का पूरे साहस से सामना किया। तेंदुलकर ने इस साहसिक पारी को देखकर कहा, मजबूती का मतलब है दर्द के बावजूद खेलना और उससे ऊपर उठना। ऋषभ ने चोट के साथ वापस मैदान में आकर और ऐसा प्रदर्शन करके जबरदस्त कैरेक्टर दिखाया है।

शुभ लाभ खबरें जो सोच बदल दे हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

बाइक आलट्राहाइक 450 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश

नई दिल्ली,25 जुलाई (एजेंसियां)।

महंगी बाइक बनाने वाली कंपनी मोटो मोरिनी ने अपनी नई एडवेंचर बाइक आलट्राहाइक 450 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश कर दिया है। फिलहाल यूरोप में इस बाइक के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और सितंबर 2025 से इसकी डिलीवरी भी शुरू होने की योजना है। यह दमदार बाइक सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और सीएफमोटो 450 एमटी को टक्कर देती है। हालांकि भारत में इसकी लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मोटो मोरिनी की भारत में मौजूदा उपस्थिति इसे यहां लाने की संभावनाएं बढ़ा देती है। ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों में सिंगल डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल एबीएस की सुविधा मौजूद है। 190 किलोग्राम के ड्राई वेट वाली इस बाइक में 18.5 लीटर का फ्यूल टैंक, 215एमएम ग्राउंड क्लीयरेंस और ट्रैक्शन कंट्रोल, नेविगेशन, यूएसबी पोर्ट, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इसका स्टाइल भी बेहद आकर्षक है, जिसमें बग-आई हेडलैंप, बीक फ्रंट फेंडर और लंबा टेल सेक्शन दिया गया है। भारत में लॉन्च होने पर यह बाइक एडवेंचर बाइक सेगमेंट में एक मजबूत खिलाड़ी बन सकती है। आलट्राहाइक 450 को खासतौर पर एडवेंचर लवर्स के लिए तैयार किया गया है। इसमें 450 सीसी का लिक्विड-कूल्ड ट्विन-सिलेंडर इंजन है, जो 44.2 बीएचपी की ताकत और 42एनएम का टॉर्क देता है। स्टील फ्रेम पर बनी इस बाइक में केवायबी का एडजस्टेबल सस्पेंशन, 21-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर स्पोक व्हील्स, फ्रंट में यूएसडी फोर्क्स और रियर में लिंक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है।

एचएफ डीलक्स का नया वर्जन एचएफ डीलक्स प्रो लांच

नई दिल्ली। अपनी पॉपुलर एंट्री-लेवल बाइक एचएफ डीलक्स का नया वर्जन एचएफ डीलक्स प्रो हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत रुपए 73,500 तय की गई है। इस बाइक में आधुनिक टेक्नोलॉजी और नए जमाने के फीचर्स को शामिल किया है, जिससे यह बाइक अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश और परफॉर्मेंस से भरपूर हो गई है। नई एचएफ डीलक्स प्रो में 97.2सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 7.9 बीएचपी की पावर और 8.05 एनएम टॉर्क देता है। बाइक में आईउएस टेक्नोलॉजी, लो फ्रिक्शन इंजन, एलईडी हेडलाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लो फ्यूल इंडीकेटर, 18-इंच व्हील और एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। साथ ही, इसे नए ग्राफिक्स और बेहतर डिजाइन के साथ पेश किया गया है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

सरकारी दफ्तर में ...

परिधान से परहेज करना होगा। इस आदेश-परिपत्र में महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। स्पष्ट है कि बांग्लादेश में इस्लामिक परिधान लागू करने की भूमिका स्पष्ट रूप से शुरू कर दी गई है।सरकारी आदेश में पुरुष कर्मचारियों के लिए जींस या गाबार्डिन ट्राउजर पहनने से मना किया गया है और केवल लंबी या आधी बाजू की औपचारिक शर्ट और उचित औपचारिक जूते पहनने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश बैंक के कार्यकारी निदेशक और प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने इस आदेश को शिष्टाचार बहाली के लिए आवश्यक ड्रेस कोड बताया। जबकि इस बहाने के निहितार्थ आसानी से समझे जा सकते हैं। निर्देश में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि इसका पालन न करने पर सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। शिष्टाचार बहाली के आदेश की अशिष्टता से बांग्लादेश सरकार के इरादे स्पष्ट हैं। बांग्लादेश महिला परिषद की अध्यक्ष फौजाया मोस्लेम ने इस निर्देश पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मैंने पहले कभी किसी सरकारी संस्थान में ऐसा निर्देश नहीं देखा। यह हमारे सांस्कृतिक परिवेश और सामाजिक मानदंडों को नया रूप देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। यह सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, यह इस्लामिक-दृष्टि थोपने के बारे में है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रथाओं को संस्थागत बनाने से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हाशिए पर जाने और बांग्लादेश को धार्मिक अधिनायकवाद के करीब ले जाने का खतरा है। बांग्लादेश बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ड्रेस कोड संबंधी निर्देश तो बस एक छोटी सी झलक है। पिछले कई महीनों से, वरिष्ठ अधिकारी अपने मातहतों को कार्यालय समय के दौरान सामूहिक नमाज अदा करने, दाढ़ी बढ़ाने और अरब शैली के परिधान पहनने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं। गैर-मुस्लिम और धर्मनिरपेक्ष कर्मचारियों, खासकर धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को, अस्पष्ट बहानों के तहत चुपचाप प्रमुख पदों से हटाया जा रहा है या पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक धीमा लेकिन खतरनाक बदलाव किया जा रहा है, जो सार्वजनिक संस्थानों को धार्मिक रूप से अनुरूपतावादी स्थानों में बदल रहा है और प्रशासनिक आड़ में असहिष्णुता को बढ़ावा दे रहा है। यह घटनाक्रम अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के संरक्षण और इशारे पर हो रहे हैं। उक्त अधिकारी ने कहा कि यूनुस को पश्चिमी तथाकथित उदारवादी पूंजीपति वर्ग का संरक्षण मिल रहा है। इसी पश्चिमी ताकत के सहारे बांग्लादेश में यूनुस का अवैध शासन चल रहा है और एक निरंकुश, विवादास्पद, मतदाता-विहीन व्यक्ति इस देश को इस्लामिक गणराज्य बनाने पर तुला है।

यूनुस मुफ्ती करीम जैसे कट्टरपंथी इस्लामी नेताओं और अंतरराष्ट्रीय इस्लामी नेटवर्क के साथ मिलकर बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष शासन को एक इस्लामिक शासन में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ की लगातार चुप्पी अत्यंत चिंताजनक और संदेहास्पद है। विडंबना यह अपने धर्मनिरपेक्ष संविधान पर गर्व करने वाला अमेरिका तालिबान के कठोर ड्रेस-कोड पर चिंता व्यक्त करता है, लेकिन बांग्लादेश में इसी तरह का चलन अख्तियार करने पर खामोश रहता है। अमेरिका का यह दोगलापन बांग्लादेश के लोगों को चुभ रहा है। अमेरिका की यह चुप्पी आकस्मिक नहीं है। बाइडेन प्रशासन, बिल एवं हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा और जॉर्ज सोरोस जैसे वैश्विकतावादी अभिजात वर्ग के साथ यूनुस का गठजोड़ कुछ अलग ही गुल खिला रहा है।

बांग्लादेश एक खतरनाक दोराहे पर खड़ा है। केंद्रीय बैंक द्वारा तालिबान-प्रेरित ड्रेस कोड अपनाने, अल्पसंख्यकों को दरकिनार किए जाने और सरकारी संस्थाओं में सूक्ष्म रूप से कट्टरपंथीकरण के साथ, एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और लोकतांत्रिक बांग्लादेश का सपना तेजी से धूमिल हो रहा है। यह सिर्फ एक घरेलू मुद्दा नहीं है, इसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक निहितार्थ हैं। शरिया-शासित बांग्लादेश कट्टरपंथ के लिए एक उपजाऊ जमीन साबित होगा, जो पड़ोसी भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भीषण खतरा पैदा करेगा, साथ ही चरमपंथ से निपटने के वैश्विक प्रयासों को अस्थिर करेगा।

बांग्लादेश सरकार ने अध्यादेश जारी कर यह भी कहा है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बोलने वाले सरकारी कर्मचारी को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। नए अध्यादेश के तहत, अगर कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा तब भी उसे नौकरी से जबरन निकाल बाहर किया जाएगा। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने बुधवार 23 जुलाई 2025 को इस बारे में एक नया अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के जरिए 2018 के सरकारी सेवा कानून में संशोधन के रूप में यह बदलाव किया गया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को कुछ बोलने या विरोध करने से रोक रही है। यह बांग्लादेश में लोकतंत्र के कमजोर होने और सख्त शरिया कानून के लागू होने का संकेत है।

बांग्लादेश के माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस साल 2 जनवरी को एक नोटिस जारी किया था। इसमें साफ कहा गया था मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ गलत खबरें फैलाने और दुष्प्रचार करने वाले छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखने में यह नोटिस गलत सूचना रोकने का कदम लग सकता है, लेकिन असल में यह आलोचनाओं को दबाने और छात्रों को डराने का तरीका है।

हमारे लिए...

पारंपरिक नौकाओं को प्रदर्शित किया गया है। यह दर्शाता है कि हम न केवल पड़ोसी हैं, बल्कि सह-यात्री भी हैं। हमारे लिए हमेशा दोस्ती पहले आती है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और महासागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद दोस्त होने पर गर्व है। चाहे संकट हो या महामारी भारत हमेशा सबसे पहले उनके साथ खड़ा रहा है। चाहे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता हो या कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को संभालना हो, भारत ने हमेशा साथ मिलकर काम किया है। पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा के दौरान हमने व्यापक आर्थिक और समुद्री साझेदारी पर एक दृष्टिकोण साझा किया था। अब यह एक वास्तविकता बन रहा है। यह उसी का परिणाम है कि हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन संभव हो पाया है। भारत के सहयोग से निर्मित 4000 सामाजिक आवास इकाइयां मालदीव के कई परिवारों के लिए एक नई शुरुआत बनेंगी। ये उनके नए घर होंगे। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, अड्डू रोड विकास परियोजना और हनीमाधू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं के चलते मालदीव आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगा। जल्द ही नौका प्रणाली की शुरुआत के साथ विभिन्न द्वीपों के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। उसके बाद द्वीपों के बीच की दूरी केवल नौका समय के संदर्भ में मापी जाएगी, न कि जीपीएस के संदर्भ में।

दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में 4,850 करोड़ रुपए की ऋण रेखा (लाइन ऑफ क्रेडिट) का विस्तार। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ऋणों की वार्षिक पुनरभुगतान बाध्यता में छूट। भारत-मालदीव मुक्त व्यापार समझौते (आईएमएफटीए) पर वार्ता की शुरुआत। भारत-मालदीव राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर संयुक्त डाक टिकट जारी की। हुलहुमाले में 3300 सामाजिक आवास इकाइयों का हस्तांतरण। अड्डू शहर में सड़क और जल निकासी प्रणाली परियोजना का उद्घाटन। मालदीव में 6 हाई-इम्पैक्ट सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। भारत ने मालदीव को 72 वाहनों और अन्य उपकरणों का सौंपा। कोप-33 की मेजबानी के लिए मालदीव ने भारत का किया समर्थन शामिल हैं।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दो महत्वपूर्ण अवसरों के साथ हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरे साथ शामिल होंगे। आज हमने मालदीव के साथ औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त रूप से एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी और मुझे कई प्रमुख क्षेत्रों में चार समझौता ज्ञापनों और तीन समझौतों पर हस्ताक्षर होते देखने का सम्मान प्राप्त हुआ। इनमें 565 मिलियन डॉलर का एक ऋण समझौता भी शामिल है। इसका उपयोग प्रमुख क्षेत्रों में मेरी सरकार की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा, मुझे भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू होने की घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है। यह ऐतिहासिक पहल हमारी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी प्रमुख ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना पूरी हो जाने पर भारत और मालदीव के बीच स्थायी साझेदारी का एक स्थायी प्रतीक बन जाएगी। मैं मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को 72 वाहन प्रदान करने के लिए भारत के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में मालदीव के प्रमुख भागीदार के रूप में भारत सरकार की भूमिका के लिए उसे धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि मालदीव कोप-33 के मेजबान के रूप में भारत को अपना पूर्ण समर्थन देगा। हम सफल और प्रभावशाली परिणाम के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करने की भारत की क्षमता को पहचानते हैं।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के माले स्थित रिपब्लिक स्क्वायर में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भारत सरकार के अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका परिचय कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने माले में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पीएम मोदी ब्रिटेन की यात्रा के बाद आज मालदीव पहुंचे। दो दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू के आमंत्रण पर मालदीव पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की यह मालदीव की तीसरी यात्रा है। मोहम्मद मुइज्जू सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद पहली बार हो रही है। हालांकि उसके पहले मोहम्मद मुइज्जू भारत आकर तनाव को काफी कम चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी की पिछली मालदीव यात्रा जून 2019 में हुई थी।

प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय मालदीव यात्रा पर मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा, मालदीव और भारत के बीच संबंधों ने हमेशा यह दिखाया है कि भारत पहली प्रतिक्रिया देने वाला देश है। जब भी हम अंतरराष्ट्रीय लाइन पर डायल करते हैं, भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारतीय लोगों का दिल बड़ा है और वे मालदीव की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वे बहुत उदार हैं। दूसरा, भारत भौगोलिक रूप से मालदीव के बहुत करीब है। जब भी मालदीव में कोई आपात और संकटपूर्ण घटना होती है, भारत ने हमें कभी निराश नहीं किया है। भारत सरकार द्वारा मालदीव की सहायता में वृद्धि उनकी उदारता और परिपक्वता को दर्शाती है। कूटनीतिक तनाव के बावजूद, भारत ने फैसला किया कि संबंध लोगों के बीच है और सरकारें बदलती रहती हैं, सत्ता में राजनीतिक दल बदलते रहते हैं लेकिन हमारे दोनों लोगों के बीच मौजूद संबंध ठोस आधार पर हैं और कभी नहीं बदले हैं।

पीएम मोदी के मालदीव दौरे पर माले में भारत के उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम ने कहा, पीएम मोदी के मालदीव दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में काफी उत्साह है। इस दौरे पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और विभिन्न मुद्दों पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इनमें विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट या मदद दी जाएगी। दूसरे दिन पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मालदीव पहुंचने के पहले पीएम मोदी ब्रिटेन के दौरे पर थे, जहां उनकी मौजूदगी में भारत-ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं ब्रिटेन में पीएम मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टार्मर और किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात की।

पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच और कूटनीतिक समझ का नतीजा है कि वह मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। दुनिया जहां भारत के सबसे करीबी समुद्री भागीदारों में से एक को भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के हाथों खोने की आशंका जता रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व संयम और रणनीतिक धैर्य दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी कूटनीति ने भारत के पड़ोसी देशों, विशेषकर मालदीव के साथ संबंधों में एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली जीत हासिल की है। दो साल पहले, जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इंडिया आउट मुहिम के साथ सत्ता में आए थे, तब अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने भारत की मालदीव नीति की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। जल्दबाजी में जवाबी कार्रवाई के बजाय सरकार ने शांत और स्थिर दृष्टिकोण अपनाया। पीएम मोदी मुइज्जू को बधाई देने वाले पहले विश्व नेता थे। यह दूरदर्शिता ही थी जिसने संबंधों को मजबूत किया है। नतीजा सामने है और पीएम मोदी राष्ट्रपति मुइज्जू की सरकार में मालदीव में राजकीय यात्रा पर जाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। वह मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। यह एक ऐसा निमंत्रण जो इंडिया आउट के नारों को कमजोर करता है और कुछ वक्त पहले के संबंधों में आई उल्लेखनीय प्रगति और विश्वास को दर्शाता है।

रक्षा, समुद्री और क्षमता निर्माण सहयोग भी जारी रहा है, जो किसी अन्य भागीदार के मुकाबले बेजोड़ है। भारत का मजबूत व्यापार और निवेश 54.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जिसमें भारतीय व्यवसाय और पर्यटक मालदीव के तटों को व्यस्त रखते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने खुद भारत को मालदीव के सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढांचा विकास में एक प्रमुख भागीदार बताया है। राष्ट्रपति मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद से, भारत ने एक सच्चे और विश्वसनीय मित्र के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। भारत ने आपातकालीन वित्तीय सहायता (40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की और 3,000 करोड़ रुपए का मुद्रा स्वैप सहित), क्षमता निर्माण सहायता, और 13 नए समझौता ज्ञापनों के माध्यम से मालदीव में नौका सेवाओं का विस्तार करके मालदीव का निरंतर समर्थन किया है।

मालदीव की ही तरह श्रीलंका में भी राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पदभार संभालने के बाद जानकारों ने आशंका जताई थी कि नई दिल्ली-कोलंबो संबंध नकारात्मक दिशा में चले जाएंगे। दावे किए गए कि श्रीलंका के वामपंथी झुकाव से भारत को चिंतित होना पड़ सकता है। हालांकि, संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। यह दर्शाता है कि भारत का सम्मानजनक साझेदारी, समय पर समर्थन और रणनीतिक धैर्य का अद्वितीय दृष्टिकोण निर्णायक रूप से काम करता है। विश्वास के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में, पीएम मोदी ने हाल ही में इस साल की शुरुआत में श्रीलंका का राजकीय दौरा किया, जो नए नेतृत्व के तहत प्राप्त होने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बने। एक अभूतपूर्व हावभाव में, राष्ट्रपति दिसानायके ने समारोहिक स्वागत से लेकर संयुक्त सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थलों तक, पीएम मोदी के पूरे दौरे में व्यक्तिगत रूप से साथ दिया।

संविधान से...

हटाने के लिए औपचारिक रूप से कोई कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

राहुल गांधी और उनके पिछलग्गू विपक्षी नेता आरएएसएस महाचचिव दत्तात्रेय होसबोले के एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण को आधार बना कर संविधान संशोधन का शिगूफा छोड़ रहे हैं। होसबोले ने आपातकाल की चर्चा पर कहा था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इमरजेंसी के दरम्यान ही संविधान में जोड़े गए थे। जबकि इस पर पहले जनता की रायशुमारी होनी चाहिए थी। बस विपक्ष को यह पतंग मिल गया और वे उसे ही उड़ाने लगे और सरकार से जोड़ने का खेल करने लगे। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के सवाल पर अर्जुन मेघवाल ने कहा भी कि सेमिनार या विचार गोष्ठियों में कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी अगर ऐसी चर्चा करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि इसका सरकार की योजना से कोई लेना देना है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नवंबर 2024 में डॉ. बलराम सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया। इस फैसले में कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय संदर्भ में समाजवाद एक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है और निजी क्षेत्र के विकास में बाधा नहीं डालता, जबकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। लिहाजा, सरकार का आधिकारिक रुख यही है कि संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों पर पुनर्विचार करने या उन्हें हटाने की कोई योजना या इरादा नहीं है।

प्राचीन शिव मंदिर...

दोनों देश सीमा विवाद और मंदिरों पर अधिकार के मुद्दे को 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस- आईसीजे) ले गए। आईसीजे ने कंबोडिया के पक्ष में फैसला दिया। थाईलैंड ने फैसले के बाद इस मंदिर पर अधिकार छोड़ दिया। लेकिन मंदिर के आसपास के इलाकों को लेकर दोनों देशों में विवाद बना रहा। विवाद के चलते साल 2008 में दोनों देशों में संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों तरफ से 20 लोगों की मौत हुई और हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा था। इसके बाद कंबोडिया फिर से आईसीजे पहुंचा और आईसीजे ने फिर से कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और दोनों देशों का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कंबोडिया ने अपने यहां थाईलैंड की फिल्में और टीवी शो प्रतिबंधित कर दिए। साथ ही पड़ोसी देश से ईंधन, फल और सब्जियों का आयात बंद कर दिया। इतना ही नहीं कंबोडिया ने इंटरनेट और ऊर्जा क्षेत्र में भी थाईलैंड का बहिष्कार किया। गुरुवार को तनाव चरम पर पहुंच गया और टकराव शुरू हो गया। दोनों तरफ से गोलीबारी के आरोप लगे। शुक्रवार को यह संघर्ष और गंभीर होता दिख रहा है।

हजारों साल पुराने शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जंग छिड़ चुकी है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, जंग में फाइटर जैट भी कूद चुके हैं। माना जा रहा है कि इस युद्ध में चीन भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। यहां भी उसके दोनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि थाईलैंड के साथ आर्थिक साझेदारी ज्यादा चल रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि दबाव कंबोडिया पर बनाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है? भारत थाईलैंड का समर्थन करेगा या वो कंबोडिया के साथ जाएगा?

भारत हमेशा ऐसे मामले में बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसका भी अपना कारण है। बात चाहे थाईलैंड की हो या फिर कंबोडिया की, भारत के दोनों के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं। दोनों देशों के साथ अलग-अल क्षेत्रों में कई सालों से सहयोग चल रहा है। ऐसे में किसी एक देश को समर्थन कर भारत दूसरे के साथ रिश्ते बिगाड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। भारत के थाईलैंड के साथ रिश्ते काफी मजबूत हैं। दोनों ही देश इस समय मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक) का हिस्सा हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वजह से भी दोनों देशों में मजबूत साझेदारी है। भारत और थाईलैंड समय-समय पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। दोनों ही देशों की नौसेना भी समय-समय पर संयुक्त अभ्यास करती रहती है।

व्यापार के क्षेत्र में भारत और थाईलैंड के बीच 18 बिलियन डॉलर का कारोबार होता है। इंडो-आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत थाईलैंड में व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड ट्राइलेट्रल हाई-वे का जिक्र करना भी जरूरी है, इस एक हाई-वे की वजह से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी काफी मजबूत हो जाएगी।

दूसरी तरफ कंबोडिया थाईलैंड की तुलना में छोटा और कमजोर देश है। इसके साथ भी भारत के सांस्कृतिक, व्यापारिक रिश्ते हैं। भारत पिछले कई दशकों से कंबोडिया की आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के क्षेत्र में मदद कर रहा है। इसके ऊपर कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी भारत की मदद से हुआ है। भारत तो पिछले कई सालों से कंबोडिया की सेना को भी ट्रेन कर रहा है, वहां भी बड़े स्तर पर मदद दी जा रही है। बात चाहे काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग की हो या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की, भारत ने हमेशा कंबोडिया को सहारा दिया है। भारत और कंबोडिया में 300-400 मिलियन डॉलर का कारोबार है। यहां भी भारत अब आने वाले समय में एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर में भी अपनी साझेदारी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसके ऊपर कुछ समय पहले कंबोडिया मेकॉन्ग-गंगा कोऑपरेशन फ्रेमवर्क का भी हिस्सा भी बन चुका है, इससे भारत के साथ सांस्कृतिक, पर्यटन और शैक्षणिक रिश्ते अच्छे हुए हैं।

यहां पर एक समझने वाली बात यह भी है कि भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी में काफी मानता है, आसियान देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहे, इस बात को प्राथमिकता दी जाती है। मोदी सरकार के आने के बाद तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज्यादा बल मिला है। यहां भी चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भी आसियान देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की कवायद होती है। इसी वजह से जानकार मानते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में छिड़ी जंग न सिर्फ आसियान देशों के बीच जारी आपसी साझेदारी को झटका देगा बल्कि कहीं न कहीं भारत की रणनीति को भी नुकसान पहुंचाएगा।

इसी वजह से उम्मीद है कि भारत दोनों देशों के बीच शांति स्थापना की पूरी कोशिश करेगा। चीन की दुष्ट-नीति इसमें आड़े आ सकती है। चीन की रणनीति रही है कमजोर देशों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लेना। बात चाहे नेपाल की हो या फिर श्रीलंका की, वह ऐसा कर चुका है। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। चीन भारत को आगे बढ़ने और विस्तार करने का मौका नहीं देना चाहता। इसी वजह से इस युद्ध में भी अगर चीन कमजोर कंबोडिया का साथ देता है और भारत खुलकर थाईलैंड के समर्थन में उतर जाता है, तो यह हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए झटका होगा। कंबोडिया अगर चीन के और करीब गया तो उस स्थिति में भी चिंता भारत की बढ़ने वाली है।

शत्रु की शैतानी...

(एसआईआर) प्रक्रिया समेत कई मुद्दे उठाए हैं। हमने उन्हें बताया है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। उसके बाद हम तय करेंगे कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी।

उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में फंसे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। हमें किसी भी संदेह में नहीं रहना चाहिए। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की कार्यवाही लोकसभा में शुरू होगी। राज्यसभा में इसी तरह के प्रस्ताव के लिए विपक्ष की ओर से प्रायोजित नोटिस को उच्च सदन में स्वीकार नहीं किया गया है, जिससे निचले सदन में इस प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति की घोषणा करने की उम्मीद है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के अनुसार लोकसभा में कार्यवाही समाप्त होने के बाद कार्यवाही राज्यसभा में स्थानांतरित की जाएगी। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के 150 से अधिक सांसदों ने लोकसभा में नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे।

सबसे लंबा खेलने ...

दो पूर्ण कार्यकाल पूरा किया है। उनके नाम लगातार दो बार निर्वाचित होने वाले पहले और एकमात्र गैर-कांग्रेसी प्रधानंत्री होने का रिकॉर्ड भी है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने वाले पहले और एकमात्र गैर-कांग्रेसी नेता भी हैं। वह इंदिरा गांधी (1971) के बाद पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। पंडित नेहरू के अलावा वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार तीन आम चुनाव जीते हैं। वह सभी प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार छह चुनाव जीते हैं। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की।

6 साल में...

(2023-24) हो गया है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 58.2 प्रतिशत हो गया है। बेरोजगारी की दर 6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई है और युवा बेरोजगारी दर 17.8 प्रतिशत से घटकर 10.2 प्रतिशत हो गई है। यह वैश्विक औसत 13.3 प्रतिशत से कम है।

BOOK YOUR DISPLAY CLASSIFIED ADVERTISEMENTS AT
Timings : 9 am to 7 pm
Head office
SHREE SIDDIVINAYAK PUBLICATIONS
Plot No. A-23/5 & 6 2nd Floor,
APIE, Balanagar, Hyderabad - 500 037
City office
SHREE SIDDIVINAYAK PUBLICATIONS
4th Floor, 19 Towers (T19),
Near Bus Stand, Ranigunj,
Secunderabad - 500 003
8688868345

शुभ लाभ
म्हारो भाग्यनगर
दैनिक हिन्दी शुभ लाभ, हैदराबाद, शनिवार, 26 जुलाई, 2025

गोवत्स फाउण्डेशन
हैदराबाद
(Reg. No. 224/2013)
गोसेवा - धर्म सेवा!
गाय बचेगी,
हमारी संस्कृति बचेगी!
गौ रक्षा,
हमारी संस्कृति की रक्षा!
Scan for Donation
जय गो माता - जय गोपाल
सीए मुरली मनोहर पलोड़ 9849467807
ओमप्रकाश अग्रवाल 9246532277

अग्रसेन बैंक की नई उड़ान-चार नई शाखाओं का उद्घाटन कल से

उद्घाटन से पहले विशेष पूजा-अर्चना, ग्राहकों और शेयरधारकों में उत्साह

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। अग्रसेन बैंक ने अपनी उपलब्धियों की सूची में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए चार नई शाखाओं का उद्घाटन करने की घोषणा की है। शुक्रवार, दि. 25 जुलाई को बैंक के मुख्यालय में शुभारंभ से पहले विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के चेयरमैन प्रमोद कुमार केडिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने भाग लिया। इस अवसर पर बैंक के शेयरधारक और ग्राहक भी मौजूद रहे।

बैंक ने इसे अपनी निरंतर विकास यात्रा और ग्राहकों के विश्वास का प्रतीक बताया।

चार नई शाखाओं का उद्घाटन कार्यक्रम

अमीरपेट - ग्रीन पार्क होटल के सामने - 27 जुलाई 2025
गगन पहाड़, राजेंद्र नगर - 3 अगस्त 2025
कुकटपल्ली (मलिक प्लाज़ा, KPHB कॉलोनी) - 10 अगस्त 2025
माधापुर, विट्ठल राव नगर - शीघ्र उद्घाटन

नई जमा योजनाएं - ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर

-555 दिन की एफडी योजना - सामान्य ग्राहक: 9.00%, वरिष्ठ नागरिक: 9.50%

-फ्यूचर स्टार्स आरडी स्कीम - रु.5500 प्रतिमाह - 120 माह - 10.10 लाख, रु.14000 प्रति माह - 60 माह - 10.34 लाख।

बैंक प्रबंधन के अनुसार, ये योजनाएं ग्राहकों के दीर्घकालिक निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाने के लिए शुरू की गई हैं।चेयरमैन प्रमोद कुमार केडिया ने कहा, हमारे ग्राहकों और शेयरधारकों के विश्वास के बिना यह संभव नहीं था। नई शाखाओं के साथ हम और अधिक लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अग्रवाल समाज दोमलगुडा शाखा का अन्न प्रसाद कार्यक्रम सम्पन्न

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। अग्रवाल समाज, तेलंगाना की दोमलगुडा शाखा द्वारा संचालित अग्रसेवा योजना के तहत अमावस्या के अवसर पर एक अन्न प्रसाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अग्रवाल हेल्थ क्लिनिक परिसर के बाहर आयोजित किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में समाज के सदस्यों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा श्री अग्रसेन जी की पूजा-अर्चना के साथ हुई। इस अन्न प्रसाद सेवा में समाज के कई सदस्यों ने सहयोग किया, जिनमें प्रवीण-राजेश्वरी अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, सुषमा पंसारी, सोनल अग्रवाल, अनिल-दीपा गर्ग, विजय-मीना कुंछल, अनिल सराफ और अन्य प्रमुख थे। सीए यश गोयल और सीए तन्मय गुप्ता भी अपने परिवारों के साथ उपस्थित थे।

यह सेवा कार्य शाखा की महिला समिति के सहयोग और भगवान के मधुर भजनों के बीच संपन्न हुआ।

इस अवसर पर शाखा के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद थे, जिनमें परामर्शदाता गिरधारी लाल अग्रवाल और ओमप्रकाश पंसारी, अध्यक्ष डॉ. दिलीप पंसारी, उपाध्यक्ष योगेश अग्रवाल, सचिव प्रतीक अग्रवाल, सहसचिव विजय कुंछल और कोषाध्यक्ष रोशन लाल मित्तल शामिल थे।

इसके अलावा, केंद्रीय समिति सदस्य प्रदीप अग्रवाल और अनिल गर्ग, कार्यकारिणी सदस्य अजय गुप्ता, गोपाल अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, विकास अग्रवाल और रश्मि अग्रवाल सहित कई अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

श्री गोपाल गौशाला इब्राहिमपट्टनम में हारियाली अमावस्या मनाई गई

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री गोपाल गौशाला, इब्राहिमपट्टनम में भक्तों द्वारा हारियाली अमावस्या धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत गोमाता की पूजा-अर्चना और भोग लगाकर हुई, जिसके बाद भक्तों ने प्रसाद एवं झूलों का आनंद लिया।

मुख्य अतिथियों का स्वागत

इस अवसर पर विशेष रूप से पधारे अग्रवाल समाज-तेलंगाना के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ता एवं उपाध्यक्ष रूपेश अग्रवाल ने गोमाता की पूजा की और उन्हें चारा खिलाया। मंच संचालन करते हुए महावीर अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया और सभी को मंच पर आमंत्रित किया।

गौशाला के चेयरमैन तुलसीराम बंसल ने अग्रवाल समाज के सभी सदस्यों को एकजुट करने का आह्वान किया और समाज के कल्याण के लिए प्रयासों पर जोर दिया। अग्रवाल समाज-तेलंगाना के अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ता ने अगले दो वर्षों के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्योरा दिया, जिसमें समुदाय को डिजिटल कार्ड से जोड़ने और कर्मचारियों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने की योजना शामिल है।

उपाध्यक्ष रुपेश अग्रवाल ने युवा पीढ़ी को जोड़ने और परंपराओं को आधुनिक रूप देने पर बल दिया।

उन्होंने गौवंश के प्रति लोगों में संवेदनशीलता बढ़ाने की भी बात कही।

प्राणी मित्र संघ के जसमतभाई पटेल ने अपनी गतिविधियों का वर्णन किया और सरकार से गौशालाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग की मांग की।

गौशाला सहयोग कानून पर चर्चा

जसराज श्रीश्रीमाल ने अपने संबोधन में 2017 में पारित गौशाला सहयोग कानून की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने गौवंश को पकड़कर गौशाला में रखने और उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रावधानों का उल्लेख किया। गौशाला के मैनेजिंग ट्रस्टी महावीर प्रसाद ने समाज के पदाधिकारियों से गौशालाओं को सहयोग देने का आग्रह किया।

कार्यक्रम के अंत में गौशाला की ओर से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

अग्रवाल समाज-वनस्थलीपुर शाखा के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद जसमतभाई पटेल ने अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम शांति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ।

श्री आईजी गौशाला में नवीन शेड का उद्घाटन, कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। श्री आईजी गौशाला में नवीन शेड के उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों और गौभक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री आईजी गौशाला के अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, सचिव हुकमाराम सानपुरा, सह सचिव ढगलाराम सेपटा, कोषाध्यक्ष नारायणलाल परिहार, और सलाहकार डायाराम लचेटा, भंवरलाल मुलेवा तथा पारसमल शर्मा उपस्थित रहे।समारोह में सीरवी समाज पारसीगुटा वडेर के अध्यक्ष मोहनलाल हाम्बड़, सीरवी समाज कोरेमुला वडेर के अध्यक्ष कालुराम काग, राजस्थान के बुलादा से पधारे उप सरपंच भंगाराम प्रजापत और लुंबाराम गुर्जर, चेन्नई से आए केसराराम, महाबलिपुरम बडेर के कोषाध्यक्ष बुधाराम, विजयराज, सचिव शेषाराम और चेन्नई के महिला मंडल से कमला बाई, रामुबाई, भंवरी बाई, गीत, मैना देवी तथा प्रेमा देवी भी मौजूद रहीं। इस दौरान श्री आईजी गौशाला की समस्त कार्यकारिणी और सभी गौभक्तों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

तेरापंथ किशोर मंडल ने आयोजित की वर्षा राहत सेवा

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। तेरापंथ युवक परिषद - हैदराबाद के नेतृत्व में तेरापंथ किशोर मंडल - हैदराबाद ने 23 जुलाई 2025 को वर्षा राहत सेवा का आयोजन किया। यह एक मानवीय पहल के तहत जरूरतमंदों की मदद के लिए शुरू की गई।

सेवा कार्य से पूर्व, मंडल के 30 किशोरों ने साध्वीश्री डॉ. गवेषणा श्री जी (आदि ठाणा-4) के दर्शन किए और सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साध्वीश्री के प्रेरणादायक उपदेशों ने किशोरों में सेवा की भावना को और गहरा किया।

साध्वीश्री डॉ. गवेषणा श्री जी के मंगलपाठ के साथ रात 8:00 बजे से सेवा यात्रा शुरू हुई। किशोरों ने सिकंदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को वर्षा से बचाने के लिए रेनकोट वितरित किए।

यह सेवा केवल वस्त्र वितरण तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह मानवता, करुणा और सहयोग की जीवंत अभिव्यक्ति बन गई।

गौमाता के लिए प्रतिदिन एक रुपये दान योजना का ज़ोरदार प्रचार-प्रसार

लव फॉर काऊ फाउण्डेशन ने कई कार्यक्रमों का किया आयोजन

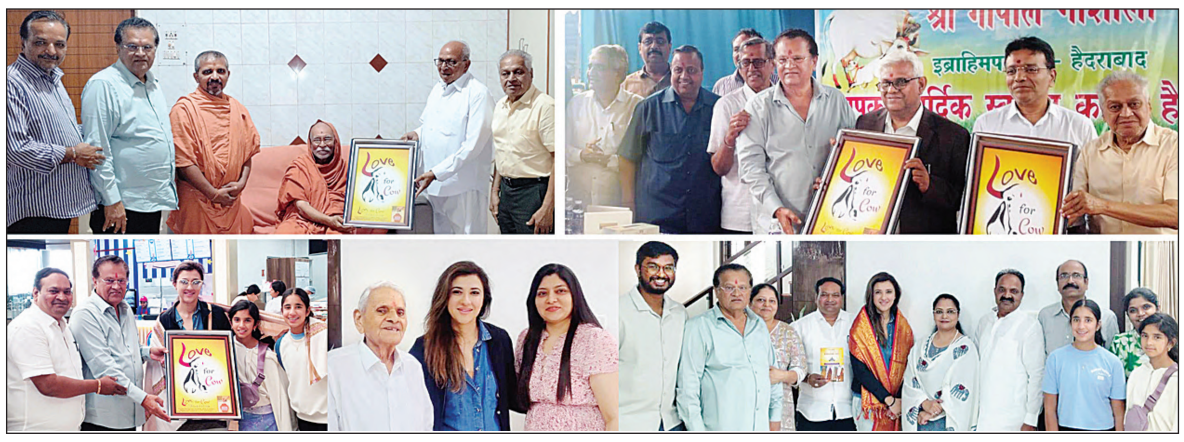

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।

गौमाता की सेवा के लिए 'लव फॉर काऊ फाउण्डेशन' द्वारा चलाए जा रहे 'प्रतिदिन एक रुपये दान योजना' अभियान का विभिन्न क्षेत्रों में ज़ोरदार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस अभियान के तहत, फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने हाल ही में कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

फाउंडेशन की ट्रस्टी रंजना शाह और वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पदाधिकारियों ने मोइनाबाद स्थित स्वामीनारायण गुरुकुल में राजकोट से पधारे पूज्यपाद गुरुदेव श्री देवकृष्णादासजी स्वामी का स्वागत किया। इस अवसर पर जसमत पटेल, सुखवल्लभदास स्वामी, हरजीवन पटेल और अन्य उपस्थित थे। इसके साथ ही, इब्राहिमपट्टनम स्थित श्री गोपाल गौशाला में अग्रवाल समाज तेलंगाना के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिरुद्ध अग्रवाल और उपाध्यक्ष रूपेश अग्रवाल का अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन कार्यक्रम में फाउंडेशन की ओर से जसमत पटेल, जसराज श्रीश्रीमाल, तुलसीराम बंसल और महावीर प्रसाद अग्रवाल मौजूद थे।

वहीं, हैदराबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से लौटीं प्रसिद्ध हिंदी और तेलुगु फिल्म अभिनेत्री साक्षी शिवानंद से मुलाकात की गई। उनसे 'लव फॉर काऊ' और 'ऑल इंडिया ओल्ड टेम्पल ट्रस्ट' से जुड़ने का अनु-रोध किया गया। इस दौरान पटेल निवास पर नानजीभाई पटेल, जसमत पटेल, निरंजन रेड्डी, आर.के. जैन, डॉ. गीतांजलि, दक्षा पटेल और पूजा पटेल ने उनका अभिनंदन किया।फाउंडेशन के चेयरमैन जसमत पटेल ने बताया कि इस अभियान के तहत गौ ग्रास के लिए दान पात्रों का वितरण और प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना को शुरू हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अगले एक वर्ष में 20 हज़ार दान पात्र वितरित करने की योजना है। उन्होंने सभी गौभक्तों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, बच्चों के जन्मदिन या पितरों की पुण्यतिथि जैसे किसी भी शुभ अवसर पर गौमाता के लिए दान देकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। उन्होंने 'बूंद-बूंद से सागर भरता है' की कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि यदि हम प्रतिदिन गौमाता के लिए एक रुपया निकालते हैं, तो यह एक छोटी रकम लगती है, लेकिन जब यह एक विशाल रूप धारण करता है तो इससे बड़ी राशि जमा हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप हम एक बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं।गुरुदेव देवकृष्णदासजी ने स्वयं गौ दान पात्रों में दान राशि डालकर इस अभियान में सहयोग किया। उन्होंने सभी भक्तों से कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद हम यथासंभव अपने परिवार में गाय के दूध का ही प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही, अपने इष्ट मित्रों को भी गाय के दूध का उपयोग करने की प्रेरणा देंगे। उन्होंने कहा कि गौभक्ति के प्रति यह हमारा संकल्प है।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तिः

चेयरमैन जसमत पटेल, सलाहकार नानजीभाई पटेल, हरजीवन पटेल, जसराज श्रीश्रीमाल, तुलसीराम बंसल, महावीर अग्रवाल, निरंजन रेड्डी, आर.के. जैन, डॉ. गीतांजलि, दक्षा पटेल, पूजा पटेल, रिद्धीश जागीरदार, मुकेश चौहान, तरुण मेहता, सीरवी समाज महिला मंडल से कमला बाई, रामू बाई, भंवरी बाई, गीत, मैना देवी, प्रेमा देवी और अन्य कई गौभक्त मौजूद थे।

फर्टी9 फर्टिलिटी सेंटर ने वर्ल्ड आईवीएफ डे पर

दक्षिण भारत का पहला एआई-संचालित सीमेन एनालाइज़र लॉन्च किया

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।

वर्ल्ड आईवीएफ डे के अवसर पर, फर्टी9 फर्टिलिटी सेंटर ने शुक्रवार को अपने सिकंदराबाद स्थित केंद्र में ङशपीकेज्ञश द12 झठज, एक उन्नत एआई-संचालित सीमेन एनालाइज़र, लॉन्च किया।

यह उपलब्धि फर्टी9 को दक्षिण भारत का पहला आईवीएफ सेवा प्रदाता बनाती है, जिसने पुरुष बांझपन के मूल्यांकन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से इस अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक टूल को अपनाया है।

लोकप्रिय अभिनेत्री लया की उपस्थिति ने इस अवसर को और खास बना दिया। इस कार्यक्रम में उन जोड़ों को भी आमंत्रित किया गया, जिन्होंने फर्टी9 की मदद से संतान प्राप्त की है। इस मौके पर TogetherInIVF अभियान की भावना को दर्शाते हुए केक काटा गया।

बांझपन के प्रति जागरूकता की जरूरत – डॉ. ज्योति सी. बुड़ी और वीनेश गाडिया

फर्टी9 की मेडिकल डायरेक्टर डॉ. ज्योति सी. बुड़ी और सीईओ एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीनेश गाधिया ने समाज में बांझपन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़े सामाजिक कलंक को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया।

गाडिया ने कहा, बांझपन कोई व्यक्तिगत असफलता नहीं, बल्कि एक चिकित्सकीय समस्या है। उन्होंने हाल ही में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि भारत की प्रजनन दर 1.9 है, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है।

गाधिया ने बताया, 50 प्रतिशत बांझपन के मामले पुरुषों से संबंधित होते हैं, लेकिन 95 प्रतिशत परामर्श महिलाओं द्वारा ही शुरू किए जाते हैं। पुरुष अक्सर जांच के लिए आगे नहीं आते, जबकि यह संतुलन जरूरी है।

एआई-संचालित सीमेन एनालाइज़र – एक गेम चेंजर

नव-लॉन्च किया गया एआई-संचालित सीमेन एनालाइज़र पारंपरिक तरीकों की तुलना में कई गुना बेहतर है।पहले जहां एक एंड्रोलॉजिस्ट मैन्युअल रूप से सीमेन की जांच करता था, अब यह उन्नत प्रणाली सिर्फ छह मिनट में सटीक परिणाम देती है।यह मानवीय त्रुटियों को समाप्त कर, सटीकता बढ़ाता है और सबसे सामान्य आकार के स्वस्थ शुक्राणुओं का चयन करता है, जिससे नैदानिक परिणाम बेहतर होते हैं।इसके अलावा यह डीएनए फ्रैगमेंटेशन की जानकारी भी देता है, जिससे गर्भपात की संभावना कम होती है और गर्भधारण की सफलता दर बढ़ती है।

समाज में जागरूकता बढ़ाने की अपील – अभिनेत्री लया

अभिनेत्री लया ने डॉक्टरों की बातों का समर्थन करते हुए कहा, लोग अक्सर मानते हैं कि समस्या महिलाओं में है, जबकि आधे मामले पुरुषों से जुड़े होते हैं। प्रजनन संबंधी समस्याओं को डायबिटीज जैसी सामान्य बीमारी की तरह देखना चाहिए। समय पर विशेषज्ञ सलाह लेने से वर्षों की परेशानी बच सकती है।उन्होंने फर्टी9 की तकनीकी प्रगति और सामाजिक प्रतिबद्धता की सराहना की।इस कार्यक्रम में फर्टी9 के चिकित्सा विशेषज्ञ, मीडिया प्रतिनिधि और आईवीएफ उपचार से लाभान्वित दंपत्ति भी उपस्थित थे।

शेयर मार्केट

बीएसई : 81,463.09
-721.08 -0.88% ↓

एनएसई :24,837.00
-225.10 (-0.90%) ↓

कार्टून कॉर्नर

मौसम हैदराबाद

अधिकतम : 26^0
न्यूनतम : 23^0

सर्राफ़ा बाज़ार

(24 कैरेट गोल्ड)

सोना : 1,01,160/- (प्रति 10 ग्राम)

चाँदी : 1,15,890/- (प्रति किलोग्राम)

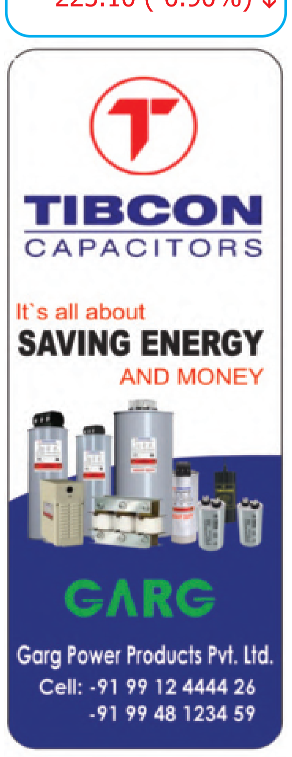

राधे राधे ग्रुप द्वारा अपने नियमित अन्नदान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को नामपल्ली स्थित पब्लिक गार्डन, पिलर नं. 1265 के समीप जरूरतमंद लोगों को अल्पाहार वितरित किया गया। इस अवसर पर राधे राधे ग्रुप के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जरूरतमंदों की सेवा की।

अग्रवाल समाज मलकपेट शाखा युवा मोर्चा की मासिक बैठक संपन्न

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।

अग्रवाल समाज मलकपेट शाखा युवा मोर्चा की मासिक बैठक आनंद नगर, मलकपेट स्थित नितिन अग्रवाल के निवास पर संपन्न हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।

युवा मोर्चा के संयोजक हर्ष बंसल ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। बैठक के दौरान, सावन की सैर के अवसर पर एक क्रिकेट प्रतियोगिता, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन कार्यक्रम और एक बाइक रैली निकालने पर विचार-विमर्श हुआ।इस अवसर पर, अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट (आत्म गौरव भवन) के अध्यक्ष चुने जाने पर युवा मोर्चा सदस्य अक्षय अग्रवाल को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

बैठक का सफल आयोजन भाग्यलक्ष्मी ढाबा में सहभोज के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर हर्ष बंसल, आशीष बंसल, जितेंद्र गोयल, नितेश अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, नितिन श्रवण अग्रवाल, श्रवण अग्रवाल, निश्चिंत अग्रवाल, किशन जैन, मनीष सिंघल, धरवेश गोयल, विशेष सिंघानिया, रोहित अग्रवाल, शैंकी अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, आयुष गोयल, अक्षय अग्रवाल और कुणाल अग्रवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

राधे राधे ग्रुप द्वारा अपने दूसरे केंद्र पर भी नियमित अन्नदान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बेगम बाजार गौशाला के समीप माता के मंदिर के पास जरूरतमंद लोगों को अल्पाहार वितरित किया गया। ग्रुप के सदस्यों ने इस सेवा कार्य में सक्रिय योगदान दिया। इस अवसर पर राधे राधे ग्रुप के सदस्यों एवं अन्य उपस्थित थे।

अग्रवाल समाज मलकपेट शाखा द्वारा मासिक अन्नप्रसाद का आयोजन, 650 लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।

अग्रवाल समाज की मलकपेट शाखा के तत्वावधान में प्रतिमाह की तरह इस बार भी मासिक अन्नप्रसाद का आयोजन गंज स्थित अग्रसेन हॉल के पास किया गया। इस सेवा कार्यक्रम में करीब 650 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।इस अवसर पर शाखा के कई पदाधिकारी और सदस्यों ने अपनी सेवाएँ प्रदान कीं। इनमें अध्यक्ष पंकज कुमार संघी, उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, मंत्री प्रदीप बंसल, सह मंत्री शैलेश अग्रवाल और केंद्रीय समिति सदस्य सुरेश गुप्ता व गोविंद नारायण मोदी शामिल थे।

इसके अलावा, परामर्शदाता महावीर प्रसाद अग्रवाल, ओमप्रकाश पचेरिया, श्याम सुंदर अग्रवाल, सुरेश गोयल, गोपाल मोदी, निश्चिंत अग्रवाल, शीतल रूंगटा और स्वाति अग्रवाल ने भी अन्नप्रसाद वितरण में सहयोग दिया।

अग्रवाल मानव सेवा मंच का 191वाँ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर 27 कल

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।

अग्रवाल मानव सेवा मंच द्वारा 191वाँ निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर 27 जुलाई 2025, रविवार को आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर हैदराबाद के अशोक नगर स्थित सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी (पीएनटी कॉलोनी के सामने) में होगा।यह स्वास्थ्य शिविर श्री छगनलाल गुप्ता की स्मृति में मेसर्स मंगतराय रामकुमार ज्वैलर्स, हैदराबाद के सौजन्य से आयोजित किया गया है। इसमें हैदराबाद सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी प्रबंधन का भी सहयोग रहेगा।इस शिविर में किम्स फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर, सिकंदराबाद द्वारा सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की जाएंगी।अग्रवाल मानव सेवा मंच और हैदराबाद सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी प्रबंधन ने स्थानीय निवासियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का निवेदन किया है। अधिक जानकारी के लिए, संयोजक श्याम सुंदर अग्रवाल से मोबाइल नंबर 9014573582 पर संपर्क किया जा सकता है।

दक्षिण मध्य रेलवे
हमें SCRailwayindia पर फॉलो करें
द.म. रेलवे की निविदा सूचनाओं के विवरणों को हमारी वेबसाइट : www.scr.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है

निविदा सूचना सं. 30/2025 दिनांक 25.07.2025 PUB/0902

भंडार आपूर्ति ई-खरीद निविदा सूचना:- निम्नलिखित निविदाएँ ऑनलाइन जारी की गयी हैं। निविदादाताओं से आग्रह है कि वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें और अपने प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा करें। निविदा विवरण, मात्रा, पूधरा एवं एसडी वेबसाइट में देखी जा सकती है । व्यक्तिक प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा । डाक द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा बन्द होने का समय निविदा की नियत तिथि को 14.30 बजे है । **सभी देशज प्रस्तावों के लिए पूधरा को www. ireps. gov.in पर उपलब्ध अनुसार ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा।**

निविदा सं.	संक्षिप्त विवरण
LN255276A	एलएचबी अंडर फ्रेम के लिए हेड स्टॉक सीपीएल
81255002	शील्डिंग गैस
LN2555960	रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट पूर्ण
29251414	WAG-9 लोको के लिए सेकेंडरी हॉरिजॉन्टल डैम्पर
31251662	गैर-एस्बेस्टस आधारित K प्रकार
33251330	गैर-एस्बेस्टस आधारित ऑर्गेनिक ब्रेक पैड
29251082	WAG-9 (नई श्रृंखला) लोको के लिए पिनियन शाफ्ट 21 दांत
29251243	WAG-9 लोको के लिए बुल गियर 107 दांत।
25253459	पैंटोग्राफ, प्रकार AM12 पूर्ण
52255011	IP आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली की आपूर्ति
56255203	(HASSDAC)
80251215	शेल गैडस एस5 वी 42 पी 2.5 ग्रीस
77251145A	रेडी मिक्स्ड पेंट रेड ऑक्साइड
60256547	एंड कट मेटल लाइनर ड्रग.नं. टी-4511/3740
LN255540	भित्तिचित्र-रोधी पारदर्शी कोटिंग की आपूर्ति एवं अनुप्रयोग
38255011	संशोधित इलास्टोमेरिक पैड (डिज़ाइन-इ)
67245007A	30/05 टन क्षमता की आपूर्ति, स्थापना एवं कमीशनिंग
56251187	जेली से भरी 6 क्वाड केबल
38252293	वितरक के लिए ओएच किट
56251006	पीवीसी केबल आकार 30 कोर X1.5 वर्ग मिमी

नोट: निविदा खोलने की अंतिम तिथि: SL.No.01 on dt. 04.08.2025. SL.No. 02 on dt. 11.08.2025. SL.No. 03 to 05 on dt. 13.08..2025. SL.No.06 to 09 on dt.14.08.2025.SL No.10 to 13 on dt 18.08.2025 SL.No 14 on dt. 19.08.2025. SL.No. 15 on dt. 20.08.2025 SL. No. 16 on dt. 21.08.2025 SL. No. 17 on dt. 25.08.2025. SL. No.18 on dt. 28.08.2025 SL.No. 19 on dt. 20.08.2025. SL. No. 20 on dt. 08.09.2025

उपर्युक्त निविदाओं के अतिरिक्त, रु.50 लाख रुपये से अधिक की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऊपर दी गई रेलवे वेबसाइट देखें।

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक/सिकंदराबाद

कोटेशन आमंत्रण सूचना PUB/0903

कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यरत उप मुख्य मुख्य अभियंता/सी-II/एससी, संगठन, निर्माण, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित हैं:

कोटेशन सूचना संख्या: 05/उप मुख्य अभियंता/सी/II/2025-26 दि. : 24/07/2025 **कार्य का नाम:** मोटुमारी-विष्णुपुरम दोहरीकरण परियोजना - रेलवे सीमा के भीतर किमी 1.10 और किमी 27.30 (मोटुमारी-जगय्यापेट टाउन खंड) के बीच विभिन्न प्रजातियों के 1183 पेड़ों की कटाई, निष्कर्षण और परिवहन, जिसमें रेलवे द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा पूरी बची हुई लकड़ी को अपने पास रखना शामिल है। **आरक्षित लागत:** 61,37,384.00/- **पूधरा:** 1,22,800.00/- **समापन अवधि**: 02 (दो) महीने। **खोलने की तिथि:** 06/08/2025 11:30 बजे

1. बोली दस्तावेज़ और अन्य विवरणों के लिए, कृपया उप मुख्य अभियंता/सी-II/एससी के कार्यालय से संपर्क करें। 2. बोलीदाताओं के कोटेशन उप मुख्य अभियंता/सी-II/एससी के कार्यालय में उपलब्ध कोटेशन बॉक्स में 06.08.2025 को सुबह 11:00 बजे तक डाले जा सकते हैं। 3. अग्रिम राशि वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/निर्माण/एस.सी. रेलवे, सिकंदराबाद के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जानी चाहिए, अन्यथा कोटेशन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,निर्माण, सिकंदराबाद

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (http://ireps.gov.in के माध्यम से) PUB/0904

कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यरत वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता, कर्षण वितरण, सिकंदराबाद द्वारा एकल पैकेट निविदा प्रणाली में निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित हैं।

निविदा संख्या/निविदा सं.: C/E.29/TRD/SC/38/2025-26 दिनांक 24.07.2025 कार्य का नाम: ओएच प्रभाग के KZJ-BPQ खंड पर OHE मापदंडों की स्टेंसिलिंग अनुमानित लागत: रु. 39,75,000/- समापन अवधि: 180 दिन समापन तिथि: 18.08.2025 को 15:00 बजे

1) बोली दस्तावेज़ और अन्य विवरणों के लिए, कृपया वेबसाइट http://ireps.gov.in पर लॉग इन करें। 2) निविदाकर्ताओं को केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से भाग लेना चाहिए और किसी भी मैन्युअल प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। 3) सभी संभावित निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निविदा फॉर्म और ईएमडी की लागत केवल ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ही जमा करें। 4) सभी संभावित निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे जीएसटीआईएन पहचान संख्या प्राप्त करें और अपने प्रस्तावों के साथ जमा करें। 5) निविदाकर्ता को निविदा जमा करने की अवधि शुरू होने की तारीख तक किसी भी शुद्धिपत्र (केवल ऑनलाइन जारी) पर नज़र रखनी चाहिए।

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता, टीआरडी, सिकंदराबाद

खुली ई-निविदा सूचना सं.: C/E.29/Electic/M/SC/27/P-/OT/2025-26 दि. : 24.07.2025 PUB/0905

कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे दिए गए कार्य के लिए 14.08.2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित हैं।

ई-निविदा सं.: C/E.29/Electic/M/SC/27/P-/OT/2025-26 ई-निविदा संख्या: E-M-SC-27-OT-2025-26 कार्य का नाम: सिकंदराबाद विद्युत अनुरक्षण विभाग (i) बीदर में द्वितीय प्रवेश द्वार में सुधार, अग्रभाग कार्य और पे एंड यूज़ शौचालय ब्लॉक का निर्माण (ii) अमृत भारत स्टेशन योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत मौजूदा स्टेशन भवन का विघटन और परली वैजनाथ में नए स्टेशन भवन, पार्सल कार्यालय, विश्राम कक्ष, सड़क, भूदृश्यांकन और प्लेटफार्म में सुधार का निर्माण। - विद्युत व्यवस्था। **निविदा मूल्य:** रु.2,92,37,835.32 ईएमडी: रु.2,96,200.00 सीटीएफ: 0.00 समापन अवधि: 6 महीने।

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (एम), सिकंदराबाद

ई-निविदा सूचना सं. : 04 से 05 PUB/0906

कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यरत,मंडल विद्युत अभियंता (एम), गुंटूर, द्वारा आईआरईपीएस पोर्टल www.ireps.gov.in के माध्यम से निम्नलिखित ई-निविदाएँ आमंत्रित हैं।

क्रम संख्या: 1 निविदा संदर्भ संख्या: जीएनटी-जीएस-ईएलई-04-2025-26 दिनांक: 23.07.2025 निविदा शीर्षक: जीएनटी प्रभाग:- एबीएसएस-विद्युत व्यवस्था के अंतर्गत जीएनटी, एनआरटी और एमआरके स्टेशनों पर 12.0 मीटर चौड़े गैंगवे के साथ नए एफओबी का प्रस्तावित निर्माण। लगभग। मूल्य: 2,81,62,960.44 बयाना राशि जमा: 2,90,800.00 निविदा प्रपत्र की लागत (वापसी योग्य नहीं): 0

क्रम संख्या: 2 निविदा संदर्भ संख्या: GNT-GS-ELE-05-2025-26 दिनांक: 23.07.2025 निविदा शीर्षक: GNT प्रभाग:- ABSS-विद्युत व्यवस्था के अंतर्गत NLDA, PGRL, NDL और चठ्रक्ष- स्टेशनों पर 12.0 मीटर चौड़े गैंगवे सहित नए ऋजइ का प्रस्तावित निर्माण। अनुमानित मूल्य: 2,86,43,517.45 बयाना राशि जमा: 2,93,200.00 निविदा प्रपत्र की लागत (वापसी योग्य नहीं): 20 ई-बोली ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 21-08-2025 को 15.30 बजे तक।

आगे कोई भी सूचना/शुद्धिपत्र केवल ई-पोर्टल www.ireps.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

A1108 **मंडल विद्युत अभियंता/एम/गुंटूर**

अतिरिक्त निविदा शर्तों/विवरणों के लिए और निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए कृपया वेबसाइट : www.ireps.gov.in या http://www.scr.indianrailways.gov.in देखें।

DAILY शुभ लाभ Classifieds FIND BUY SELL

CHANGE OF NAME & DOB
I, R NASSAMAL Mother of Service No.JC 289060L Sub(DS) T JOHN ISSAC, Resident of Vill and PO:Keezlkulam, Teh:Vilvancode, Dist:Kanyakumari, Tamilnadu-629153 have changed my name and DOB from R NASSAMAL, DOB:01-07-1953 to NESAMMAL THANGAPPAN, DOB:07-01-1953 vide affidavit dt:25-7-2025 before CVN Ramakrishna, Advocate and Notary, Secunderabad.

CHANGE OF NAME & DOB
I, E THANKAPPAN father of Service No.JC 289060L Sub(DS) T JOHN ISSAC, Resident of Vill and PO:Keezlkulam, Teh:Vilvancode, Dist:Kanyakumari, Tamilnadu-629153 have changed my name and DOB from E THANKAPPAN, DOB:01-07-1947 to THANGAPPAN, DOB:07-01-1938 vide affidavit dt:25-7-2025 before CVN Ramakrishna, Advocate and Notary, Secunderabad.

CHANGE OF NAME & DOB
I, Army No.JC 736600A Nb Sub MANOJ KUMAR MOHAPATRA of Unit:01 TrgBn, AOC Centre, Secunderabad, Telangana hereby state that my father name and DOB is to be changed from MAGUNI MOHAPATRA, DOB:03-07-1952 to MAGUNI CHARAN MOHAPATRA, DOB:01-01-1954.

CHANGE OF NAME & DOB
I, Army No.JC 735936N Sub GHISA RAM of AdmBn, AOC Centre, Secunderabad, Telangana hereby state that my mother name and DOB is to be changed from SHARLA DEVI, DOB:10-02-1954 to SHRAWAN, DOB:01-01-1955.

CHANGE OF NAME
I, Service No.JC 289060L Sub(DS) T JOHN ISSAC, Resident of Vill and PO:Keezlkulam, Teh:Vilvancode, Dist:Kanyakumari, Tamilnadu-629153 hereby declare that my daughter name is to be changed from J DEETHEYA to DEETHEYA J vide affidavit dt:25-7-2025 before CVN Ramakrishna, Advocate and Notary, Secunderabad.

CHANGE OF NAME
I, Service No.JC 289060L Sub (DS) T JOHN ISAAC, Resident of Vill and PO:Keezlkulam, Teh:Vilvancode, Dist:Kanyakumari, Tamilnadu-629153 hereby declare that my son name is to be changed from J DAN ISAAC to DAN ISAAC J vide affidavit dt:25-7-2025 before CVN Ramakrishna, Advocate and Notary, Secunderabad.

CHANGE OF NAME
I, P KRISHNAVENI Spouse of Service No. 21009765N Hav (GNR) VIGNESH T, Resident of 3/56, Kovil Street, Semmetupatti, Viruveedu Post, NilakottaiTaluk, Sekkapati, Dindigul, Tamilnadu-624220 have changed my name from P KRISHNAVENI to V KRISHNAVENI vide Affidavit dated:25-7-2025 before CVN Ramakrishna, Advocate and Notary, Secunderabad.

किनवट में रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज की समस्या का हल, विधायक केराम के प्रयासों को मिली सफलता

किनवट, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। शहर के शिवाजी नगर परिसर में रेलवे अंडरब्रिज को लेकर लंबे समय से चली आ रही समस्या अब हल होने की कगार पर है। किनवट के विधायक भीमराव केराम के लगातार प्रयासों के बाद, रेलवे प्रशासन ने पुराने रेलवे फाटक की जगह पर नया अंडरब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, उसी स्थान पर ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। इन फैसलों से नागरिकों में खुशी का माहौल है।

विधायक भीमराव केराम ने शिवाजी नगर परिसर में बन रहे रेलवे अंडरब्रिज की समस्या को लेकर केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत के बाद, 26 जून को दिल्ली में एक बैठक हुई। इसके बाद, आयोग के आदेशानुसार 28 जून को संबंधित अधिकारियों और विधायक भीमराव केराम ने किनवट में अंडरब्रिज स्थल का जायजा लिया।

इस सिलसिले में, 22 जुलाई को दिल्ली में एक और बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक भीमराव केराम, किनवट के सहायक जिलाधिकारी झेनिथ चंद्रा दोंतुला, सिकंदराबाद रेलवे के मुख्य अभियंता और नांदेड़ मंडल रेलवे कार्यालय के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में रेलवे प्रशासन ने यह स्वीकार किया कि पहले इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही और अंडरब्रिज की वास्तविक आवश्यकता का सही आकलन नहीं किया गया था। इसी गलती के कारण गलत जगह पर एक छोटा अंडरब्रिज बनाया गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थीं।

रेलवे प्रशासन ने विधायक भीमराव केराम द्वारा सुझाए गए स्थान पर, जहाँ पहले रेलवे फाटक था, 3 मीटर चौड़ा नया अंडरब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी है। इसी बीच, विधायक केराम ने 26 जून को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र सौंपकर शहर से गुजरने वाले शिवाजी नगर परिसर के रेलवे फाटक की जगह पर एक ओवरब्रिज (उड़ानपुल) बनाने का अनुरोध किया था। 5 जुलाई को रेल मंत्री वैष्णव ने इस पत्र का जवाब देते हुए रेलवे विभाग को इस स्थल पर ओवरब्रिज की संभावना का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण का आदेश दिया।

रेल मंत्री के इस निर्णय से एसवीएम परिसर के निवासियों के साथ-साथ इस मार्ग से जुड़े 20 गाँवों की यातायात और वाहनों की समस्या हल होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। नागरिकों में इस फैसले को लेकर संतोष का माहौल है। इस महत्वपूर्ण सफलता ने एक बार फिर सामाजिक और नागरिक समस्याओं के प्रति विधायक भीमराव केराम के सक्रिय योगदान को उजागर किया है।

दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवाएँ

कागज़नगर, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। मंडल शिक्षा अधिकारी वसाला प्रभाकर ने बताया कि कागजनगर मंडल शिक्षा संसाधन केंद्र स्थित भाविता केंद्र में दिव्यांग छात्रों के लिए आज से निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं।

निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवाएँ डॉ. प्रवीण कुमार फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को दिव्यांग छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने मंडल के 0 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग छात्रों को इन सेवाओं का लाभ उठाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में मंडल के संकुल प्राचार्य और भाविता केंद्र समन्वयक सतीश और स्वरूप ने भाग लिया।

कागजनगर के अनेक वार्डों में आवारा कुत्तों का आतंक

लोगों ने नगर निगम अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की

कागज़नगर, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। कागज़नगर कस्बे की श्रीनगर कॉलोनी में आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी मौजूदगी स्थानीय लोगों के लिए कई तरह की परेशानियाँ पैदा कर रही है। हर सुबह और शाम, स्कूली बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमले से बच्चे दहशत में हैं। वाहन चालकों पर भी उनके हमले बढ़ गए हैं। खासकर रात में, बाइक सवारों को आवारा कुत्तों के झुंड का सामना करना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोग नगर निगम अधिकारियों से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कॉलोनी में घूम रहे कुत्तों को पकड़कर उन्हें हटाने की सख्त ज़रूरत है।

सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

मंचेरियाल, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पेंटा राजैया और नगर अध्यक्ष गदेसात्यम ने मांग की है कि शहरी विकास निधि से मंचेरियल नगर पालिका के मुख्य मार्ग पर चार इलाकों में 4 करोड़ रुपये की लागत से बने जंक्शनों को तोड़कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए उन्होंने मंचेरियाल कलेक्टर कार्यालय के एओ को एक याचिका सौंपी उन्होंने कहा कि 20 महीने पहले बने जंक्शनों को तोड़ दिया गया है और विधायक पीएसआर ने खुद कहा था कि कांग्रेस सरकार आने के बाद हुई नगर निगम बैठक में जंक्शनों की चौड़ाई कम करने का निर्णय लिया गया था लेकिन इसके उलट जंक्शनों को तोड़ दिया गया उन्होंने मांग की कि जनता के करोड़ों रुपये बर्बाद करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए उन्होंने कहा कि बीआरएस द्वारा बनाए गए चारों जंक्शनों की आईबी पर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ संसद का मॉडल स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ।

लेकिन इसमें कुछ देरी हुई उन्होंने कहा कि वेंकटेश्वर टॉकीज़ चौराहे पर विभिन्न जातियों के लोगों की आदर्श मूर्तियाँ स्थापित की गई है बेलमपल्ली चौराहे पर तीनों सेन-ाओं की आदर्श मूर्तियाँ स्थापित की गई है और लक्ष्मी टॉकीज़ चौराहे पर प्रकृति से जुड़ी विभिन्न आकृतियों के मॉडल स्थापित करके उन्हें सुंदर बनाया गया है उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि जहाँ कहीं भी दुर्घटनाएँ नहीं हुई है वहाँ अचानक से उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है उन्होंने कहा कि जंक्शनों को ध्वस्त करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है उन्होंने माँग की कि करोड़ों रुपये बर्बाद करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उनसे धनराशि वसूल की जाए कलेक्टर कार्यालय एओ को सौंपी गई।

वाहन चोरी करने पर 2 वर्ष की जेल 500 रुपए जुर्माना

जागतियाल, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। जागतियाल जिले धर्मपुरी पुलिस थाने में शब्बीर अहेमद बेग 14 -05 -2024 को एक फिरयाद दाखिल किया जिस में लिखा के अपने माकन के सामने से ढड 21 ऋ 0519 गाड़ी नंबर पल्सर सवेरे चोरी की गयी इस फिरयाद पर पुलिस ने केस दर्ज किया और जानकारी कर ने लगे तो तब सब इनस्पेक्टर ऑफ़ पुलिस उदय कुमार मौजूद थे अपने सिभंधि के अनुसार महेश को लेकर कुछ चोरो को तहकिकः आरम्भ की थिए गुर्रम कोटेश्वर को पुलिस की हिरासत में लिया गया जिस की उम्र 29 साल और खम्मम का बताया गया और इस को पोलिकेहिरासत में लिया और न्याय लाये में पब्लिक प्रस्कियुटर ने इस बात को साबित किया तो इस चोर को 2 साल और 500 रुपये सुनाई गयी ।

कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी

कांग्रेसी नेता कार्यक्रमों में भाग लेने और राशन कार्ड बांटने पर बने चर्चा का विषय

मंचेरियाल, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। कांग्रेस नेताओं को सरकारी कार्यक्रमों और सरकारी खर्च पर आयोजित कार्यक्रमों में दखलंदाज़ी के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है जनता द्वारा और जनता के लिए चुने गए जनप्रतिनिधि सरकारी कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कुछ कांग्रेसी नेता सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने और लाभार्थियों को राशन कार्ड बाँटने के लिए चर्चा का विषय बन गए हैं मंचेरियाल जिला मुख्यालय स्थित अल्पसंख्यक समारोह हॉल में आयोजित नए राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने राशन कार्ड वितरित किए किसी भी प्रोटोकॉल पद पर न होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष तुमुला नरेश, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुधारी तिरुपति, मंचेरियल नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सल्ला महेश, कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद बनेश और पुधारी प्रभाकर आदि द्वारा राशन कार्ड वितरित करना विवादास्पद हो गया है ।

जिन अधिकारियों को इसे रोकने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी वे अनुपस्थित थे और कांग्रेस नेता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जिससे काफ़ी हंगामा हुआ हालाँकि यह सर्वविदित है कि यह नियमों के विरुद्ध है मंचेरियाल तहसीलदार की भी आलोचना हो रही है क्योंकि उन्होंने राशन कार्ड बाँटने में उनका साथ दिया और मूकदर्शक की भूमिका निभाई पहले भी जब चावल बाँटे गए थे तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लाभार्थियों को चावल दिया था उस समय किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी विपक्षी दल के नेता और स्थानीय लोग इस बात से नाराज़ हैं कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कांग्रेस नेताओं ने इंदिराम्मा आवास का निरीक्षण किया

मदनूर, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। मदनूर मंडल छोटा शक्करगा गांव के कांग्रेस नेता दिगंबर ,पांडुरंग पाटील व शेख फरीज ने गांव में इंदिराम्मा आवास योजना के मकान का निरक्षण करते हुए बताए कि प्रदेश की रेवंत रेड्डी सरकार ने गरीब जनता को आवास का सपना पूरा करने के लिए इंदिराम्मा आवास योजना अमल में लाने पर स्थानिक विधायक लक्ष्मी कांताराव ने जुक्कल बिस क्षेत्र के लिय बड़ी मात्रा में इन्द्रम्मा आवास की मंजूरी दिलाई मदनूर मंडल छोटा शक्करगा गांव के लाभार्थी इस योजना का लाभ लेते हुए।

अपना आवास निर्माण कर रहे आज इनका का मकान लेंटल लेवल आया है। छोटा शक्कर गांव में इन्द्रम्मा आवास योजना का कार्य प्रगति पथ पर चल रहा है बाकी के लाभार्थी इन्द्रम्मा आवास निर्माण कार्य के लिय तयार है ।

उप जिला अधिकारी ने कस्तूरबाग गांधी पाठशाला का निरीक्षण किया

मदनूर, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। बांसवाड़ा की उपजिलाधिकारी किरणमयी ने शुक्रवार को मदनूर मंडल केंद्र स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया।

उन्होंने विद्यालय की रसोई और सब्जी भंडार का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की छात्राओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि वे छात्राओं को हर रोज मेनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएँ। मंडल विकास अधिकारी रानी ने उपजिलाधिकारी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय निरीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

वन विभाग अधिकारियों ने हथियार और वन पुलिस स्टेशन की मांग की

मंचेरियाल, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। वृक्षारोपण अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों पर हाल ही में हुए हमले और पथराव की घटना से चिंतित वन विभाग के अधिकारियों ने सरकार से आत्म-सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने और वन पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का आग्रह किया है। सरकार को सौंपे गए पत्रों में वन अधिकारियों ने आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति मांगी है तथा इकोडा मंडल के सिरीचेल्मा गांव में वन पुलिस स्टेशन की स्थापना की अपनी लंबे समय से लंबित मांग दोहराई है यह क्षेत्र अवैध लकड़ी तस्करी तथा कर्मियों पर हमलों के लिए जाना जाता है अधिकारियों ने बताया कि वन अधिकारियों को हथियार देने का प्रस्ताव कई वर्षों से लंबित है जबकि अतीत में तस्करों द्वारा वन रेंज अधिकारी स्तर के कर्मचारियों की हत्या सहित हिंसा की घटनाएं बार-बार होती रही हैं सागौन तस्करों का ख़तरा बढ़ रहा है इकोडा जैसे वन क्षेत्रों में गश्त करते समय उच्च अधिकारियों को हथियारों की ज़रूरत होती है उन्होंने बताया।सिरीचेल्मा में प्रस्तावित वन पुलिस स्टेशन का उद्देश्य वन बीट अधिकारियों जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की सुरक्षा करना होगा जो अक्सर अकेले जंगलों में गश्त करते हैं और हमलों का शिकार हो सकते है अगर इस स्टेशन को मंज़ूरी मिल जाती है तो इसमें दस सशस्त्र कर्मचारी होंगे और यह केरल असम और पश्चिम बंगाल में पहले से संचालित वन पुलिस स्टेशनों की तरह ही काम करेगा वन अधिकारियों ने बताया कि विभाग की सतर्कता एवं प्रवर्तन शाखा मामले की जाँच कर रही है वन विभाग कर्मचारी संघ ने भी सरकार को पत्र लिखकर बढ़ते खतरों के मद्देनजर तत्काल सुरक्षा उपाय करने की माँग की है जिले में वन एवं पुलिस कर्मियों के खिलाफ नियमित हिंसक घटनाओं का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कहा कि ये हमले मनोबल तोड़ने वाले हो गए है एक अधिकारी ने कहा सुरक्षा में सुधार से मनोबल बढ़ाने में मदद मिलेगी अन्यथा खराब सुरक्षा कर्मचारियों को असुरक्षित और जोखिम में डाल देगी वन अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि इकोडा में सागौन और रेत तस्कर तेजी से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं तथा कुछ राजनीतिक नेता उन्हें कानून-व्यवस्था को बाधित करने के लिए उकसा रहे है ।

गौरीगुंडला झरने को 6 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा : जयेश

मंचेरियाल, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। जिले में गौरीगुंडला (सब्बिथम) झरने को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 6 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दे दी गई है पर्यटन विभाग के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने इस आशय के आदेश जारी किए इस धनराशि का उपयोग उस स्थल पर बुनियादी ढाँचे और सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा, जहाँ मानसून के मौसम में भीड़ बढ़ती जा रही है स्थानीय विधायक सी. विजयरामन राव जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले इस स्थल के विकास का वादा किया था ने बाद में झरने का दौरा किया और अधिकारियों को परियोजना का अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए।12 करोड़ रुपये की एक विस्तृत योजना तैयार की गई, जिसमें से अब 6 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके है कुल स्वीकृत राशि में से 4.5 करोड़ रुपये के कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किए जाएंगे जबकि वन विभाग 1.5 करोड़ रुपये की राशि के कार्य निष्पादित करेगाप्रमुख कार्यों में सब्बीथम गाँव से झरने तक तीन किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण और आगंतुकों के लिए बैठने की जगह दर्शनीय स्थल शौचालय और साइनेज जैसी सुविधाओं का विकास शामिल है पिछली घटनाओं को देखते हुए जहाँ युवाओं ने घटनास्थल पर अपनी जान गंवाई थी सुरक्षा ढाँचे को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

नए राशन कार्ड का वितरण

मदनूर, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और जुक्कल विधायक लक्ष्मीकांतराव सर के निर्देशानुसार, आज एक छोटे शक्करगा गाँव में लाभार्थियों को नए राशन कार्ड वितरित किए गए। मदनूर मंडल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दरासवार साईं, मिर्जापुर हनुमान मंदिर के अध्यक्ष राम पटेल, वरिष्ठ नेता हनमनलू स्वामी, विठ्ठल गुरुजी, पूर्व सिंगल विंडो चेयरमैन अध्यक्ष कोंडा गंगाधर, पूर्व मंडल विकास अध्यक्ष प्रज्ञा कुमार, पूर्व कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष वटनालवार रमेश, बंडीवार गोपी, कांग्रेस पार्टी के नेता पांडु पटेल, दिगंबर, गाँव के लोग के साथ और अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

उप-कलेक्टर ने भू-भारती पट्टा वितरित

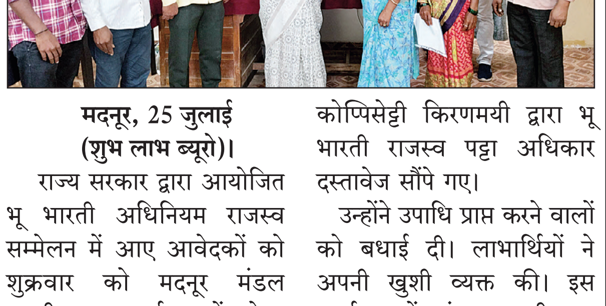

मदनूर, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। राज्य सरकार द्वारा आयोजित भू भारती अधिनियम राजस्व सम्मेलन में आए आवेदकों को शुक्रवार को मदनूर मंडल तहसीलदार कार्यालय में सोमूर गांव के हनुमंतवार शिवानंद और एबिटवार फूला लाभार्थियों को बांसवाड़ा उपजिलाधिकारी कोप्पिसेट्टी किरणमयी द्वारा भू भारती राजस्व पट्टा अधिकार दस्तावेज सौंपे गए।

उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वालों को बधाई दी। लाभार्थियों ने अपनी खुशी व्यक्त की। इस कार्यक्रम में मांडल तहसीलदार एम.डी. मुजीब, गिरदावर शंकर, कार्यालय कर्मचारी और अन्य लोग शामिल हुए।

इंटीग्रेटेड छात्रावास पाठशाला निर्माण के लिए तहसीलदार ने जमीन दी

मदनूर , 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)। जुक्कल विस क्षेत्र के विधायक थोटा लक्ष्मीकांत राव सर ने जुक्कल निर्वाचन क्षेत्र के मदनूर मंडल के मदनूर गांव में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल को मंजूरी दे दी है क्योंकि यह हम सभी को पता है, इसलिए इस शुभ अवसर पर आज मदनूर एमआरओ कार्यालय में एमआरओ मुजीब सर टीजीईडब्ल्यू आईडीसी कामारेड्डी की देखरेख में सर्वेक्षण संख्या 499 के साथ 20 एकड़ जमीन सौंपी गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष दरासवार साय लू, मिर्ज़ापुर हनुमान मंदिर के अध्यक्ष राम पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी नेता हनमनलू स्वामी और वटनालवार तहसीलदार मुजीप, राजस्व निरक्षक शंकर, के साथ अन्य लोग उपस्थित थे।

कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना में कराई गई जाति जनगणना की सराहना की

नई दिल्ली, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को राज्य में व्यापक और सार्थक जाति जनगणना कराने के लिए बधाई दी।

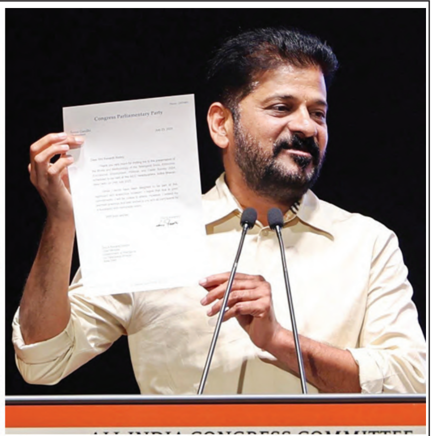

तेलंगाना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण 2024 के विवरण प्रस्तुत करने के अवसर पर इंदिरा भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए, खड़गे ने कहा कि तेलंगाना ने पूरे देश को एक नई दिशा दिखाई है। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा जाति जनगणना को साहसिक कदम बताया। खड़गे ने पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों से एकजुट होकर कांग्रेस का समर्थन करने का आह्वान किया, जिससे पार्टी को देशभर में 60-70 प्रतिशत समर्थन मिल सकता है।

उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, बल्कि 'जय बापू, जय भीम, जय संविधान' का नारा देकर लोगों में जोश भरा और संविधान की रक्षा का बीड़ा उठाया। इसका लाभ कांग्रेस को हाल के संसदीय चुनावों में मिला। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के दबाव के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को बधाई देते हुए कहा कि तेलंगाना में जाति जनगणना न केवल की गई, बल्कि इसे असाधारण रूप से अच्छी तरह और सही भावना के साथ अंजाम दिया गया। यह सामाजिक न्याय के लिए एक मील का पत्थर है और देशव्यापी जाति जनगणना के लिए मानक स्थापित करेगा, चाहे भाजपा इसे स्वीकार करे या नहीं। उन्होंने बताया कि यह सर्वेक्षण पारदर्शी तरीके से हुआ, जिसमें लाखों लोगों से पूछा गया कि वे कौन से प्रश्न चाहते हैं। अंत में 56 प्रश्न चुने गए, जो सत्ता में हिस्सेदारी, भेदभाव, संपत्ति, ज्ञान और शिक्षा जैसे पहलुओं को परिभाषित करते हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के पास अब 21वीं सदी का सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय डेटा है, जो विकास को लक्षित करने की शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने तेलंगाना के अगले कदम का भी जिक्र किया, जिसमें शिक्षा, सरकारी नौकरियों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा हटाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है, लेकिन भाजपा इसे पारित होने से रोक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश में सही तरीके से जाति जन-गणना नहीं करेगी, क्योंकि यह ओबीसी, दलित, आदिवासी और सामान्य जातियों की वास्तविक स्थिति को उजागर नहीं करना चाहती।

आंध्र सरकार का नई पेंशन मंजूरी पर महत्वपूर्ण फैसला

अमरावती, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।

आंध्र प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद पेंशन राशि को 4,000 रुपये तक बढ़ाया गया और इसे हर महीने की पहली तारीख को लाभार्थियों के घर पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि, कुछ समय से पात्र लाभार्थी नई पेंशन मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने शुरू में अपनी एक साल की शासन अवधि पूरी होने पर नई पेंशन वितरण की योजना बनाई थी। अब, मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने नई पेंशन वितरण को लेकर ताजा घोषणा की है।

पेंशन मंजूरी

मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने कहा कि यदि पेंशन प्राप्त करने वाले पति की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी को यथासंभव जल्दी पेंशन प्रदान करने की प्रक्रिया को उनकी सरकार लागू करेगी। उन्होंने बताया कि 1,09,155 लोग नई पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हुए हैं। अगस्त से इन सभी को विधवा पेंशन की श्रेणी में पेंशन मंजूरी के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार हर महीने 43.66 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी। मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि 2014-19 के दौरान टीडीपी सरकार के कार्यकाल में पेंशन पंजीकरण की प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती थी, और लाभार्थी सप्ताह के किसी भी दिन पेंशन के लिए आवेदन कर सकते थे।

वितरण प्रक्रिया

उस समय अधिकारी हर सप्ताह आवेदनों की जांच करते थे और महीने के अंत तक पेंशन सूची तैयार करते थे। सरकार ने पेंशन मंजूरी के समय अपात्र व्यक्तियों को हटाने का भी निर्णय लिया है। पहले, दिव्यांग श्रेणी में नकली सादरम प्रमाणपत्र बड़े पैमाने पर जारी किए गए थे, जिनमें प्रति प्रमाणपत्र 30,000 रुपये तक वसूले गए थे। गठबंधन सरकार ने नई पेंशन मंजूरी से पहले इनका पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विशेष चिकित्सा टीमें नियुक्त की गई हैं, जो इनकी जांच कर रही हैं। विधवा पेंशन के लिए आज से सभी वार्ड और ग्राम सचिवालयों में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। पात्र व्यक्तियों से आवेदन पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं, और सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।

अगले महीने से

इसके तहत अपात्र व्यक्तियों को सूचित करने के बाद, पात्र लाभार्थियों को वितरण शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस नए फैसले से सरकार पर हर महीने 35.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अगस्त महीने से नई पेंशन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

इस संबंध में मंत्रिमंडल की उप-समिति ने पहले ही बैठक की है और इस सप्ताह फिर से बैठक कर नई पेंशन मंजूरी के बारे में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। विभिन्न श्रेणियों के तहत लगभग 6 लाख आवेदन आने की उम्मीद है।

सीएम चंद्रबाबू ने 250 गरीब परिवारों को गोद लेने की घोषणा की

अमरावती, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने अपने विधानसभा क्षेत्र कुप्पम में 250 गरीब परिवारों को गोद लेने की घोषणा की है। शुक्रवार को सचिवालय में जीरो पॉवर्टी पी4 की समीक्षा के तहत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम चंद्रबाबू नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने ख -ा - चरी-रसरवरीळ कैप्शन के साथ पी4 लोगो का अनावरण किया।

इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अब तक आंध्र प्रदेश में राज्यव्यापी स्तर पर 5,74,811 गरीब परिवारों को गोद लिया जा चुका है। सीएम चंद्रबाबू ने इन परिवारों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया में पी4 के मार्गदर्शक के रूप में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्य भी भागीदार बने हैं। इस कॉन्फ्रेंस में विधायक, जिला कलेक्टर और निर्वाचन क्षेत्र के विशेष अधिकारी शामिल हुए।

डॉ.आर. गोपालकृष्णन ने संभाला सिकंदराबाद मंडल के डीआरएम का कार्यभार

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।

डॉ. आर. गोपालकृष्णन, 1998 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (आईआरटीएस) अधिकारी, ने 24 जुलाई 2025 को दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) का कार्यभार संभाला। इससे पहले वे सिकंदराबाद मंडल में अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

डॉ. गोपालकृष्णन ने आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक, दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एफएमएस) से एमबीए और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन (एसटीयूडी) से इंजीनियरिंग सिस्टम्स और डिजाइन में पीएचडी की है।

उनकी शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि तकनीकी विशेषज्ञता, रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता का उत्कृष्ट मिश्रण दर्शाती है।

अपने करियर के दौरान डॉ. गोपालकृष्णन ने कई अहम भूमिकाएँ निभाई हैं जिसमें- मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली में परिचालन और वाणिज्यिक कार्यों का सफल प्रबंधन। रेलवे बोर्ड में राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम लॉजिस्टिक्स का नेतृत्व।

भारतीय रेलवे के डेटा एनालिटिक्स यूनिट की स्थापना और पाँच वर्षों तक उसका नेतृत्व। उनके नेतृत्व में भारतीय रेलवे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा रणनीति तैयार की गई।

यात्री सेवाएँ, माल परिचालन, क्रू अनुकूलन, बुनियादी ढांचा योजना, सामग्री प्रबंधन और ट्रैक रखरखाव जैसे क्षेत्रों में कई नवाचार लागू किए गए। रेलवे संचालन में डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत किया गया।

डॉ. गोपालकृष्णन ने भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण (एनएचटीएस) तैयार किया, जो अब राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा लागू किया जा रहा है।

प्रशासनिक सेवाओं के अलावा डॉ. गोपालकृष्णन एक प्रतिष्ठित शोधकर्ता और अकादमिक भी हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में डॉक्टरेट स्तर पर परिवहन मांग मॉडलिंग पढ़ाया है।

सिंगापुर-एमआईटी स्कॉलर के रूप में उन्होंने एमआईटी-यूएसए के इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स लैब और सिस्टअप, आईआईएससी में शोध कार्य किया है।

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

विजयवाड़ा, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस.अब्दुल नजीर ने आज कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।'कारगिल विजय दिवस' के अवसर पर, राज्यपाल ने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि 1999 का कारगिल युद्ध भारतीय सशस्त्र बलों के अटूट साहस, दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों में अडिग संकल्प का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है।

उन्होंने कहा, इन सैनिकों का साहस, वीरता और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

तेलंगाना कैबिनेट की बैठक 28 को

हैदराबाद, 25 जुलाई (शुभ लाभ ब्यूरो)।

तेलंगाना राज्य कैबिनेट की बैठक, जो मूल रूप से शुक्रवार दोपहर को होनी थी, को स्थगित कर दिया गया है। अब यह बैठक 28 जुलाई, सोमवार को दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक स्थगित करने का कारण औपचारिक रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन सभी संबंधित विभागों को नई तारीख की सूचना दे दी गई है। आगामी सत्र के दौरान, कैबिनेट के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत मामलों पर चर्चा करने की उम्मीद है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक गोपाल अग्रवाल द्वारा श्री शेषसाई इंटरप्राइजेज प्लॉट नंबर. 98/1, को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गांधी नगर, बालानगर के पास मेडचेल-मल्काजगिरि जिला. हैदराबाद 500037, तेलंगाना स्टेट से मुद्रित तथा प्लॉट नं. ए-23/5 तथा 6, दूसरा माला, ओपीआईई, बालानगर, हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना राज्य-500037 से प्रकाशित। आर. एन. आई रजिस्टर्ड नं. TELHIN/2019/78163, फोन नं. 040-29551811. E-mail : dailyshubhlabh@gmail.com.